

**एमएसएमई** : ग्रोथ फंड बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एलान

**एफएंडओ** पर एसटीटी 0.02 से 0.05 फीसदी की गई

**17 कैसर** की दवाएं व 7 दुर्लभ बीमारी की दवाएं होंगी सस्ती

**7,84,678.28** रक्षा

**2,77,830** रेलवे

**1,39,289.48** शिक्षा

**1,06,530.42** स्वास्थ्य

**2,55,233.53** गृह मंत्रालय सभी राशि करोड़ रुपये में

**नए संस्थान, हॉस्टल और यूनिवर्सिटी टाउनशिप**

**नौकरियां, कौशल और बेहतर अस्पताल को मिलेगा बढ़ावा**

**किसानों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें टैक सपोर्ट देगी सरकार**

**इस बार इनकम टैक्स स्लेब में कोई बदलाव नहीं**

**बैंकिंग और निवेश में सुधार पर फोकस**

# टैक्स वही, सोच नई

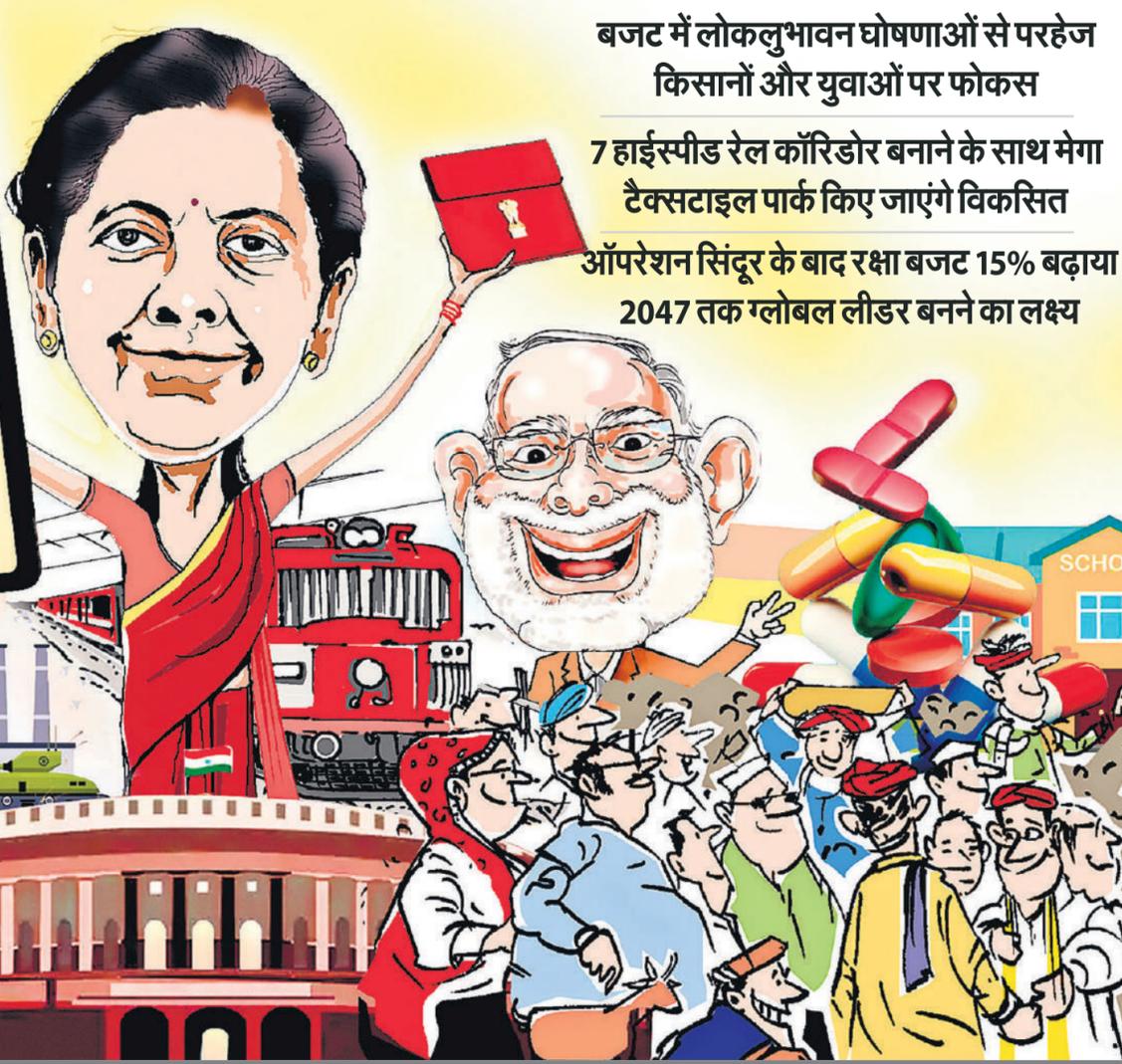
**53.5** लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्री ने किया पेश

**बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किसानों और युवाओं पर फोकस**

**7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने के साथ मेगा टैक्सटाइल पार्क किए जाएंगे विकसित**

**ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15% बढ़ाया 2047 तक ग्लोबल लीडर बनने का लक्ष्य**

**85** मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिखलाई भविष्य की झलक



## यह हुआ महंगा

- इनकम टैक्स में गलत जानकारी देना : टैक्स की रकम के 100% के बराबर पेनल्टी
- चल संपत्ति का खुलासा न करना : अब इस पर पेनल्टी लगगी
- स्टॉक ऑफ़ान और फ्यूचर्स ट्रेडिंग: सिक्वोरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया
- छत्ते और उनके पाटर्स पर 10 प्रतिशत या 25 रुपये प्रति किलो (जो भी ज्यादा हो) इयूटी लगगी
- शराब, मिनरल्स और स्क्रेप की बिक्री पर टीसीएस अब 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2% की
- क्रैनबेरी पर इयूटी 5 प्रतिशत और ब्लूबेरी पर 10 प्रतिशत कर दी गई है
- पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड पर इयूटी अब शून्य से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दी गई है।
- चबाने वाला तंबाकू, जर्दा और गुटखा पर एनसीसीडी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 कर दिया

## सस्ती हुई चीजें

- माइक्रोवेव ओवन के खास पाटर्स पर अब बेसिक कर्टम इयूटी नहीं
- चमड़े के नियात में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास इन्पुट्स को इयूटी-फ्री आयात की सुविधा
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर कर्टम इयूटी माफ
- सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर कर्टम इयूटी हटी
- न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आयात किए जाने वाले सामान पर 2035 तक कर्टम इयूटी माफ
- एविएशन सेक्टर के पाटर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर कर्टम इयूटी माफ
- विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस की दर 5-20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर की गई
- विदेश में पढ़ाई के खर्च पर एलआरएस के तहत अब कम टीडीएस लगगी।
- एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े उपकरणों पर बेसिक कर्टम इयूटी माफ
- प्रोजेन टर्की मांस और खाने योग्य ऑफ़ल पर टैरिफ 30 से घटाकर 5 प्रतिशत
- ऑटोमोबाइल सिस्ट और कैसर की कुछ दवाओं पर टैरिफ 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित पांच प्रमुख राज्यों में चुनाव करीब होने के बाद भी उन्होंने लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज रखा। साथ ही सुधार एक्सप्रेस को जारी रखते हुए वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट और कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने संसद में कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। छोटे उद्यमों एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। अब तक के सर्वाधिक 12.22 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ इस बजट को बढ़ते वैश्विक जोखिमों के बीच वृद्धि को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा के रूप में देखा जा रहा है। सीतारमण ने छूट को युक्तिसंगत बनाकर सीमा शुल्क व्यवस्था को सरल बनाया है। इसके तहत 17 कैसर दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। बेजोख नियमों में ढील के साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

## छोटे उद्योगों के साथ कृषि, पर्यटन क्षेत्रों पर जोर

नई दिल्ली। निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए वैश्विक अनिश्चितता के बीच बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर को बनाए रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया जो पिछले वित्त वर्ष में 11.2 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि सरकार सात क्षेत्रों औषधि, समीकंडक्टर, दुर्लभ-खनिज चुंबक, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र और खेल सामग्री में विनिर्माण को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देगी। साथ ही, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास पर भी जोर दिया जाएगा। बजट में पशुधन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए भी कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई। वहीं भारत को जैव-औषधि विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। कपड़ा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्गों के विकास के साथ-साथ 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास का भी प्रस्ताव किया गया। लघु उद्यमों को बढ़ावा देने और भविष्य के 'चैपियन' तैयार करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एमएसएमई वृद्धि कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें चुनिंदा



मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करने की बात कही गयी है। बजट में घोषित उपाय पिछले वर्ष आयकर में छूट और जीएसटी कटौती के पूरक हैं। इन उपायों ने बुनियादी ढांचे पर खर्च, श्रम कानून में सुधार और

## वित्त मंत्री ने बताए 3 कर्तव्य

- सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सरकार का विकास रोडमैप सामने रखा। उन्होंने तीन मूल कर्तव्यों गिनाए।
- आर्थिक ग्रोथ** : सरकार का पहला कर्तव्य है भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज रखना। वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकार का लक्ष्य है कि वृद्धि दर को लगातार ऊंचा रखा जाए।
- जनता की उम्मीद** : दूसरा कर्तव्य है जनता की उम्मीदों और उनके भरोसे पर खरा उतरना। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, युवाओं के अवसर, महिला सशक्तिकरण और रोजगार ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार बजट के जरिए सीधे राहत देने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।
- सबका साथ, सबका विकास** : सरकार का तीसरा कर्तव्य है विकास को सबके लिए समान और सुलभ बनाना। सीतारमण ने कहा कि किसी भी नीति या योजना का उद्देश्य सभी पुरा होना है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे।

रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती के साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत के शुल्क का सामना करने में मदद की है।

## एसटीटी बढ़ोतरी से बाजार धराशायी, सेंसेक्स 1,547 अंक टूटा



मुंबई। वायदा सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने की केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद रविवार को धरेलु शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,547 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी 495 अंक टूटकर बंद हुआ। मार्केट में भारी बिकवाली के तबाव में निवेशकों के 9.40 लाख करोड़ रुपये ड्रव गए। विश्लेषकों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में सौदों पर एसटीटी को बढ़ाने का एलान बाजार को परसंद नहीं आया और यह बहुत तेजी से नीचे चला गया। बीएसई का 30 शेयर्स पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती बढ़त गंवाते हुए दोपहर के कारोबार में 2,370.36 अंक यानी 2.88 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 80,000 अंक के अहम रस्ते से भी नीचे फिसलकर 79,899.42 अंक पर खिसक गया था।

## सात साल में सबसे बड़ी गिरावट, वित्त मंत्री बोलीं- सड़हबाजी को रोकना है मकसद, निवेशकों के 9.40 लाख करोड़ डूबे

हालांकि, बाद में सेंसेक्स थोड़े सुधार के साथ 1,546.84 अंक यानी 1.88 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,722.94 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 495.20 अंक यानी 1.96 प्रतिशत गिरकर 24,825.45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 748.9 अंक यानी 2.95 प्रतिशत लुढ़ककर 24,571.75 अंक के निचले स्तर तक चला गया। एचडीएफसी सिक्वोरिटीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) धीरज रेल्ली ने कहा, एसटीटी में प्रस्तावित बढ़ोतरी अल्पवधि में पूंजी बाजार से जुड़ी इकाइयों के लिए दबाव बना सकती है, हालांकि दीर्घवधि में इसके सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं।

## 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं वाला बजट

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है तथा विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है। मोदी ने कहा कि बजट में अवसरों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बजट में देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। सीतारमण ने लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश करते एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा की नींव है। इस वर्ष का बजट भारत की सुधार एक्सप्रेस को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। भारत केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं है और यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है।

## विकसित भारत के निर्माण का प्रेरणादायी संकल्प-पत्र

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह विकसित भारत के निर्माण का एक प्रेरणादायी संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा यह बजट युवाओं को अवसर, किसानों को सुरक्षा, उद्यमियों को प्रोत्साहन, मध्यम वर्ग को राहत और श्रमिकों को सम्मान प्रदान करेगा। योगी ने कहा यह बजट नवाचार, विनिर्माण और रोजगार को नई गति देने के साथ ही कृषि, ग्रामीण विकास, अवसंरचना, पर्यटन, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को संरक्षित बनाते हुए 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को साकार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एमएसएमई, स्टार्टअप और स्वदेशी उत्पादन को समर्थन देकर 'आत्मनिर्भर भारत' की नींव को और सुदृढ़ किया गया है।

## वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.3 प्रतिशत रहेगा जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 4.4 प्रतिशत से कम है। कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में राज्यों को कर हस्तान्तरण राशि के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये प्रदान करेगी जबकि शुद्ध कर प्राप्ति 28.7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा (सरकारी व्यय और आय के बीच का अंतर) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।



## शिक्षा और स्वास्थ्य

# 2 अमृत विचार

एक लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने और आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणाएं इस बार आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खास हैं। इसी के साथ भारत को चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में राज्यों को सहायता देने के लिए योजना शुरू करने की घोषणा भी देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को काफी भायी है।

# स्वस्थ भारत

• स्वास्थ्य मंत्रालय को 1,06,530 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

10%  
पिछली बार  
से ज्यादा

## निजी क्षेत्र की साझेदारी में बनेंगे पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 2026-27 के बजट में 1,06,530.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2025-26 के बजट के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने भारत को एक प्रमुख चिकित्सा पर्यटन गंतव्य के तौर पर बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनाने में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ये हब एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परिसर के तौर पर काम करेंगे, जिनमें चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय दूर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए, बजट आवंटन को 45 करोड़ रुपये से कुछ बढ़ाकर 51 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 350 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। स्वायत्त इकाइयों के लिए बजट आवंटन 2024-25 में 21,901.98 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 22,343.97 करोड़ रुपये हो गया है।

नई दिल्ली स्थित एम्स के लिए आवंटन 5,238.70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,500.92 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि आईसीएमआर के लिए 4,821.21 करोड़ रुपये बजट में शामिल किए गए हैं, जो लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि है।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन 37,100.07 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 39,390 करोड़ रुपये किया

530.42 करोड़ रुपये में से 1,01,709.21 करोड़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा 4,821.21 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए

आयुष्मान भारत का बजट 5.6% बढ़ा

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटन 8,995 करोड़ से बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।



## अगले पांच साल में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

नई दिल्ली। बजट में अगले पांच वर्षों में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम से देश के दवा उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 'बायोफार्मास्यूटिकल्स' या 'बायोलॉजिक्स' ऐसे जटिल औषधीय उत्पाद होते हैं, जिन्हें रासायनिक संश्लेषण के बजाय जीवों, कोशिकाओं या ऊतकों से तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री ने विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा समेत छह प्रमुख क्षेत्रों के लिए टोस पहल करने का प्रस्ताव रखा।



## दस क्षेत्रों में जोड़े जाएंगे एक लाख स्वास्थ्य पेशेवर

नई दिल्ली। अगले पांच सालों में ऑटोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और एलाइड साइकोलॉजी समेत अलग-अलग क्षेत्रों में करीब एक लाख सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों (एचपी) को जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि एचपी के लिए मौजूदा संस्थानों को उन्नत किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्र में नए एचपी संस्थान बनाए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के युवाओं के लिए कौशल वाले रोजगारों के नए रास्ते बनेंगे। इसमें ऑटोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, एलाइड साइकोलॉजी और व्यवहार संबंधी सेहत समेत 10 नए क्षेत्र शामिल होंगे।

# शिक्षित भारत

8.27% से  
ज्यादा वृद्धि

शिक्षा के क्षेत्र के लिए आम बजट 2026-27 में 1.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए 55,727 करोड़ रुपये शामिल

## प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टिक केंद्रों के पास देश में बनेंगी 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने में राज्यों को सहयोग देगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, 'इन प्रस्तावित शैक्षणिक क्षेत्रों में कई

विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे।

केंद्र सरकार ने बजट में शिक्षा को

प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखते हुए इस वर्ष 8.27 प्रतिशत से अधिक धनराशि का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में कुल 128650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। बजट में उच्च शिक्षा और खासतौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (एसटीईएम) को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने बजट में शिक्षा को

प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखते हुए इस वर्ष 8.27 प्रतिशत से अधिक धनराशि का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में कुल 128650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। बजट में उच्च शिक्षा और खासतौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (एसटीईएम) को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

## 15,000 स्कूलों, 500 कॉलेजों में स्थापित की जाएंगी 'एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब'

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल 'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज' के तत्वावधान में 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है।

सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक उभरता हुआ उद्योग है, जिसके लिए 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने



एवीजीसी क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये

का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा, मैं 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई को

सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। केंद्रीय बजट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 4,551.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसमें से एक बड़ी राशि भारत के सार्वजनिक प्रसारक 'प्रसार भारती' के साथ-साथ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभा विकास और सामुदायिक रेडियो के विस्तार को समर्थन देने के लिए निर्धारित की गई है। एवीजीसी क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके माध्यम से सरकार देश के युवाओं को कंटेंट क्रिएशन में अग्रणी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

नई दिल्ली, एजेंसी

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रविवार को पेश केंद्रीय बजट में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में शिक्षा के बजट को बढ़ाया गया है जो सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।

प्रधान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बजट में नवजात शिशु से लेकर युवा तक का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी, स्कूल शिक्षा, स्किलिंग, नर्चिंग इन्वैशन, इंटरप्रैन्वोरशिप और शोध इस बजट के बड़े संकेत हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने के लिए बजट में कई कल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में शिक्षा में बजट बढ़ाया गया है। पिछली बार की तुलना में इस बार बजट 8.27 प्रतिशत अधिक है



इस बजट में भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने की कल्पना

जो सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। प्रधान ने कहा कि भारत की लड़कियां विज्ञान, तकनीक और गणित की शिक्षा में दुनिया के अन्य देशों की तुलना

## अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान



नई दिल्ली। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और दवाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद आयुर्वेद को दुनिया भर में पहचान और मान्यता मिली। अखंड गुणवत्ता के आयुर्वेद उत्पाद जड़ी-बूटियों की पैदावार करने वाले किसानों और इनका प्रसंस्करण करने वाले युवाओं की मदद करते हैं।

वित्त मंत्री ने बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, प्रमाणन तंत्र के लिए आयुष फार्मसी और दवा जांच प्रयोगशालाओं को उच्च मानकों पर पहुंचाने और अधिक कुशल लोग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा, प्राचीन भारतीय योग, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही सम्मान है, को तब बढ़े पैमाने पर वैश्विक पहचान मिली जब प्रधानमंत्री इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद, आयुर्वेद को भी वैसी ही वैश्विक पहचान मिली। वित्त मंत्री ने जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र को उन्नत करने का भी प्रस्ताव रखा कि पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।

## निमहांस 2.0 के साथ रांची मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरेगा

रांची। अपने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जानी जाने वाली झारखंड की राजधानी रांची को इसका पहला निमहांस मिलने जा रहा है, जो उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रांची में दूसरे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस 2.0) की स्थापना की घोषणा की।



पहला निमहांस बंगलुरु में स्थित है। शहर के दो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक केंद्र द्वारा संचालित रांची तंत्रिका और मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान 100 से अधिक वर्षों से मनोरोग देखभाल, अनुसंधान और पुनर्वास के प्रमुख केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीआईपी अधिकारियों ने कहा कि वे संस्थान को निमहांस की तर्ज पर उन्नत करने की मांग कर रहे थे। इस संस्थान की स्थापना अग्रेजों ने 17 मई 1918 को रांची यूरोपियन लुनेटिक असाइलम के नाम से की थी। सीतारमण ने कहा, उत्तर भारत में कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है। इसलिए, हम निमहांस 2.0 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नत करेंगे।

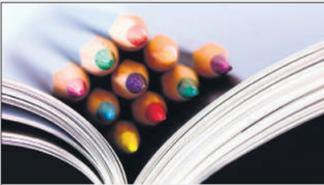
## हर जिले में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल 700 से ज्यादा जिले हैं पूरे देश में

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास (गर्ल्स हॉस्टल) स्थापित करने की घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं। सीतारमण ने पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं के लिए ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना का भी प्रस्ताव रखा। मंत्री ने आयुष औषधालयों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन तथा गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।



## शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता पर उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन

नई दिल्ली। देश को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सरकार 'शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता' पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री ने रविवार को बजट पेश करते हुए कहा, मैं 'शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता' पर एक उच्चस्तरीय स्थाई समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ, जो विकसित भारत के प्रमुख प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, ताकि वर्ष 2047 तक वैश्विक सेवाओं में हमारी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत हो सके। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करेगी। साथ ही, एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के रोजगार और कौशल आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर आवश्यक उपायों का सुझाव देगी।



## 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बजट, शिक्षा के प्रति दर्शाता है सरकार की प्राथमिकता को : प्रधान

में सर्वश्रेष्ठ है। सरकार इसमें और गति देने के लिए हर जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाए जाएंगे जिसमें शोध, नवाचार और ज्ञान का एक इकोसिस्टम बनेगा। अर्थ नीति को बढ़ाने के लिए उसे ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है। देश से बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों को पहले पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था उसे दो प्रतिशत किया गया जिससे छात्रों को देश के बाहर शोध करने के लिए जाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि बजट में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीआरटी) के बजट में चौदह प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

# 2.77 लाख करोड़ में रेलवे करेगा विकास

## नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन तथा कोच की खरीद के साथ-साथ होंगे कई अन्य कार्य

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजी व्यय के लिए रेल मंत्रालय को 2,77,830 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। बजट आवंटन में नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन तथा कोच की खरीद के साथ अन्य कार्य शामिल हैं। मंत्रालय को वित्त वर्ष 2025-26 में 2,52,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। आने वाले वित्त वर्ष के लिए यह आवंटन 10.25 प्रतिशत ज्यादा है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इसके अलावा, मंत्रालय को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 15,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

बजट दस्तावेज के मुताबिक, रेलवे की कुल कमाई 3,85,733.33 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि खर्च 3,82,186.01 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिससे वित्त वर्ष के आखिर में 3,547.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि क्योंकि रेलवे की कमाई इतनी कम

- 2025-26 में 2.52 लाख करोड़ थे आवंटित वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 10.25% ज्यादा
- रेलवे की कमाई 3,85,733.33 करोड़ और खर्च 3,82,186.01 करोड़ होने का अनुमान

है कि वह परिस्पति बनाने और नए कामों का समर्थन नहीं कर सकती, इसलिए उसे सरकार से धन मिलता है। इसलिए, मंत्रालय को नई लाइन बिछाने, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने और सिंगल-लाइन वाले मार्गों पर डबल लाइन बनाने जैसे कार्यों के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बजट दस्तावेज में विभिन्न निर्माण कार्यों और संपत्ति निर्माण परियोजनाओं के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। इनमें नई लाइन के लिए 36,721.55 करोड़ रुपये, गेज परिवर्तन के लिए 4,600 करोड़ रुपये, लाइन दोहरीकरण के लिए 37,750 करोड़ रुपये, रोलिंग स्टॉक (लोकोमोटिव, वैगन आदि) के लिए 52,108.73 करोड़ रुपये, और सिग्नलिंग तथा दूरसंचार के लिए 7,500 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस दस्तावेज में 2024-25

## सात हाई-स्पीड, एक फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 के केंद्रीय बजट में अलग-अलग शहरों के बीच सात हाई-स्पीड कॉरिडोर और परिचम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सुरत के बीच एक नए विशेष फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि पर्यवरण अनुकूल यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक, ये प्रस्तावित गलियां मुंबई और पुणे, पुणे और हैदराबाद, हैदराबाद और बंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, चेन्नई और बंगलुरु, दिल्ली और वाराणसी तथा वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच विकसित किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि मालवहन के लिए पर्यवरण अनुकूल सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, वह पूर्वी क्षेत्र में डंकुनी को परिचमी हिस्से के सुरत से जोड़ने वाला एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रख रही हैं। अभी, अहमदाबाद और मुंबई के बीच एक हाई-स्पीड कॉरिडोर पर काम जारी है। इसी तरह, कई राज्यों और जिलों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर - ईस्टर्न और वेस्टर्न का काम जारी है।

में रेलवे की वास्तविक कमाई और खर्च का ब्यौरा भी दिया गया है। साल के दौरान, रेलवे ने 3,35,757.09 करोड़ रुपये कमाए और 3,32,440.64 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे 3,316.45 करोड़ रुपये की आय हुई। उस साल के लिए, बजट में 2,51,946.56 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

एक अधिकारी ने कहा कि जहां तक वित्त वर्ष 2025-26 की बात है, कमाई और खर्च

के असल आंकड़े वित्त वर्ष खत्म होने के बाद ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकतर कमाई और खर्च मामूली बदलावों के साथ उम्मीद के मुताबिक ही हैं। रेलवे के कुल खर्च में से सबसे बड़ा हिस्सा उसके कर्मचारियों को पेंशन देने में जाता है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, 2024-25 में पेंशन पर खर्च 58,844.07 करोड़ रुपये था, जिसके 2026-27 में बढ़कर 74,500 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

# राजकोषीय घाटे की भरपाई को 17.2 लाख करोड़ का कर्ज लेगी सरकार

सरकार अगले वित्त वर्ष में 4.3% के अनुमानित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए कुल 17.2 लाख करोड़ रुपये उधार ले सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 14.80 लाख करोड़ रुपये के सकल कर्ज का अनुमान लगाया था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचत और अन्य स्रोतों से किये जाने की उम्मीद है। सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। कर्ज की राशि अधिक होने के प्रश्न पर, आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि शुद्ध बाजार उधारी 11.73 लाख करोड़ रुपये के आसपास है, जो कुछ वर्षों के आंकड़ों के करीब है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी संख्या इसलिए है क्योंकि हम इस साल 5.5 लाख करोड़ रुपये चुकाने हैं। इसलिए, उस लिहाज से हमें यह कोई बड़ी संख्या नहीं लगती। ठाकुर ने कहा कि प्रतिभूति पुनर्विचार और अदला-बदली का मुख्य उद्देश्य सरकार पर ऋण चुकाने का बोझ कम करना, एक साथ कई ऋण के जमा होने के प्रभाव को कम करना और लागत को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि हमने इस साल उच्च ब्याज वाली प्रतिभूतियों की महत्वपूर्ण अदला-बदली की है। अगले साल इस 5.5 लाख करोड़ रुपये को चुकाना होगा। जैसे-जैसे ये प्रतिभूतियाँ आती रहेंगी, हम निर्णय लेते रहेंगे। बजट के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीतारमण ने कहा कि केंद्र राज्यों से उनके राजकोषीय प्रबंधन के बारे में बात कर रहा है और उनके ऋणों पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र अनुच्छेद 293 (3) के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य है कि राज्यों के कर्ज पर भी नजर रखी जाए। हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उनके वित्तीय प्रबंधन अधिनियम से ऊपर जाने पर हम उस पर गौर कर सकते हैं।



## बजट में राजकोषीय मजबूती, पूंजीगत व्यय बढ़ने से वृद्धि को मिलेगा प्रोत्साहन

नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने बजट 2026-27 में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रशंसा की। कांत ने एक्स पर कहा कि सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को प्रभावी ढंग से घटाकर जीडीपी का 4.3 प्रतिशत किया है, जो 2020-21 के 9.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से एक बड़ी कमी है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन के वादे को सफलतापूर्वक निभाने के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई! इस उपलब्धि ने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था में भरसे को मजबूत किया है, बल्कि निजी क्षेत्र को कर्ज लेने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण भी तैयार किया है। कांत ने कहा कि इस राजकोषीय मजबूती को पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ जोड़ा गया है, जिससे प्रभावी पूंजीगत व्यय अब जीडीपी का 4.4 प्रतिशत हो गया है।

# लड़ाकू दक्षता बढ़ाने के लिए सेना को मिले 7.85 लाख करोड़

## रक्षा बजट में 15 प्रतिशत का इजाफा, पूंजीगत व्यय में करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7,84,678 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो पिछले वर्ष के आवंटन 6.81 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। सरकार का ध्यान खासकर चीन और पाकिस्तान से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने पर है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के परिप्रेक्ष्य में पूंजीगत खरीद के बजट समेत रक्षा आवंटन में की गई यह वृद्धि हमारी सेना को और अधिक मजबूत बनाने के संकल्प को प्रबल बनाएगी। कुल आवंटन में से 2,19,306 करोड़ रुपये सशस्त्र बलों के पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए, जिसमें



मुख्य रूप से नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदना शामिल है। यह पूंजीगत व्यय 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में 21.84 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय के तहत, 63,733 करोड़ रुपये विमान और एयरो इंजन के लिए और 25,023 करोड़ रुपये नौसेना बेड़े के लिए आवंटित किए गए हैं। कुल पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान 1.80 लाख करोड़ रुपये से 39,000 करोड़ रुपये अधिक है। 2025-26 का संशोधित पूंजीगत

1.85 लाख करोड़ में सेनाओं के आधुनिकीकरण का प्रावधान

1.71 लाख करोड़ रुपये पेंशन के लिए व्यय करने का प्रावधान

17,250 करोड़ अनुसंधान व विकास पर होगा खर्च

12,100 करोड़ भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना के लिए

## खरीदे जाएंगे 114 राफेल

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश किए गए बजट में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की रक्षा तैयारियों को आगे बढ़ाने और सेनाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। बजट में वायु सेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मद्देनजर पूंजीगत बजट में अरबी खसरी बढ़ोतरी की गयी है जो 2.19 लाख करोड़ रुपये है। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक है। पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ दिए गए हैं जबकि पिछली बार 1.60 लाख करोड़ रुपये था। अनुसंधान और विकास के लिए भी 17250 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो पिछली बार 14923 करोड़ रुपये था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आए बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए निर्धारित किए गए, जिसमें

# एफएंडओ में एसटीटी वृद्धि से रोकेंगे सट्टेबाजी

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने का मकसद उच्च जोखिम वाली सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन भोले-भाले निवेशकों को हतोत्साहित करने के लिए किया गया, जो डेरिवेटिव बाजार में बड़ी मात्रा में पैसा गंवा रहे थे। बजट में वायदा अनुबंधों पर एसटीटी को 0.02 से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, विकल्प सौदों पर एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है। अब तक एसटीटी विकल्प प्रीमियम पर 0.1% और विकल्प कारोबार पर 0.125% था।

बजट के बाद सीतारमण ने कहा कि सरकार वायदा-विकल्प कारोबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि भारी नुकसान का सामना कर रहे छोटे निवेशक सट्टेबाजी वाले एफएंडओ बाजार से दूर रहें। सीतारमण ने कहा कि यह मामूली वृद्धि पूरी तरह से सट्टेबाजी को लक्षित है। इसलिए, एफएंडओ पर एसटीटी में यह वृद्धि ऐसे निवेश को रोकने के लिए है। सबी के अध्ययनों के अनुसार, एफएंडओ खंड में 90% से अधिक खुदरा निवेशकों को नुकसान होता है। बाजार नियामक ने इस खंड में कारोबार कम करने के लिए पहले भी कम कदम उठाए हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अत्यधिक सट्टेबाजी की गतिविधियों को हतोत्साहित करने और अधिक संतुलित बाजार संरचना को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। हालांकि, कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि यह निकट अविधि में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की भागीदारी को प्रभावित कर सकता है।

## 12.22 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय जीडीपी का 4.4%

सीतारमण ने कहा कि 2026-27 के लिए घोषित 12.22 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4% है और अब तक का सर्वाधिक है। वित्त वर्ष 2026-27 का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2025-26 में घोषित 11.11 लाख करोड़ के बजटीय पूंजीगत व्यय से 10% अधिक है। उन्होंने कहा कि हमने घोषणा की है कि 12.22 लाख करोड़ का सार्वजनिक व्यय किया जाएगा। इस बार यह जीडीपी का 4.4% है। यह कम से कम पिछले 10 वर्षों

में सबसे अधिक है और यदि आप पिछली अवधि के आंकड़ों को भी देखें तो यह संभवतः सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.5% और 2024-25 में 4.0% था। वित्त वर्ष 2015-16 में सरकार का पूंजीगत व्यय 2.35 लाख करोड़ रुपये था। सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.3% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य यथार्थ है।

## सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने को एसटीटी बढ़ाया : राजस्व सचिव

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि एफएंडओ खंड में एसटीटी बढ़ाने का मकसद सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना और प्रणालीगत जोखिम को संभालना है। एफएंडओ में सट्टेबाजी से छोटे और खुदरा निवेशकों को नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना है, और यही वजह है कि दर में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि यह मुख्य रूप से वायदा-विकल्प बाजारों में प्रणालीगत जोखिम को संभालने के लिए है। श्रीवास्तव ने कहा कि इस वृद्धि के बाद भी एसटीटी की दरें होने वाले लेनदेन की मात्रा की तुलना में मामूली रहेंगी।

## एसटीटी वृद्धि से पूंजी बाजार पर बढ़ेगा दबाव, विशेषज्ञों ने जताई चिंता



नई दिल्ली/मुंबई। केंद्रीय बजट 2026-27 में वायदा और विकल्प (एफएंडओ) खंड में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने पर विशेषज्ञों ने कहा कि यह कदम अल्पकालिक रूप से बाजार के लिए दबाव पैदा कर सकता है। एफडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक धीरज रेल्ली ने कहा कि एफएंडओ में एसटीटी वृद्धि अल्पकालिक रूप से पूंजी बाजार संस्थाओं के लिए दबाव डाल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह सकारात्मक हो सकती है। एसटीटी वृद्धि को बजट भाषण के बाद शेयर बाजार में आई तेज गिरावट का कारण बताया गया। कोटक सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी शीवाल शाह ने कहा कि एसटीटी में यह तेज वृद्धि

व्यापारियों, जोखिम प्रबंधकों के लिए लागत बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। इसका उद्देश्य आमदनी अधिकतम करने से अधिक लेन-देन की मात्रा को नियंत्रित करना प्रतीत होता है, क्योंकि संभावित आय लाभ को वायदा विकल्पों की कम मात्रा से संतुलित किया जा सकता है। घरेलू क्रॉकरेज फर्म सेमको सिक्योरिटीज ने कहा कि उच्च लेन-देन लागत से लेन-देन की मात्रा घटने, अल्पकालिक गति कमजोर होने और सक्रिय बाजार प्रतिभागियों के लिए लाभदायकता कम हो सकती है। कोटक भाषण के बाद शेयर बाजार में आई तेज गिरावट का कारण बताया गया। कोटक सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी शीवाल शाह ने कहा कि एसटीटी में यह तेज वृद्धि

(बायबैक) को पूंजीगत लाभ के रूप में मानने से एक साथैक क्षतिपूर्ति मिलती है और दीर्घकालिक निवेशक विश्वास मजबूत होता है। एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीषकुमार चौहान ने कहा कि बजट सट्टेबाजी पर रोक के लिए वायदा और विकल्प पर उच्च एसटीटी जैसे सुनिश्चित उपायों से वित्तीय बाजारों को सुदृढ़ बनाता है। आनंद राठी दीर्घ लिमिटेड के सीईओ फेरोज अजीज ने कहा कि एसटीटी में वृद्धि से डेरिवेटिव व्यापारियों के लेन-देन की लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी जिससे उनकी रणनीतियों पर प्रभाव पड़ेगा। यह बाजार में डेरिवेटिव लेन-देन की मात्रा कम कर सकता है और निकट भविष्य में अस्थिरता ला सकता है।

## 5000 करोड़ में सात सीईआर होंगे स्थापित

सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बंगलुरु, सुरत और वाराणसी सहित सात शहरी आर्थिक क्षेत्र (सीईआर) स्थापित किए हैं। इनके लिए पांच साल में प्रति क्षेत्र 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। सीतारमण ने शहरों को भारत के विकास, नवोन्मेष और अवसरों का इंजन बनाने के लिए कहा कि यह नई पहल मझोली और छोटे शहरों (टियर दो और तीन) के साथ-साथ मंदिर नगरो पर केंद्रित होगी, जिन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। सरकार ने बजट में दो नई योजनाओं - शहरी आर्थिक क्षेत्रों और क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों के लिए 2,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव रखा है। यह आवंटन सात शहरी आर्थिक क्षेत्रों गंगवुड, भुवनेश्वर-पुरी-कटक त्रिपक्षीय क्षेत्र, कोयंबटूर-इरोड-तिरुपुुर, पुणे, सुरत, वाराणसी और विशाखापत्तनम के लिए प्रस्तावित किया गया है।

## विधि मंत्रालय को ईपीआई के लिए मिले 250 करोड़

मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बीच बजट में विधि मंत्रालय को मतदाता पहचान पत्रों के लिए 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव से संबंधित खर्चों के लिए 500 करोड़ अलग से दिए गए हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्रों (ईपीआईसी) पर होने वाला खर्च केंद्र और राज्यों के बीच बराबर बांटा जाता है। प्रत्येक राज्य मतदाताओं की संख्या के अनुपात में राशि का भुगतान करता है। भारत में मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 99 करोड़ है। निर्वाचन आयोग, चुनाव कानूनों, संबंधित नियमों और निर्वाचन आयोग की नियुक्तियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाले विधि मंत्रालय को 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के लिए 500 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं।

## ई-अदालत परियोजना को मिला 1,200 करोड़

सभी अधीनस्थ अदालतों के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से विधि मंत्रालय की ई-अदालत परियोजना के तृतीय चरण के लिए केंद्रीय बजट में 1,200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना को अनुमान के 1,500 करोड़ के मुकाबले 1,200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सितंबर 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ के वित्तीय व्यय के साथ केंद्रीय योजना के रूप में परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी थी, जिसे चार साल में लागू किया जाना है। राष्ट्रीय ई-गवर्नंस योजना के तहत भारतीय न्यायपालिका को सुचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में सक्षम बनाने के लिए 2007 से ई-अदालत परियोजना क्रियान्वरण में है। परियोजना का दूसरा चरण 2023 में खत्म हुआ।

## मौजूदा कीमतों पर 10% वृद्धि का अनुमान यथार्थपूर्ण

## वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2026-27 के लिए जीडीपी में मौजूदा कीमतों पर 10% की वृद्धि का अनुमान यथार्थपूर्ण है। बजट दस्तावेज के अनुसार, भारत की जीडीपी का वित्त वर्ष 2025-26 में 393 लाख करोड़ आका गया है। वित्त मंत्री ने कहा, भारत में मुद्रास्फीति कम है और कुछ समय तक इसी स्तर पर बनी रहेगी। मुद्रास्फीति अकेला मूल्य संशोधन कारक नहीं है, लेकिन काफी हद तक आप इसी पर निर्भर करते हैं। इसलिए मौजूदा कीमतों पर जीडीपी का अनुमान यथार्थपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह 10% वृद्धि का अनुमान जीडीपी के मौजूदा आधार वर्ष और उपयोग की गई गणना पद्धति पर ही तय किया गया है। सरकार फरवरी में कई वृद्ध-आर्थिक संकेतकों, जैसे जीडीपी और खुदरा मुद्रास्फीति की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने जा रही है।

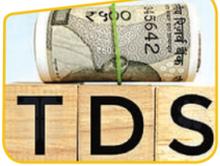




## आयकर में नहीं मिली राहत स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले जैसा

अमृत विचार, बजट डेस्क

केंद्रीय बजट में आमजन की टैक्स से जुड़ी उम्मीदों के मुताबिक, कोई ऐलान नहीं हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। लोगों को आशा थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया था। इसके मुताबिक 12 लाख रुपये सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना था। यही सीमा अब 2026-27 में भी लागू रहेगी। इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी पूर्व की भांति 75 हजार ही रहेगा। ऐसे में मिडिल क्लास के हाथ खाली रह गए।



## टैक्स में कुछ इन छूट का भी ऐलान

वित्त मंत्री की बजट घोषणा के अनुसार अब किसी मोटर एक्सीडेंट वलेम के तहत तय ब्याज को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। इस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। लेबर सर्विस को टीडीएस के तहत लाने का प्रस्ताव किया गया है और इन सेवाओं पर 1 से 2 फीसदी की टीडीएस कटौती हो सकती है।



## छोटे करदाताओं को राहत

वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है। अब आईटीआर फाइल करने पर कम या जीरो टैक्स कटौती सर्टिफिकेट ले सकेंगे। इसके अलावा, अलग-अलग कंपनियों के शेयर रखने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए डिपॉजिट, निवेशक के फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच स्वीकार करने और इसे सीधे उन कंपनियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।

## विदेश में घूमना, इलाज और पढ़ाई अब पहले से सस्ती

सरकार ने विदेश घूमने वालों के लिए बड़ी राहत दी है। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले टीसीएस जो पहले 5-20 फीसदी लगता था, को घटाकर सिर्फ 2 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह विदेश में मेडिकल और पढ़ाई पर होने वाले खर्च को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने टीसीएस के तहत खर्च पर ब्याज दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया है, यानी आप विदेश में अपना पैसा खर्च करते हैं तो कम ब्याज देना होगा। हालांकि, यह सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल खर्च के लिए ही मान्य होगा। इससे विदेश में पढ़ाई और इलाज अब सस्ता हो जाएगा।



## आईटीआर के लिए नई डेडलाइन

अब आईटीआर-1 और 2 को भरने के लिए डेडलाइन 31 जुलाई है। नॉन-ऑडिटेड बिजनेस को आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 अगस्त तय की गई है। वहीं इनआरआई के लिए टैन की जरूरत अब समाप्त कर दी गई है। अब अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने पर निवासी खरीदार के पैर पर चालान के जरिए टीडीएस जमा किया जा सकता है।



## एक अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि आयकर अधिनियम 2025 को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा। यह छह दशक पुराने आयकर कानून का स्थान लेगा। आयकर अधिनियम-2025 के नियम तथा 'टैक्स रिटर्न' फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे, ताकि करदाताओं को इसकी आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

## 63,500- करोड़ रुपये बजट में किसान सम्मान निधि के लिए जारी किए गए हैं। पिछली बार भी इस योजना के लिए इतनी ही धनराशि का आवंटन किया गया था। इस तरह 6000 रुपये सालाना की किसान सम्मान निधि योजना जारी रहेगी।

### वित्त मंत्री ने बजट में किया स्मार्ट फार्मिंग एआई टूल 'भारत विस्तार' का ऐलान

# खेती में एआई क्रांति से किसान होंगे मालामाल

अमृत विचार, बजट डेस्क

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र के लिए 1,62,671 करोड़ का प्रस्ताव और किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें कृषि क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा एआई टूल 'भारत-विस्तार' (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज) को माना जा रहा है। यह एक बहुभाषी एआई टूल होगा जो एग्रीस्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संसाधनों को एआई प्रणाली से जोड़ेगा। इसका मकसद किसानों को उनकी अपनी भाषा में खास सलाह देना, खेती के जोखिमों को कम करना और पैदावार बढ़ाकर बेहतर फैसला लेने में मदद करना है। इससे किसान आसानी से अपनी आय में इजाफा कर सकेंगे। एग्रीस्टैक भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसे भारत सरकार ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए एक संपूर्ण डेटाबेस बनाना है जिसमें उनकी पहचान, भूमि रिकॉर्ड, आय, ऋण, फसल की जानकारी और बीमा इतिहास शामिल है। यह खेती से प्राप्त डेटा और सरकारी एपीआई से मिली जानकारी का उपयोग करता है। एग्रीस्टैक के अंतर्गत विभिन्न डिजिटल उपकरणों और सेवाओं को शामिल किया जाता है। 'भारत विस्तार' का ऐलान सबका साथ विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके अंतर्गत फसल चयन, मिट्टी स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान, बीज-खाद और कंटानाशक की सलाह के अलावा सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन तथा ट्रेकिंग जैसी सारी जानकारी एक ही इंटरफेस पर किसान को उसकी अपनी भाषा में मिलेगी। इस तरह यह प्लेटफॉर्म फसल की उत्पादकता बढ़ाएगा, किसानों के बेहतर निर्णय में मदद करेगा तथा कस्टमाइज्ड एडवाइजरी से जोखिम कम करेगा।

### यूनिकाइड सिस्टम और एआई चैटबॉट

भारत विस्तार एआई टूल किसानों के लिए एक बहुभाषी एआई आधारित सिस्टम है, जो मौसम, फसल स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन और बाजार कीमतों की सटीक जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान करेगा। इसके तहत किसानों को एआई चैट बॉट, यूनिकाइड सिस्टम और टैरिंटिंग की जानकारी दी जाएगी। कृषि साथी एआई चैटबॉट के जरिए किसान वॉयस चैटिंग कर सकेंगे और अपनी खेती संबंधित सवाल और समस्याओं के बारे में पूछ सकेंगे। इसमें वे वीडियो के जरिए भी समाधान हासिल कर सकेंगे।



### कोकोनट प्रोत्साहन योजना से एक करोड़ किसानों को लाभ

भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है। एक करोड़ किसानों सहित लगभग तीन करोड़ लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए नारियल पर निर्भर हैं। नारियल संवर्धन योजना के माध्यम से नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पुराने और कम पैदावार देने वाले पेड़ों को नए पौधों और किस्मों से बदलने का काम किया जाएगा।



### 20 हजार से अधिक पशु चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ेगी

पशुपालन ग्रामीण कृषि आय का करीब 16 प्रतिशत योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत किसानों की आमदनी भी शामिल है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री ने 20,000 से अधिक पशु-चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऋण-सम्बद्ध पूंजी सख्ति योजना पेश की है। यह योजना पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, निजी कॉलेज, डायग्नोस्टिक लैब और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देगी।



## पशुपालन क्षेत्र को मदद मिलने से बढ़ेगी किसान की आमदनी

→ **1,62,671** रुपये कृषि क्षेत्र के लिए कुल आवंटन

→ **7%** अधिक है यह राशि पिछले साल के बजट आवंटन से

पशुपालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट-लिंग्ड सॉल्विडी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। दुग्ध, पोल्टी और पशु व्यवसायों का आधुनिकीकरण होगा तथा वैल्यू चेन में किसान संगठनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार पशुधन उद्यमों का संवर्धन और आधुनिकीकरण करके डेयरी और मुर्गीपालन के लिए संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सुजन को संवर्धित करके और पशुधन कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन देगी। बजट में रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना तैयार करने की बात भी कही गयी। इससे रेशम किसानों, भेड़ पालक किसानों और जूट की खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

### 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास

मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। इससे अंतर्देशीय मत्स्य पालन मजबूत होगा, तटीय क्षेत्रों में वैल्यू चेन विकसित होगी और स्टार्टअप, महिला समूहों तथा फिश फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों के जरिए बाजार से जुड़ाव बढ़ेगा।



## उद्योग जगत

## इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के निर्माण को 40 हजार करोड़ तो कंटेनर के वैश्विक इकोसिस्टम के लिए 10 हजार करोड़ रुपये

# मैनुफैक्चरिंग और एमएसएमई बनेंगे विकसित भारत की राह में गेम चेंजर

नई दिल्ली, बजट डेस्क

केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत में मैनुफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाकर 'विकसित भारत' के लक्ष्य को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। सरकार ने 7 रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में मैनुफैक्चरिंग को गति देने का प्रस्ताव किया है। इसमें बायोफार्मा में अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 'बायोफार्मा शक्ति' योजना शुरू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण को योजना का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत उपकरणों और आईपी डिजाइन पर विशेष जोर दिया गया है। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और तकनीक के जरिए पुनर्जीवित किया जाएगा। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर (रेयर अर्थ कॉरिडोर) और 3 समर्पित

### एमएसएमई को 'चैंपियन' बनाने के लिए 10,000 करोड़ का कोष

नयी दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को 'चैंपियन' बनाने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपना रही है जिसमें 10,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष भी शामिल है। एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री ने इविटो समर्थन, नगदी समर्थन और पेशेवर समर्थन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इविटो समर्थन के तहत 10,000 करोड़ रुपये के एमएसएमई विकास कोष के माध्यम से चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- उन्होंने कहा कि एमएसएमई को तरलता समर्थन के लिए ट्रेडिंग मंच की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक उपकरणों (सीपीएसई) द्वारा सभी एमएसएमई खरीदारी को लेनदेन ट्रेडिंग मंच पर करना, सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी प्रदान करना और जॉर्डिंग को कारोबार के साथ जोड़कर वित्तपोषण को तेज और सरता बनाना शामिल है। इसके साथ ही सीतारमण ने 2021 में गठित 'आत्मनिर्भर भारत कोष' में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि डालने की घोषणा की ताकि सूक्ष्म उद्यमों को जोखिम पूंजी उपलब्ध रहे।

कैमिकल पार्क बनाए जाएंगे। एमईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) से घरेलू बाजार में बिक्री के लिए रियायती शुल्क की सुविधा। कंटेनर विनिर्माण का अगले 5 वर्षों में वैश्विक इकोसिस्टम बनाने के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। टेक्सटाइल क्षेत्र में प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर के लिए नेशनल फाइबर मिशन और में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है।

**'कॉरपोरेट मित्रों' का दस्ता एमएसएमई की करगा मदद:** सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता के लिए मझोले (श्रेणी-दो) और छोटे (श्रेणी-तीन) शहरों में 'कॉरपोरेट मित्रों' का एक दस्ता तैयार करेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों की स्थापना करने के लिए 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' स्थायी समिति का गठन करेगी। 'कॉरपोरेट मित्रों' का यह दस्ता एमएसएमई को किफायती लागत पर अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। सरकार इस दस्ता को तैयार करने के लिए आईसीएसआई, आईसीएसआई और आईसीएमआई जैसे संस्थानों को मांड्यूल पाठ्यक्रम और व्यावहारिक टूल डिजाइन करने में सहयोग देगा।

**200** पुराने औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे आधुनिक

### "भविष्य के लिए तैयार भारत" का बजट

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय बजट को "भविष्य के लिए तैयार भारत" का बजट बताया है। उनके मुताबिक इस बजट का मकसद निर्यात और घरेलू विनिर्माण को मजबूती देना है। बजट में मैनुफैक्चरिंग, सेवाएं, महिलाएं, शिक्षा, कौशल विकास, मछुआरे, पशुपालन और नई तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। गोयल ने कहा कि अब तक करीब 350 सुधार किए जा चुके हैं और लगातार नई पहलों के जरिए सुधार की रफ्तार तेज हो रही है। बजट में डेटा सेंटर को अभूतपूर्व लाभ देने और 2047 तक टैक्स छूट का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे भारत को एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक हब बनाने की दिशा में सरकार की मंशा साफ झलकती है।



### उद्योग जगत ने बताया दूरदर्शी और भरोसा बढ़ाने वाला बजट

नयी दिल्ली। केंद्रीय बजट को भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) ने दूरदर्शी और भरोसा बढ़ाने वाला बताया है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह बजट भारत की विकास यात्रा को स्थिर और मजबूत दिशा देता है। बजट में सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, रसायन, पुंजीगत वस्तुएं, वस्त्र, खेल सामग्री, महत्वपूर्ण खनिज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

### बजट कर अवकाश

नयी दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक 'कर अवकाश' का प्रस्ताव रखा, जो देश में स्थित डेटा सेंटर का उपयोग करके दुनिया भर के ग्राहकों को वलाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। यह कर अवकाश संबंधित संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन दिया जाएगा। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा, ' मैं किसी भी ऐसी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर अवकाश देने का प्रस्ताव करती हूँ, जो भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्वस्तरीय ग्राहकों को वलाउड सेवाएं प्रदान करती है। ' इस कर अवकाश का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को एक भारतीय पुनर्विक्रय इकाई के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देनी होंगी।

**भारत के डेटा सेंटर का उपयोग करने वाली विदेशी वलाउड कंपनियों को कर अवकाश का प्रस्ताव**

और डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा, ' मैं किसी भी ऐसी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर अवकाश देने का प्रस्ताव करती हूँ, जो भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्वस्तरीय ग्राहकों को वलाउड सेवाएं प्रदान करती है। ' इस कर अवकाश का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को एक भारतीय पुनर्विक्रय इकाई के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देनी होंगी।

# यूपी के विकास को मिलेगी रफ्तार, मिलेंगे 4 लाख करोड़ रुपये

● इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाई-स्पीड रेल, पर्यटन व सिटी इकोनॉमिक रीजन से टियर-2 व टियर-3 शहरों को मिलेगी मजबूती ● टेक्सटाइल व एआई आधारित कृषि पर फोकस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

बजट-2026

अमृत विचार: आम बजट से प्रदेश को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सौगात मिलने की उम्मीद है, जिससे विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर फोकस से सरकार उत्साहित है। हाई-स्पीड रेल, जल परिवहन और सिटी इकोनॉमिक रीजन से तत्वीर बदलने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को जमकर सराहा है। भाजपा जहां इसे ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। आम आदमी और नौकरीपेशा वर्ग को प्रत्यक्ष राहत कम नजर आई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय करों से उत्तर प्रदेश के हिस्से में 2.69 लाख करोड़ रुपये आएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में राज्य को कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये मिलने हैं। पूंजीगत निवेश (विकास कार्यों) के लिए राज्यों को ब्याजमुक्त ऋण योजना से 22 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में करीब 18 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान है। इसी प्रकार केंद्र सहायित योजनाओं के मद में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग ने केंद्रीय योजनाओं से भी 15 हजार करोड़



● भाजपा जहां बजट को ऐतिहासिक बता रही, वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है

रुपये से अधिक की धनराशि मिलने का अनुमान लगाया है। इन मदों से वर्ष 2026-27 में राज्य को करीब 4.18 करोड़ रुपये मिलेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इन मदों से राज्य को 3.92 करोड़ रुपये मिलने हैं। अब केंद्र से मिलने वाले इस धनराशि के आधार पर राज्य सरकार अपना बजट तैयार करेगी। बजट में किसान, महिला, युवा, कारीगर व छोटे उद्यमियों को केंद्र में रखते हुए समावेशी विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से पूर्वांचल, काशी क्षेत्र, बुंदेलखंड और टियर-2 व टियर-3 शहरों के लिए ये योजनाएं क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार, निवेश व आर्थिक गतिविधियों को गति

देने में अहम भूमिका निभाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी-सिलीगुड़ी और दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया, जिससे यूपी को कुल 1500 किमी हाई-स्पीड रेल मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सभी 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का विशेष बजट, नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क और तीर्थ स्थलों के विकास की घोषणा की गई। ये परियोजनाएं राज्य में कनेक्टिविटी, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देंगी। केंद्र सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। इससे दूर-दराज इलाकों से उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक रहने की व्यवस्था मिलेगी।

## बजट में यूपी को मिले प्रमुख तोहफे

- वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम
- बुंदेलखंड में होगा आईआईटी का निर्माण, पश्चिमी यूपी में खुलेगा एम्स
- सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना से टियर-2 व टियर-3 शहरों का कार्यालय
- 12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स से सड़क, रेल व लॉजिस्टिक्स को मजबूती
- खेल, एमएसएमई, खादी, हथकरघा व टेक्सटाइल सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन की घोषणा
- एआई आधारित 'भारत-विस्तार' से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक
- 'शी-मार्ट' से ग्रामीण महिलाओं को नया बाजार और उद्यमिता का अवसर
- सोलर, बैटरी व ई-मोबिलिटी को बढ़ावा, पीएम सूर्य घर योजना को गति
- हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल और जिला अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार
- 10,000 करोड़ का कंटेनर निर्माण विशेष बजट
- नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क, तीर्थ स्थलों का समग्र विकास

## इस धनराशि से तय होगा यूपी के आम बजट का आकार

- केंद्रीय करों से हिस्सा (2026-27) : 2.69 लाख करोड़ (2025-26 में 2.55 लाख करोड़)
- पूंजीगत निवेश के लिए ब्याजमुक्त ऋण : 22,000 करोड़ (चालू वर्ष में 18,000 करोड़)
- केंद्र सहायित योजनाएं : 1 लाख करोड़ से अधिक
- वित्त आयोग की सिफारिशों से : 10,000-12,000 करोड़
- केंद्रीय योजनाओं से अनुमानित राशि : 15,000 करोड़ से अधिक
- कुल अनुमानित केंद्रीय सहायता (2026-27) : लगभग 4.18 लाख करोड़
- (2025-26 में लगभग 3.92 लाख करोड़)

## आपात-स्थिति में सस्ता और प्रभावी इलाज

गरीबों व निम्न आयवर्ग के लोगों को आपात-स्थिति में सस्ता व प्रभावी इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में सभी जिला अस्पतालों को इमरजेंसी सुविधाएं बढ़ाने तथा ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे समय पर उपचार मिलने से जान बचाने की संभावनाएं बढ़ेंगी और जिला अस्पतालों की क्षमता में भी वृद्धि होगी। इन दोनों पहलों से यूपी में न केवल स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सहायक कर्मियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

# कनेक्टिविटी से लेकर रोजगार तक बदलेगा यूपी का परिदृश्य

अमृत विचार, लखनऊ : केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के लिए विकास का व्यापक खाका लेकर आया है। हाई-स्पीड रेल, जल परिवहन, सिटी इकोनॉमिक रीजन और 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्रदेश की कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही किसान, महिला, युवा, एमएसएमई, पर्यटन और टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष ध्यान देकर रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित करने की दिशा तय की गई है।



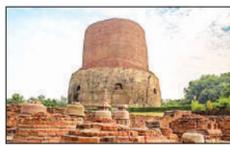
## हाई-स्पीड रेल से बदलेगी कनेक्टिविटी की तस्वीर

केंद्रीय बजट में घोषित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से 2 महत्वपूर्ण कॉरिडोर सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जिनमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राजधानी दिल्ली से काशी, पूर्वांचल और आगे पूर्वी भारत तक की रेलयात्रा तेज, सुरक्षित, सुविधाजनक तरीके से संपन्न होगी। आधुनिक तकनीक से लैस रेल नेटवर्क प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। हाई-स्पीड रेल से लंबी दूरी की यात्रा का समय काफी कम होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश व पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। काशी, पूर्वांचल व सीमावर्ती जिलों में उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।



## वाराणसी को मिलेगा जल परिवहन में नया आयाम

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जल परिवहन को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय बजट में वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह पहल गंगा नदी पर विकसित हो रहे जलमार्ग आधारित परिवहन तंत्र को तकनीकी व व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाएगी। शिप रिपेयर इकोसिस्टम के स्थापित होने से मालवाहक जहाजों और जलपोतों के रखरखाव व मरम्मत की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी, जिससे समय और लागत दोनों में कमी आएगी। इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलने के साथ जल परिवहन, एक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में प्रभावी होगा।



## पर्यटन व धार्मिक स्थलों को नई पहचान, संरक्षण को विशेष महत्व

केंद्रीय बजट में पर्यटन व सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। इसी क्रम में भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ तथा हस्तिनापुर को देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे न केवल यूपी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर नई मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। इससे धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। पर्यटकों की बढ़ती आवजाही से होटल, होम-स्टे, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और अन्य सहयोगी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।



## सिटी इकोनॉमिक रीजन से शहरों का होगा समग्र विकास

केंद्रीय बजट 2026-27 में टियर-2 और टियर-3 शहरों को विकास की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सिटी इकोनॉमिक रीजन (सीईआर) योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत बड़े महानगरों पर निर्भरता कम करते हुए पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले अन्य शहरों में बुनियादी ढांचे व आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी जैसे प्रमुख शहरों को इस योजना का सीधा लाभ मिल सकता है। आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए लगभग 5000 करोड़ तक का चरणबद्ध निवेश प्रस्तावित है।



## इन्फ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश की घोषणा मिलेगा सीधा लाभ

केंद्रीय बजट में देशभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) की घोषणा की गई है, जिसका सीधा व अप्रत्यक्ष लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। केंद्र सरकार के इस कैपेक्स का उद्देश्य आर्थिक विकास को रफ्तार देना, रोजगार सृजन करना और भारत को वैश्विक निवेश का आकर्षक केंद्र बनाना है। उत्तर प्रदेश में इस निवेश से सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक हब के विस्तार को नई गति मिलेगी। राज्य का पहले से मजबूत होता एक्सप्रेसवे नेटवर्क (पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा और लिंक एक्सप्रेसवे) औद्योगिक कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा।

## सोलर, बैटरी और ई-मोबिलिटी क्षेत्र में रियायत बनेगी गेम चेंजर

अमृत विचार, लखनऊ: केंद्रीय बजट 2026 में सोलर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और ई-मोबिलिटी से जुड़े कर कम झट्टी व आयात शुल्क में दी गई रियायतों को उत्तर प्रदेश के लिए गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। इन फैसलों को प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना और राज्य में तेजी से उभरते ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम से जोड़कर आका जा रहा है। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि बजट के ये प्रावधान स्फूर्ति से सोलर विस्तार, सोलर पैनल मैनुफैक्चरिंग, ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा

संतुलन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी- इन चारों क्षेत्रों को एक साझा दिशा में आगे बढ़ाएंगे। बजट 2026 में लिथियम-आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल- कोबाट पाउडर, बैटरी स्कैप और अन्य क्रिटिकल मिनेरल्स पर बैसिक कर कम झट्टी में छूट दी गई है। सोलर सेक्टर के लिए बजट में एक अहम प्रावधान करते हुए सोलर ग्लास निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल सोडियम एंटीमोनेट को कर कम झट्टी से छूट दी गई है। उद्योग जगत का मानना है कि इन रियायतों से डोमेस्टिक कंटेन

रिव्हायरमेंट (डीसीआर) आधारित सोलर पैनल मैनुफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। इन्फ्रस्ट्रक्चर से जुड़े कर कम झट्टी को प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। इसका असर उत्तर प्रदेश में सोलर बैट्टू चैन के विस्तार के रूप में सामने आ सकता है। बजट प्रावधानों के बाद नोएडा, लखनऊ, कानपुर और पूर्वांचल के औद्योगिक क्षेत्रों में नई सोलर मैनुफैक्चरिंग इकाइयों के साथ-साथ ईवी कंपोनेंट्स, बैटरी पैक असेंबली और वॉर्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश बढ़ने की संभावना है।

# एमएसएमई, खादी और वस्त्र क्षेत्र को मिलेगी गति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: केंद्रीय बजट 2026-27 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग को सशक्त बनाने के लिए कई अहम और दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। वस्त्र क्षेत्र को एक व्यापक, एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-कैश पहल और समर्थ 2.0 जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन और निर्यात को गति देना है। मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। इन प्रावधानों से प्रदेश के

- लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों के लिए नए अवसर
- एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम, ग्रोथ फंड और ग्रामीण उद्योगों पर फोकस

एमएसएमई, खादी, हथकरघा, रेशम और वस्त्रोद्योग से जुड़े लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। रोजगार बढ़ेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी। छोटे उद्यमों की कार्यशील पूंजी की समस्या कम करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्कॉन्टिंग सिस्टम के दायरे का विस्तार किया जाएगा।

## कॉरपोरेट मित्र और विरासत औद्योगिक क्लस्टर का प्रस्ताव

'कॉरपोरेट मित्र' व्यवस्था के जरिए एमएसएमई को व्यावसायिक मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और बाजार से जोड़ने की पहल की गई है। इसके साथ ही देशभर में 200 विरासत इंडस्ट्रियल क्लस्टरों के कार्यालय का प्रस्ताव है, जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टर भी शामिल होंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूते के ऊपर हिस्सों के शुल्क-मुक्त आयात का विस्तार और चमड़ा व वस्त्र परिधान निर्यात की समय-सीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं। इनसे वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान मिलेगी।

## किसानों, महिलाओं व युवाओं पर विशेष ध्यान

केंद्रीय बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारत-विस्तार योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इससे राज्य के अन्नदाता किसानों को मौसम, मिट्टी, फसल चक्र और बाजार की मांग के अनुरूप सटीक कृषि सलाह उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे फसल जोखिम कम होगा और राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि संभव होगी। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा, जो परंपरागत खेती पर निर्भर हैं। बजट में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शी-मार्ट्स की शुरुआत की गई है। कृषि-तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और उद्यमिता से जुड़े नए अवसर सृजित होंगे।

## स्वास्थ्य व शिक्षा में सशक्त कदम

केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण व दूर-दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इससे उच्च शिक्षा, मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास सुविधा मिल सकेगी। बजट में प्रस्तावित स्टैम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथ्स) संस्थानों से प्रदेश में पहले से जारी रिस्कल डेवलपमेंट अभियान को बढ़ावा मिलेगा।

## भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है बजट

अमृत विचार, लखनऊ : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय



बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जिन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प इसमें स्पष्ट रूप से झलकता है। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी दृष्टि, दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त घोषणापत्र है। राज्यपाल ने कहा कि करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, राजकोषीय अनुशासन, नियंत्रित घाटा और संतुलित कर्ज-जीडीपी अनुपात इस बात का प्रमाण है कि भारत की विकास यात्रा सुदृढ़ नींव पर आगे बढ़ रही है।

## बजट पर विभिन्न दलों के नेताओं का कहना...

### ऐतिहासिक बजट : केशव प्रसाद मौर्य

अमृत विचार : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। अपार अवसरों का राजमार्ग है। 2047 के विकसित भारत की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है।



### बजट में यूपी का रखा ध्यान : पाठक

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आम बजट में उत्तर प्रदेश का पूरा ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित हर क्षेत्र को बजट में समाहित किया गया है।

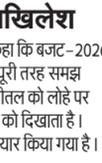
### विकसित भारत को लेकर जनोन्मुखी बजट: पंकज

अमृत विचार : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला जनोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। हाई-स्पीड रेल, आयुष्म, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, कृषि और एमएसएमई पर जोर से रोजगार, निवेश और कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।



### समझ से बाहर है बजट : अखिलेश

अमृत विचार : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बजट-2026 में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है और यह पूरी तरह समझ से बाहर है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो पीतल को लोहे पर चढ़ाकर गहने बनाने पड़ेंगे, यह बजट उसी सोच को दिखाता है। आरोप लगाया कि बजट कुछ बुनियादी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है।



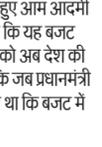
### मायावती ने बजट पर उठाए सवाल

अमृत विचार : केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बजट में कई योजनाओं, परियोजनाओं और आश्वासनों का जिक्र है, लेकिन इनके वास्तविक असर का आकलन जमीन पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, इन पर सही नीयत से अमल होना जरूरी है। सलाह देते हुए कहा कि बजट गरीब और बहुजन हितैषी होना चाहिए, न कि केवल पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों का पक्ष लेने वाला।



### बजट जवाब देने से भागने वाला : संजय

अमृत विचार : केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह विकसित भारत का बजट है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प में नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह बजट विशेष रूप से महिलाओं, नौजवानों, महिलाओं और शोषित वंचित उद्यमों के लिए समर्पित है और किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण बुनियादी को मजबूत करने का काम करेगा।



### आत्मनिर्भरता के संकल्प को ऊर्जा देगा बजट: अनिल

अमृत विचार : बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने कहा कि यह विकसित भारत का बजट है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प में नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह बजट विशेष रूप से महिलाओं, नौजवानों, महिलाओं और शोषित वंचित उद्यमों के लिए समर्पित है और किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण बुनियादी को मजबूत करने का काम करेगा।



विश्लेषण

बजट तात्कालिक वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए रचा गया वक्तव्य : प्रो. अजय द्विवेदी

# बजट संख्या नहीं संकेत : देश की आर्थिक चेतना का निर्णायक क्षण

अमृत विचार: भारत का आम बजट तब तक अधूरा रहता है, जब तक उसे केवल आय-व्यय के गणित की तरह पढ़ा जाता है। उसका वास्तविक अर्थ तब खुलता है, जब उसे समाज की मन-स्थिति, राष्ट्र की दिशा और सत्ता की मानसिकता के साथ जोड़कर देखा जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट एक ऐसे दस्तावेज के रूप में सामने आता है, जो शोर नहीं करता, संकेत देता है। यह बजट उत्सव का नहीं, निर्णय का बजट है। तात्कालिक वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरे उतरने के लिए रचा गया वक्तव्य। हर बजट अपने साथ अपेक्षाओं की एक लंबी कतार लेकर आता है। मध्यम वर्ग का रात की प्रतीक्षा करता है। किसान स्थिर आय और

सुरक्षा की उम्मीद करता है। युवा रोजगार के ठोस संकेत खोजते हैं। उद्योग नीति स्थिरता और निवेश अनुरूप वातावरण चाहता है। सामाजिक क्षेत्र अधिक संसाधनों की आकांक्षा रखता है। ऐसे में प्रश्न यह नहीं कि क्या यह बजट सबको खुश करता है, बल्कि यह है कि यह बजट किस दिशा में देश को ले जाना चाहता है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट भावनात्मक संतोष का साधन नहीं बनता। प्रत्यक्ष करों में बढ़े और आकर्षक बदलावों का अभाव पहली दृष्टि में निराशा पैदा कर सकता है। पर इसके भीतर छिपा संदेश अधिक गहरा है। सरकार यह संकेत देती है

कि अस्थिर अर्थव्यवस्था में दी गई त्वरित राहत अंततः उसी वर्ग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। महंगाई नियंत्रण, निवेश निरंतरता और वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता देना यह दर्शाता है कि मध्यम वर्ग को उपभोक्ता नहीं, बल्कि आर्थिक भागीदार के रूप में देखना चाहते हैं। यह दृष्टि लोकप्रिय नहीं, पर जिम्मेदार है। कृषि और ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह बजट करुणा से अधिक रणनीति की भाषा बोलता है। किसान को सहायता का पात्र नहीं, बल्कि आर्थिक संरचना का आधार मानने की सोच इस बजट को लोकलुभावन परंपरा से अलग करती

है। ग्रामीण रोजगार, कृषि अवसरचना और मूल्य संवर्धन पर निरंतर जोर यह स्पष्ट करता है कि सरकार जानती है कि गांव कमजोर हुआ तो शहर की प्रगति टिकाऊ नहीं रह सकती। यहां राहत बांटने से अधिक जड़ों को मजबूत करने का प्रयास दिखाई देता है। युवा वर्ग के लिए यह बजट सबसे अधिक बहस को जन्म देता है। सीधे रोजगार के बड़े वादे नहीं हैं, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं जिसे पोस्टर पर उकेरा जा सके। पर कौशल, तकनीक, स्टार्टअप और अवसरचना के माध्यम से अवसर निर्माण की जो संरचना प्रस्तुत की गई है, वह यह संकेत देती है कि सरकार नौकरी देने की नहीं, रोजगार अर्थव्यवस्था बनाने की सोच पर आगे बढ़ रही है। यह दृष्टि धैर्य मांगती है, पर दीर्घकाल में

आत्मनिर्भरता की ठोस जमीन तैयार करती है। उद्योग और व्यापार जगत के लिए यह बजट राहत की सांस जैसा है। करों में अप्रत्याशित झटकों का अभाव, नीति की निरंतरता और अवसरचना निवेश का स्पष्ट संकेत यह दर्शाता है कि सरकार उद्योग को संदेह की दृष्टि से नहीं, साझेदार के रूप में देखती है। यह बजट उद्योग से यह नहीं कहता कि सरकार सब कुछ करेगी, बल्कि यह भरोसा देता है कि रास्ता स्थिर और स्पष्ट रहेगा, चलना उद्योग को स्वयं होगा। सामाजिक क्षेत्र में यह बजट भावनात्मक घोषणाओं से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को नारों के रूप में नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही वह

सूक्ष्म अंतर है जो इस बजट को गंभीर बनाता है। यह स्वीकार किया गया है कि मानव संसाधन पर किया गया निवेश तत्काल राजनीतिक लाभ नहीं देता, पर दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण का यही आधार होता है। इस पूरे बजट की रीढ़ उसका वित्तीय अनुशासन है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने का संकल्प यह स्पष्ट करता है कि सरकार विकास की कीमत पर लापरवाही नहीं करना चाहती। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में यह संयम भारत को एक जिम्मेदार और परिपक्व अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। अवसरचना पर निरंतर निवेश के साथ यह अनुशासन यह दर्शाता है कि सरकार विकास को गति देना चाहती है, पर संतुलन खोकर नहीं।



प्रो. अजय द्विवेदी पूर्व डीन, रंधन संकलन वीर बहादुर सिंह बालीक विश्वविद्यालय, जौनपुर



## बजट प्रतिक्रिया

## वृद्धि, समावेशन का संयोजन वाला साहसिक बजट: सुनील मित्तल

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील मित्तल ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने और डेटा सेंटर परिवेश को प्रोत्साहन देने से भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा। मित्तल ने इसे विकास और समावेश को संयोजित करने वाला एक साहसिक बजट बताया और कहा कि कोशल विकास पर जोर के साथ विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान में लगातार निवेश समय पर किया गया कदम है, जो घरेलू क्षमताओं को मजबूत करेगा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात की जगह घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा। मित्तल ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के उपाय, ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना और डेटा सेंटर परिवेश को प्रोत्साहन देना, भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास को और मजबूत करेगा।

## यह बजट झुनझुना है दिखता है पर बजता नहीं: प्रमोद तिवारी

लखनऊ, एजेंसी। राजस्थान में उप नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद प्रमोद तिवारी तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा 'भोना' ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह 'झुनझुना' की तरह है, जो दिखता तो है लेकिन बजता नहीं। उन्होंने इसे किसान, बेरोजगार युवाओं और लघु एवं मध्यम उद्यमों के खिलाफ बताया हुआ कहा कि बजट से देश की जनता निराश हुई है। उनका दावा है कि बजट के बाद बाजार में गिरावट इसका संकेत है। नेता ने कहा कि पिछले एक वर्ष में पूंजी निवेश ठहरा हुआ है और न तो विदेशी निवेश आ रहा है और न ही स्वदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चालू वर्ष में राजस्व प्राप्ति में 78,086 करोड़ रुपये और शुद्ध कर संग्रह में 1,62,748 करोड़ रुपये की कमी आर्थिक सुस्ती का संकेत है। उनके अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास, नगर विकास, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं में बजटीय कटौती की गई है, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस नई योजना या अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है और यह बजट केवल नारी तक सीमित है।

## म्यूचुअल फंड आय से जुड़े ब्याज खर्चों पर कटौती खत्म करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी

सरकार ने रविवार को लाभांश और म्यूचुअल फंड आय से संबंधित ब्याज खर्चों पर मिलने वाले कटौती को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्रस्ताव से वह मौजूदा प्रावधान खत्म हो जाएगा, जिसके तहत लाभांश या म्यूचुअल फंड आय के 20 प्रतिशत तक के ब्याज खर्चों पर कटौती की अनुमति मिलती थी। आम बजट 2026-

## खेल विकास से सधेगी युवा शक्ति

युवा और खेल मंत्रालय के लिए बजट में 1,133 करोड़ की वृद्धि, खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत

नई दिल्ली, एजेंसी

यूनियन बजट 2026-27 भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मैनुफैक्चरिंग और रोजगार पैदा करने पर फोकस किया गया है।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेले इंडिया मिशन शुरू करने की घोषणा की, जिसका मकसद अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। डेवलपमेंट सेक्टर के तौर पर स्पोर्ट्स की बढ़ती अहमियत पर जोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, स्पोर्ट्स सेक्टर रोजगार, स्किलिंग और नौकरी के कई मौके देता है।

खेलो इंडिया प्रोग्राम के जरिए स्पोर्ट्स टैलेंट को सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाने की शुरुआत करते हुए, मैं अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। यूनियन बजट में, स्पोर्ट्स गुड्स मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने



के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। खेलो इंडिया मिशन पूरे देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बड़ा तरीका अपनाएगा। इस मिशन का मकसद एथलीटों के लिए सही रास्ते बनाना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत करना और सभी लेवल पर परफॉर्मस के नतीजों को बेहतर बनाना है। बजट में युवाओं पर केंद्रित नेचर पर जोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात पर जोर दिया

कि ये प्रस्ताव युवाओं को जोड़ने की कोशिशों से निकले आइडिया और उम्मीदों को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में, हमारे प्रधानमंत्री के साथ कई नए आइडिया शेयर किए गए, जिनसे कई प्रस्तावों को प्रेरणा मिली, जिससे यह एक अलोक्य युवा शक्ति पर आधारित बजट बन गया। ग्लोबल स्पोर्ट्स मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भारत की क्षमता को पहचानते हुए,

बजट में स्पोर्ट्स गुड्स मैनुफैक्चरिंग के लिए एक खास पहल का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा: केंद्रीय बजट 2026-27, युवा मामले और खेल मंत्रालय को कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ताकि 2036 तक भारत को टॉप 10 खेल देशों में और 2047 तक टॉप 5 में जगह दिलाने का विज्ञान पूरा हो सके। मंत्रालय के लिए आवंटन



वर्ष 2025-26 3,346 करोड़  
वर्ष 2026-27 4,479.88 करोड़

● 2036 तक भारत को टॉप 10 खेल देशों में और 2047 तक टॉप 5 में जगह दिलाने का विज्ञान  
● स्पोर्ट्स गुड्स मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये

2025-26 में 3,346 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 4,479.88 करोड़ रुपये हो गया है।

बढ़ा हुआ आवंटन केंद्र द्वारा चलाए जा रहे खेल और युवा विकास योजनाओं को लागू करने को मजबूत करेगा, जिसमें एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, युवा जुड़ाव की पहल, कॉचिंग और स्पोर्ट्स सिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस इंटीग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल हैं।

## भारत बनेगा एआई में सबसे बड़ा हब

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बजट पेश होने के बाद रेल भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हब के रूप में उभरने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने डिजिटल और तकनीकी विकास को बजट की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल बताया और कहा कि भारत को एआई-पारिस्थितिकी तंत्र आज पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित, निवेश-अनुकूल बन चुका है। श्री वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेमीकॉन 2.0 और सेमीकॉन 1.0 की सफलता के आधार पर आगे बढ़ रहा है, जो सेमीकंडक्टर के उपकरणों,



सामग्री का घेरलू विनिर्माण और डिजाइन और प्रतिभा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर फोकस करता है। उन्होंने मंत्रालय के तहत आईटी सेवाओं में बड़े सुधारों की भी घोषणा की। जिसमें टैक्स और लागू करने को आसान बनाना, और एआई डेटा सेंटर्स के लिए मजबूत समर्थन शामिल है-जिस 8.25 लाख करोड़ रुपये (90 बिलियन डॉलर) तक के निवेश और 2047 तक टैक्स हॉलिडे का सपोर्ट मिला है-जो भारत को वैश्विक एआई

हब के तौर पर स्थापित करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि एआई और तकनीक को लेकर बजट में मिले प्रोत्साहन से देश में एआई-संबंधित बुनियादी ढांचे, डेटा-सेंटर, जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) क्षमता और शोध को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत किसी अन्य देश की नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी रणनीति के साथ एक वास्तविक और व्यावहारिक एआई विकास मॉडल तैयार कर रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि एआई सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का अगला बड़ा इंजन है, और भारत की रणनीति इसे विश्व स्तर पर एक प्रमुख एआई हब के रूप में स्थापित करने की है। उन्होंने कहा कि सरकार एआई का उपयोग, स्किलिंग, रिसर्च और निवेश को समान रूप से बढ़ावा दे रही है ताकि देश को युवा, स्टार्टअप तथा उद्योग सभी इस तकनीक का लाभ उठा सके।

## पीएफ ट्रस्ट में नियोक्ता योगदान को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को भविष्य निधि या पीएफ ट्रस्ट के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया। इसके तहत नियोक्ता के योगदान पर समानता और प्रतिशत आधारित सीमाओं की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इस पहल का मकसद कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों में नियोक्ताओं के योगदान को सरल बनाकर कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है। इस समय कुछ ऐसे पीएफ ट्रस्ट हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति निधि संभालने वाली संस्था ईपीएफओ और आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त है। इन ट्रस्ट के नियोक्ता कुछ सीमाओं के तहत पीएफ खातों में अपने कर्मचारियों के योगदान की तुलना में कम या अधिक राशि का योगदान करते थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि परिवर्तनों का उद्देश्य कामकाज को आसान बनाना है।

## रियल एस्टेट और शहरी विकास को प्रोत्साहन

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय बजट पर राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने रविवार को कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह बजट उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। श्री जैन ने बजट में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सभी क्षेत्रों व सेक्टरों तक अवसरों की समान पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है, जो 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना को मजबूती देता है। श्री जैन ने शहरी संतुलित विकास



से परे संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर लोहिया वर्ल्डस्पेस के निदेशक पीयूष लोहिया ने कहा कि यह बजट आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्थिरता व दीर्घकालिक विकास का मजबूत आधार तैयार करता है। उन्होंने कहा कि सात हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर-मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगा और इनके आसपास नए रियल एस्टेट, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित होंगे। दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि यह बजट रियल एस्टेट सेक्टर के वाले शहरों पर विशेष फोकस से टियर-2 और टियर-3 शहरों में रियल एस्टेट गतिविधियों को नई गति मिलेगी और मेट्रो शहरों

● राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा

के लिए पूंजीगत व्यय को वित्त वर्ष 2026-27 में 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किए जाने के निर्णय को दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर विशेष फोकस से टियर-2 और टियर-3 शहरों में रियल एस्टेट गतिविधियों को नई गति मिलेगी और मेट्रो शहरों

● भारतीय कंपनियों में अब इक्विटी निवेश कर सकेंगे

उपयुक्त पहुंच के लिए एक ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान देना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात के जामनगर में स्थित विश्व स्वास्थ्य संवेदनशील पर्यटन मार्ग भी विकसित करेगी।

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

साथ ही देश की दूरबीन और खगोल विज्ञान अवसंरचना को भी उन्नत करने का प्रस्ताव है। बजट के मुताबिक, पर्यटन एवं कौशल विकास क्षेत्र में सरकार 20 प्रतिशत पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड के कौशल उन्नयन के लिए पायलट योजना शुरू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में पर्वतारोहण में विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने की क्षमता मौजूद है। इसके अलावा केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन मार्ग भी विकसित करेगी।

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

## आवास ऋण के ब्याज पर छूट में अब ब्याज भी शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के मामले में आवास ऋण के ब्याज पर मिलने वाली दो लाख रुपये तक की आयकर कटौती में अब संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण से पहले दिया गया ब्याज भी शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22 गूह संपत्ति से होने वाली धारा 22(2) में संशोधन करेगी। इससे एक अप्रैल 2026 से लागू नए



कर कानून के तहत गृह ऋण लेने वाले करदाताओं को राहत जारी रहेगी। बजट दस्तावेज के अनुसार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22 गूह संपत्ति से होने वाली धारा 22(2) में संशोधन करेगी। इससे एक अप्रैल 2026 से लागू नए

## विदेश में रहने वालों को निवेश की होगी अनुमति

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत व्यक्ति (पीआरओआई) अब पोर्टफोलियो निवेश योजना के जरिये सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी निवेश कर सकेंगे। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि पीआरओआई के लिए निवेश सीमा को भी अब पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कॉर्पोरेट बॉन्ड सूचकांक पर कोष एवं डेरिवेटिव्स तक

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन

● कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ

● एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हार्दसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उ

बजट-2026



**विशेषज्ञ बोले, डर आधारित कर-प्रणाली से विश्वास आधारित कर-संस्कृति की ओर बढ़ता कदम है आम बजट**

अयोध्या कार्यालय।  
अमृत विचार : केंद्रीय वित्तमंत्री द्वारा रविवार को आम बजट 2026 पेश किया गया। इसको लेकर सभी वर्ग के लोगों में खासी जिज्ञासा रही। बजट में क्या राहम मिली, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ आदि जानने के लिए लोग दिन भर टीवी से चिपके रहे। 'अमृत विचार' से बातचीत में लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हुए इसे संतुलित बजट बताया। 'डर आधारित कर-प्रणाली से विश्वास आधारित कर-संस्कृति की ओर बढ़ता कदम है आम बजट 2026। इसमें जहां आम जनता को सीधी राहत भले कम हो, लेकिन स्थिर अर्थव्यवस्था और बेहतर प्रशासन का लाभ दीर्घकाल में मिलेगा। पेश है बजट को लेकर प्रमुख लोगों की राय-

# आम जनता को स्थिरता, करदाताओं को भरोसा



सिविल लाइन स्थित एक शोरूम में बजट देखते लोग। अमृत विचार



एक मोबाइल शोरूम में टीवी पर बजट देखते युवा। अमृत विचार

**रिटर्न फाइलिंग नियम हुए सरल : अर्थशास्त्री**



वेतनभोगियों हेतु टेक्स स्लेब पूर्ववत होने के चलते थोड़ी हताशा देखने को मिल रही। किंतु रिटर्न फाइलिंग नियमों को सरल बनाने और टेक्स अनुपालन टीडीएस में राहत की घोषणा होना स्वागतयोग्य कदम है। केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के क्रम में आर्थिक संवृद्धि के महत्वपूर्ण पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए आधी आबादी के सम्मान व सुरक्षा में प्रत्येक जनपद में छात्राओं हेतु छात्रावास का प्रावधान काबिले तारीफ है। वर्ष 2047 को लक्ष्योन्मुख यह 2026-27 का बजट आर्थिक लक्ष्य और अनुमान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जिसमें उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत देने, निवेश के उपरांत क्षेत्रीय विकास करने पर फोकस किया गया है। - डॉ. अनुजेन्द्र तिवारी, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र।

**स्थिरता और भरोसे के रूप में दिखाई देता है बजट**



केंद्रीय बजट का असर आम जनता पर तात्कालिक राहत से अधिक स्थिरता और भरोसे के रूप में दिखाई देता है। सरकार ने बड़े लोकलुभावन वादों से बचते हुए कर-प्रशासन को सरल, पारदर्शी और मानवीय बनाने पर जोर दिया है। आयकर की दरों और स्लेब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसीलिये वेतनभोगी वर्ग को तुरंत बड़ी कर-राहत नहीं मिलेगी। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो एक अप्रैल 2026 से प्रभावी है, कानून की भाषा को सरल बनाता है। धाराओं की संख्या घटाता है और नए फॉर्मों के जरिए अनुपालन आसान करता है। इससे करदाता की भागवैड, डर और अनावश्यक विवाद कम होंगे। अब छोटी प्रक्रियात्मक गलतियों, तकनीकी चूक या कितानों के रखरखाव में कमी पर जेल का खतरा नहीं होगा, केवल जुर्माना लगेगा। अपील के लिए प्री-डिपॉजिट 20 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत किया गया है, जिससे आम करदाता को न्याय प्राप्त आसान होगा। - डॉ. मनीष अग्रवाल, चार्टर्ड एकाउंटेंट।

**ईमानदार करदाताओं को अनावश्यक दंड से राहत**



केंद्रीय बजट में आयकर कानून के तहत करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए अनुपालन को सरल और व्यावहारिक बनाने वाले कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। मोटर वाहन दुर्घटना में प्राप्त मुआवजे को कर-मुक्त किया गया है। विदेश यात्रा पैकेजों तथा शिक्षा व चिकित्सा प्रयोजनों हेतु विदेश भेजी जाने वाली राशि पर टीडीएस की दरों में कमी की गई है। मैनावापर सप्लाई को स्पष्ट रूप से धारा 194सी में शामिल कर टीडीएस से जुड़ा भ्रम दूर किया गया है। गैर-ऑडिट व्यवसायिक संस्थाओं व ट्रस्टों के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। विदेशी परिसंपत्तियों के खुलासे के लिए छह माह की विशेष योजना तथा पेनाल्टी व असेसमेंट प्रक्रिया के युक्तिकरण से ईमानदार करदाताओं को अनावश्यक दंड से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर, ये संशोधन कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, करदाता-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। - अनुज सिधल, अधिवक्ता (आयकर)

**विकसित भारत की दिशा में बढ़ाया गया मजबूत कदम**



बजट विकसित भारत की दिशा में बढ़ाया गया मजबूत कदम है। सरकार ने आम आदमी की जरूरत को ख्याल रखते हुए इस बार का बजट बनाया है। इसमें पढ़ाई और दवाई के साथ घूमने-फिरने पर ध्यान दिया गया। विदेश में पढ़ाई पर लगने वाले टेक्स को कम कर दिया गया है। जीवन रक्षक दवाओं जैसे कैन्सर और डायबिटीज के दाम में कमी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मोबाइल, टीवी इत्यादि पर टेक्स कम कर दिया है, जिससे एक आम आदमी की पहुंच में आ जायेंगे। किसानों के लिए भी सरकार ने काफी अच्छा किया है। हर जिले में छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने की योजना सराहनीय है। कुल मिलाकर यह बजट आम आदमी को आने वाले सपनों को पूरा करने के लिए उसका जीवन आसान बनाने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। कुल मिलाकर बजट संतुलित है, सुधार की आवश्यकता हमेशा रहती है और सरकार निरंतर सुधार करती रहेगी, ऐसी उम्मीद है। - प्रगति श्रीवास्तव, उप प्रधानाचार्या।

**कुल मिलाकर एक संतुलित बजट**



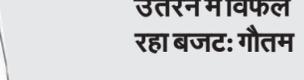
कुल मिलाकर बजट संतुलित कहा जा सकता है। इनकम टैक्स स्लेब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन नया कानून 1 अप्रैल से लागू होगा, 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स में छोटी गलती पर अब सजा नहीं मिलेगी, ये राहत भरा कदम है, क्योंकि चूक होना एक स्वभाविक बात है। कैन्सर और शुगर जैसे गंभीर रोगों के उपचार की लागत में अब कमी आएगी। ये कदम इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों व उनके परिवारियों के लिए राहत बड़ा कदम है। अब आवश्यक दवाओं और आधुनिक उपचार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। मरीजों को समग्र, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिलेगी। - बीरज राजपाल, आईआईए उपाध्यक्ष।

**पूँजीपतियों को राहत, गरीब को आफत : पारसनाथ**



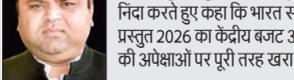
अयोध्या, अमृत विचार : सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने तीव्री प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट जनता के साथ एक और बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में सरकार ने युवाओं को दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में बेरोजगारी और बढ़ी। सरकार का दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ। इस बजट में किसानों पर भी दोहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान, नौजवान, मजदूर और गरीब वर्ग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है, जबकि चंद पूँजीपतियों को फिर से खुली छूट दी गई है। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती आयदनी पर इस बजट में कोई टोस समाधान नहीं है। समाजवादी पार्टी इस जनविरोधी बजट के खिलाफ मजबूती से संघर्ष करेगी।

**अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा बजट: गौतम**



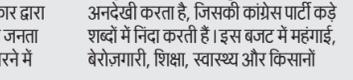
अयोध्या, अमृत विचार : कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम रानू ने बजट की निंदा करते हुए कहा कि भारत जनता के द्वारा प्रस्तुत 2026 का केंद्रीय बजट आम जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरने में विफल रहा है। यह बजट गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और युवाओं के हितों की अनदेखी करता है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस बजट में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की आय जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई टोस और प्रभावी प्रावधान नहीं किया गया है। बदती महंगाई से त्रस्त जनता को कोई राहत नहीं दी गई, वहीं रोजगार सृजन को लेकर भी सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं दिखाई देती।

**अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा बजट: गौतम**



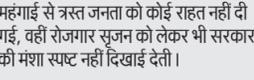
अयोध्या, अमृत विचार : कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम रानू ने बजट की निंदा करते हुए कहा कि भारत जनता के द्वारा प्रस्तुत 2026 का केंद्रीय बजट आम जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरने में विफल रहा है। यह बजट गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और युवाओं के हितों की अनदेखी करता है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस बजट में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की आय जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई टोस और प्रभावी प्रावधान नहीं किया गया है। बदती महंगाई से त्रस्त जनता को कोई राहत नहीं दी गई, वहीं रोजगार सृजन को लेकर भी सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं दिखाई देती।

**व्यापारी बोले-**



इनकम टैक्स स्लेब तो नहीं बदला, लेकिन कैन्सर की 17 दवाओं पर कस्टम इयूटी हटने से राहत मिली। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ तक बढ़ा है, उम्मीद है रोड-सेल अच्छी होगी, नौकरी के मौके बढ़ेंगे। कुल मिलाकर संतुलित बजट लगता है। - मनीष वैश्य, सर्राफा व्यवसायी।

**टैक्स से राहत मिलती तो और मजा आता**



काम बजट बढ़ने से मोबाइल बैटरी सस्ती हो सकती है। आई-स्प्रीड रेल कॉरिडोर से लॉजिस्टिक्स आसान होगा। थोड़ा और टैक्स राहत मिलती तो और मजा आता। - सुधीर तिवारी, दवा विक्रेता।

**बोले शिक्षक : संतुलन का अभाव, स्वास्थ्य शिक्षा में चाहिए था बढ़ना**



अयोध्या कार्यालय। अमृत विचार : डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर शिक्षकों द्वारा एक महत्वपूर्ण परिचर्चा (पैनल डिस्कशन) का आयोजन किया गया। यह परिचर्चा विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के बीच बजट के विभिन्न पहलुओं, जैसे शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और विकास योजनाओं पर केंद्रित रही। सभी प्रतिभागियों ने अपने विचार साझा किए, जिसमें बजट की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर चर्चा। आशुतोष सिन्हा ने बजट को वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में विश्लेषित करते हुए कहा कि यह बजट विकास और समावेशिता पर फोकस करता है, लेकिन शिक्षा और रोजगार सृजन में और अधिक निवेश की आवश्यकता है। डॉ. अलका श्रीवास्तव ने महिलाओं और युवाओं से जुड़ी योजनाओं पर जोर देते हुए बजट की कुछ कमियों की ओर इशारा किया। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में आवंटन को और बढ़ाने की मांग की। डॉ. सरिता द्विवेदी ने ग्रामीण विकास

**बोली महिलाएं**

**दवाएं सस्ती होने से राहत, राजमर्मा वस्तुओं के दामन घटने से निराशा**

बजट से महिलाओं में खुशी व गम दोनों हैं। दवाईयों, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व घरेलू उपकरण व ग्रीन पनर्जी से जुड़े उत्पाद सस्ते होने से घरेलू खर्च में राहत मिलेगी। राजमर्मा की जरूरी चीजें खाने पीने की वस्तुएं आदि में अभी राहत नहीं मिली है। - रश्मि केसरवानी, गृहिणी।

सोने-चांदी, दवा की कीमतों में कमी, खाद्य सामग्री की कीमतों में गिरावट के प्रयास से आम महिलाओं राहत मिलेगी। दैनिक उपयोग की वस्तुओं का सस्ता होना सराहनीय कदम है। रसोई के सामान का बफर स्टॉक बनाना चाहिए जिससे महंगाई नियंत्रण में रहे। - नीता भित्तल, गृहिणी।

कुछ घरेलू सामान व दवाईयों सस्ती होने से घर के खर्च में थोड़ी राहत होगी। महिलाओं के लिए योजनाओं और स्वरोजगार की बात भी सकारात्मक लगती है। राजमर्मा की महंगाई पर कोई खास राहत नहीं देखी। राशन व सब्जी के दाम अभी भी चिंतनीय है। - सपना रस्तोगी, गृहिणी।

कैन्सर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होने से राहत मिलेगी। विदेश यात्रा पर टीडीएस कम हुआ, लेकिन हम तो घूमने नहीं जाते। गृहिणी के नजरिए से स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा वाली बातें सबसे ज्यादा राहत देती हैं। महंगाई पर असर पड़े तो ठीक रहेगा। - शाहीन बानों, गृहिणी।

बजट में महिलाओं और छोटे उद्यमियों पर फोकस दिखा, लेकिन मेरे जैसे घर बैठे औरतों के लिए कुछ नहीं है। दवाईयों सस्ती होने से घर का मेडिकल खर्च बचेगा। कुल मिलाकर विकास तो दिख रहा है, लेकिन महंगाई का भ्रू में रहे तो ज्यादा खुशी होती। - सारिका शर्मा, गृहिणी।

आम महिलाओं व गृहिणियों के लिए कोई भी लाभदायक घोषणा नहीं की गयी है। ऊपर से किचन का बजट भी महंगाई से गड़बड़ है। साज सज्जा हेतु आवश्यक आभूषण व कार्मेण्टिक सामग्रियों के दाम बढ़ने से भी निराशा हाथ लगी है। मध्यम वर्ग को निराशा मिली। - अर्चना द्विवेदी, गृहिणी।

**युवा बोले- विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करेगा, बेरोजगार वर्ग में निराशा**



देवकली में अपने आवास पर बजट देखता एक परिवार। अमृत विचार

हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। कैन्सर के इलाज के लिए उपयोगी 17 दवाइयों पर कस्टम फ्री इयूटी दी गई है। तीन आयुर्वेदिक एप्स खोले जायेंगे, पूर्वोत्तर के राज्य में बैड सर्टिफिकेट की स्थापना की जाएगी। आशा है कि 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है वह पूरा करेगा। - डॉ. सिद्धांत दुबे

नौकरी पेशा वर्ग व बेरोजगार वर्ग के लिए निराशाजनक कहा जा सकता है। बजट में आयकर सीमा न बढ़ाना कष्ट कारक है, इससे ईमानदारी से आयकर अदा करने वाले वर्ग को निराशा हाथ लगी है। रोजगार सृजन पर पर्याप्त ध्यान न देकर पड़े लिखे बेरोजगार वर्ग को भी निराशा किया गया है। - यश कुमार।

स्वास्थ्य की दृष्टि से बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण वैश्विक बायोफार्म के विनिर्माण केंद्र की स्थापना है, जिससे जैविक दवाएं आने वाले दिनों में सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए दो राष्ट्रीय संस्था खोलने व हर जिला अस्पताल में ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित योग्य है। - डॉ. विनोद शुक्ला, डेंटल सर्जन।

लाइफस्टाइल बीमारियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के लिए बायोफार्म पर जोर देना सराहनीय है। इलाज, रिसर्च, मेडिकल टूरिज्म, आयुष और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को घटाने की कोशिश की गई है। ये कदम देश को मजबूत और आत्मनिर्भर हेल्थकेयर सिस्टम की ओर ले जायेंगे। - मोहडा मुखर्जी, डायटीशियन।

स्वास्थ्य बजट में वृद्धि और एलाइड प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग से संशोधन को बेहतर ऑपरेशनल सुधार का अवसर मिलेगा। मेडिकल टूरिज्म और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर से समग्र स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगी। यह बजट स्वास्थ्य को समावेशी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। - डॉ. कमाल खान, बाल रोग विशेषज्ञ।

**चिकित्सक बोले- बजट से मिलेगा विश्वस्तरीय चिकित्सीय सुविधाओं का अवसर**

हेल्थ एजुकेशन और केयरगिविंग को बढ़ावा देने की सरकार की योजना मातृत्व देखभाल और जेरियाट्रिक केयर पर सीधे असर डालेगी। मेडिकल टूरिज्म से जुड़े पहलुओं के साथ मिलकर यह विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के नए अवसर पैदा करती है। आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने से भारत की समग्र स्वास्थ्य प्रणाली और मजबूत होगी। - एमएस विष्णु, क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी।

कैन्सर के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बीमारी सुनते ही इंसान का मनोबल टूट जाता है, लेकिन आम बजट में 17 दवाएं सस्ती किए जाने की घोषणा से मरीजों को जरूर फायदा होगा। केंद्र सरकार का यह फैसला सराहनीय है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हुई घोषणाओं का स्वागत है। - डॉ. धीरेन्द्र सचान, एसोसिएट प्रोफेसर।

स्वास्थ्य बजट में वृद्धि और एलाइड प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग से संशोधन को बेहतर ऑपरेशनल सुधार का अवसर मिलेगा। मेडिकल टूरिज्म और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर से समग्र स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगी। यह बजट स्वास्थ्य को समावेशी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। - डॉ. कमाल खान, बाल रोग विशेषज्ञ।

**भाजपा कार्यालय में सुना गया लाइव प्रसारण**

**नेताओं ने कहा- उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट**

अयोध्या कार्यालय। अमृत विचार : भाजपा कार्यालय सिविल लाइव में भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लाइव प्रसारण को सामूहिक रूप से सुना। नेताओं ने इसे उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट बताया है। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश को चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित केंद्रीय सहायता मिलना तय है। यह राशि बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होगी। महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि आई-स्प्रीड रेल कॉरिडोर, एआई सिटी और आधुनिक

**उत्तर प्रदेश को दी गई विशेष प्राथमिकता : लल्लू सिंह**

पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि बजट में करों की हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और परियोजना आधारित सहायता को मिलाकर उत्तर प्रदेश को अधिक का लाभ मिलने का अनुमान है। आई-स्प्रीड रेल कॉरिडोर से काशी और पूर्वांचल को देश की आर्थिक धारा से और मजबूती से जोड़ा जाएगा। जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

**यंजनकल्याणकारी बजट है: वेद प्रकाश**

विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बजट को जनकल्याणकारी बताते हुए कहा, एआई सिटी और आधुनिक ट्रॉमा सेंटर जैसी घोषणाएं यह दर्शाती हैं कि केंद्र सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। एआई सिटी से युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश से आम नागरिक को सीधा लाभ पहुंचेगा।

**स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास से जुड़ी घोषणाएं सराहनीय : रोली**

जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी घोषणाओं की सराहना करते हुए कहा कि हर जिले में ट्रॉमा सेंटर और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सेवाएं पहुंचेंगी। केंद्र से मिलने वाली बड़ी हुई सहायता से पंचायत स्तर पर भी विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी।

**आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने वाला बजट : महापौर**

महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि शहरी विकास और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने वाला यह बजट है। केंद्रीय बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और तकनीक पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे नगर निगम क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार होगा और शहरों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।

## नेताओं ने कहा- उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट

अयोध्या कार्यालय। अमृत विचार : भाजपा कार्यालय सिविल लाइव में भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लाइव प्रसारण को सामूहिक रूप से सुना। नेताओं ने इसे उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट बताया है। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश को चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित केंद्रीय सहायता मिलना तय है। यह राशि बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होगी। महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि आई-स्प्रीड रेल कॉरिडोर, एआई सिटी और आधुनिक

**उत्तर प्रदेश को दी गई विशेष प्राथमिकता : लल्लू सिंह**

पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि बजट में करों की हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और परियोजना आधारित सहायता को मिलाकर उत्तर प्रदेश को अधिक का लाभ मिलने का अनुमान है। आई-स्प्रीड रेल कॉरिडोर से काशी और पूर्वांचल को देश की आर्थिक धारा से और मजबूती से जोड़ा जाएगा। जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

**यंजनकल्याणकारी बजट है: वेद प्रकाश**

विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बजट को जनकल्याणकारी बताते हुए कहा, एआई सिटी और आधुनिक ट्रॉमा सेंटर जैसी घोषणाएं यह दर्शाती हैं कि केंद्र सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। एआई सिटी से युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश से आम नागरिक को सीधा लाभ पहुंचेगा।

**स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास से जुड़ी घोषणाएं सराहनीय : रोली**

जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी घोषणाओं की सराहना करते हुए कहा कि हर जिले में ट्रॉमा सेंटर और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सेवाएं पहुंचेंगी। केंद्र से मिलने वाली बड़ी हुई सहायता से पंचायत स्तर पर भी विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी।

**आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने वाला बजट : महापौर**

महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि शहरी विकास और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने वाला यह बजट है। केंद्रीय बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और तकनीक पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे नगर निगम क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार होगा और शहरों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।

**यह ऐतिहासिक बजट : रामचंद्र**

रुदौली में केंद्र का बजट आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाते विधायक रामचंद्र यादव। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में 7 आई-स्प्रीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने में मदद मिलेगी। बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे देश में कैन्सर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाईयों सस्ती होंगी। कहा लखपति दीदी कार्यक्रम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।



## न्यूज़ ब्रीफ

## मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का डिप्टी सीएमओ ने किया निरीक्षण

भदैया, सुलतानपुर, अमृत विचार : शंभूराज पौपलसी पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 45 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निशुल्क दवाएं वितरित की गईं। मेले में शुगर, बीपी व डैगू की जांच की गई, सभी रिपोर्ट सामान्य पाई गईं। इस दौरान डिप्टी सीएमओ सफीकुर रहमान ने मेले का औद्योगिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. मंजर ईरान ने बताया कि मौसम परिवर्तन के चलते हृदय, सांस से रक्तचाप संबंधी मरीज बढ़ रहे हैं।

## बुक फ्रॉर ऑल ट्रस्ट ने विद्यालय को भेंट की है गिंग लाइब्रेरी

सुलतानपुर, अमृत विचार : जनपद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सादापुर, प्रतापपुर कमेठा में शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। बुक फ्रॉर ऑल ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा विद्यालय को पुस्तकों का एक पूर्ण सेट एवं एक आकर्षक हैंगिंग लाइब्रेरी प्रदान की गई। यह प्रजादायी कार्य सोशल वेलफेयर एंड अपिलिफ्टमेंट ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष कुमार अग्रवाल के प्रयासों से संभव हो सका। इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। नई पुस्तकों और हैंगिंग लाइब्रेरी को देखकर विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति विशेष रुचि दिखाई दी। विभिन्न विषयों, सामान्य ज्ञान, नैतिक शिक्षा और बाल साहित्य की पुस्तकों से बच्चों के बौद्धिक व रचनात्मक विकास को बल मिलेगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने ट्रस्ट एवं श्री अग्रवाल के प्रति आभार जताते हुए इसे ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने वाला कदम बताया।

## अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक घायल, मौत

लुधुआ, सुलतानपुर, अमृत विचार : लुधुआ कस्बे में जल्ले आरामशीन के समीप रविवार की शाम अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, गंभीर रूप से घायल युवक को राहगीरों की मदद से सीपवसी लुधुआ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मुक्त युवक की पहचान अजीमुद्दीन पिता मौलवी हसन अली उम्र 21 वर्ष निवासी शंकरपुर थाना लुधुआ जनपद सुलतानपुर के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि वह चांदा अपनी बहन को छोड़कर बाइक से घर वापस लौट रहा था और लुधुआ में दुर्घटना हो गई।

## अकेला हूं मैं साथ पाने की खातिर...

लखनऊ, अमृत विचार: सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था अवध साहित्य संगम ने संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती वजीरगंज रेलवे क्रॉसिंग स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में धूमधाम से मनाई गई। जिसमें एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता अशोक टाटम्बरी और संचालन राजीव मतवाला ने किया।

कार्यक्रम की शुरुआत अशोक टाटम्बरी की वाणी वंदना वाणी पाणी रजो राजू मोरी रसना पे दिन रैन दिन से हुई। नाते पाक पेश किया रामानंद सागर में जो सना खान-ए खैरूल वरा हो गए, यह न पूछो कि वो क्या से क्या हो गए। सबसे पहले रामानंद सागर ने कहा रविदास जी को यूं ही नहीं संत

## केंद्रीय बजट

## एमएसएमई व मैनुफैक्चरिंग को मिलेगी नई रफ्तार

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने रविवार को आईआईए भवन, लखनऊ में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर चर्चा सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर आईआईए के पदाधिकारी, उद्योगपति, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और नीति विशेषज्ञ बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय बजट की प्रमुख घोषणाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस मौके पर पर आईआईए के राष्ट्रीय सचिव प्रमित कुमार सिंह, डिविजनल चेयरमैन

संवाददाता, सुलतानपुर

अमृत विचार: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2026 को लेकर जिले में राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्रों से तीखी, लेकिन विविध प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जहां एक ओर बजट को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया गया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और मध्यम वर्ग ने इसे कोरे आश्वासनों का दस्तावेज करार दिया। बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने अपने-अपने दृष्टिकोण रखे।

गणपत सहाय पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) डॉ. दिनेश चंद्र द्विवेदी ने बजट को समय के प्रश्नों का उत्तर देने वाला बताया। कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास और ग्रामीण उद्योग पर फोकस आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करता है। एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़ निवेश, बुजुर्गों के लिए मेडिकल केयर इकाईसिस्टम, कैसर की 17 दवाओं

पर सीमा शुल्क छूट जैसे प्रावधान दीर्घकालिक लाभ देने वाले हैं।

वहीं, गणपत सहाय पीजी कॉलेज के प्राचार्य एवं अर्थशास्त्री प्रो. अंग्रेज सिंह राणा ने बजट 2026 को भरोसे, भागीदारी और बराबरी का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट रफ्तार, क्षमता और सबका साथ के विज्ञान पर आधारित है। इसके उलट कांग्रेस पार्टी के नि. राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर राजेश तिवारी ने बजट को पूरी तरह निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ जुमलों का पुलिंदा है, जिसमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई ठोस रोडमैप नहीं है। युवाओं, महिलाओं और छोटे व्यापारियों के लिए यह बजट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और 2047 का सपना दिखाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है।

उधर, भाजपा जिला कार्यालय पर 26 मंडलों में बजट का लाइव प्रसारण देखा गया। प्रदेश मंत्री व जिला प्रभारी मीना चौबे ने बजट को 2047 तक विकसित व आत्मनिर्भर भारत बनाने का रोडमैप बताया। भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने बजट को ऐतिहासिक बताया है, कहा कि इससे लोकल से ग्लोबल, की दिशा मजबूत होगी और छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा।

## विधि शिक्षा केवल पेशा नहीं, सामाजिक दायित्व

संवाददाता, सुलतानपुर, अमृत विचार: प्राणा विधि महाविद्यालय की प्रबंध समिति की प्रथम बैठक माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कूरुभार स्थित परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रबंध समिति के अध्यक्ष एडवोकेट संजय सिंह ने की। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज में न्याय, संवैधानिक मूल्यों और विधि के शासन को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम है। महाविद्यालय को गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

बैठक में उपाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद सिंह ने विधि क्षेत्र में उपलब्ध विविध कैरियर संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए अकादमिक गुणवत्ता, अनुशासन एवं व्यावहारिक

● प्रबंध समिति की प्रथम बैठक में बोले अधिवक्ता संजय सिंह

प्रशिक्षण को मजबूत करने की आवश्यकता जताई। प्रबंधक योगेश प्रताप सिंह ने न्याय, संवैधानिक मूल्यों और विधि के शासन को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम है। महाविद्यालय को गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

बैठक में उपाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद सिंह ने विधि क्षेत्र में उपलब्ध विविध कैरियर संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए अकादमिक गुणवत्ता, अनुशासन एवं व्यावहारिक

कार्यक्रम में काव्य पाठ करते कवि।

● अमृत विचार

● धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती

शिरोमणि कहा जाता। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्रसाद कथा गंगा जी का कंगन सबको सुना कर तालियां बजाने के लिए विवस कर दिया। नै फिर् दौर शुरू होता है शरो शायरी का संतोष अकेला ने

कक्षा एक की छात्रा को बाइक ने मारी टक्कर

दोस्तपुर, सुलतानपुर, अमृत विचार : थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुरहुपुर निवासी समरबहादुर निषाद की छह वर्षीय पुत्री आंवल उर्फ सुष्टि शुक्लवार की गांव स्थित विद्यालय जाने के लिए सड़क किनारे पहुंची थी। इसी दौरान मोतिलारपुर की ओर से दोस्तपुर की तरफ आ रही एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। घातक बच्यो को परिजन तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोस्तपुर ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल अंबेडकरनगर के लिए रिफर कर दिया। पीड़िता के चाचा की तहरीर पर बाइक संख्या यूपी 44 बीएल 1727 के चालक अरबाज, निवासी सलारगंज मोतिलारपुर, के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कहा अकेला हूं मैं साथ पाने की खातिर हुआ रूबरू कुछ सुनने की खातिर। अल्केश दत्त पाठक मीत देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल अंबेडकरनगर के लिए रिफर कर दिया। पीड़िता के चाचा की तहरीर पर बाइक संख्या यूपी 44 बीएल 1727 के चालक अरबाज, निवासी सलारगंज मोतिलारपुर, के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

आईआईए लखनऊ में बजट देखने और चर्चा सत्र का हुआ आयोजन

कार्यक्रम में काव्य पाठ करते कवि।

● अमृत विचार

● धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती

शिरोमणि कहा जाता। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्रसाद कथा गंगा जी का कंगन सबको सुना कर तालियां बजाने के लिए विवस कर दिया। नै फिर् दौर शुरू होता है शरो शायरी का संतोष अकेला ने

कक्षा एक की छात्रा को बाइक ने मारी टक्कर

दोस्तपुर, सुलतानपुर, अमृत विचार : थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुरहुपुर निवासी समरबहादुर निषाद की छह वर्षीय पुत्री आंवल उर्फ सुष्टि शुक्लवार की गांव स्थित विद्यालय जाने के लिए सड़क किनारे पहुंची थी। इसी दौरान मोतिलारपुर की ओर से दोस्तपुर की तरफ आ रही एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। घातक बच्यो को परिजन तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोस्तपुर ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल अंबेडकरनगर के लिए रिफर कर दिया। पीड़िता के चाचा की तहरीर पर बाइक संख्या यूपी 44 बीएल 1727 के चालक अरबाज, निवासी सलारगंज मोतिलारपुर, के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

आम बजट पर चर्चा करते आईआईए के पदाधिकारी।

● अमृत विचार

के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट स्पष्ट रूप से भविष्योन्मुखी और विकास-संचालित है। इसके साथ-उन्होंने बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग और हाई-स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर



डॉ. सुनील त्रिपाठी

डॉ. दिनेश चंद्र द्विवेदी

राजेश तिवारी

सुशील त्रिपाठी

## बजट में उद्योगों व स्वास्थ्य को बढ़ावा, रसोई की महंगाई से महिलाओं को चिंता

विदेश्वरीगंज: देहली बाजार स्थित हरिशंकर हार्डवेयर के एमडी संतोष कुमार तिवारी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि रणनीतिक क्षेत्रों में मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुद्धार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सरकार का जोर देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारियों के साथ-साथ आम जनता को भी लाभ होगा।

बधोना प्रेकंधई शुक्ल निवासी गृहणी पूनम धर्मनंद शुक्ला ने बजट को महत्वाकांक्षी बताया है, कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देना सराहनीय कदम है। बच्चों के खेलने से जुड़े सामान सस्ते किए जाने से मध्यम और गरीब वर्ग को राहत मिलेगी। कैसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज से जुड़े प्रावधानों को उन्होंने स्वागत योग्य बताया, लेकिन रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की महंगाई पर राहत न मिलने से निराशा भी जताई।

बल्दौराय निवासी बुजुर्ग गौरीशंकर आर्य ने बजट को जनहितकारी बताया है, कहा कि लंबी और गंभीर बीमारियों से जुड़ रहे मरीजों के लिए किए गए प्रावधान अत्यंत लाभकारी हैं। खेल सामग्री सस्ती किए जाने से ग्रामीण बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़े कदमों की भी सराहना की।

वहीं बल्दौराय में तैनात चिकित्सक डॉ. अशोक मिश्रा ने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को काले सरकार के निर्णय प्रशंसनीय है। हेल्थ केयर कोम्प्लेक्स के निर्माण, औषधि केंद्रों के विस्तार और कैसर की दवाओं को सस्ता किए जाने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देकर भारतीय चिकित्सा पद्धति को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में यह बजट अहम साबित होगा। साथ ही तीन नए एम्स की स्थापना से देश में स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत होंगी।



संतोष तिवारी



पूनम धर्मनंद शुक्ला



गौरीशंकर आर्य



डॉ. अशोक मिश्रा

## किराना स्टोर में आग से लाखों का नुकसान

मोतिगरपुर, सुलतानपुर

अमृत विचार: स्थानीय थाना क्षेत्र के कालीगंज बाजार में शनिवार देर रात शॉर्ट सर्किट से किराना एवं जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया, जबकि मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आग की लपटों और घने धुंए से पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। जानकारी के अनुसार मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के विभारपुर निवासी शरद जायसवाल की कालीगंज बाजार में स्थित मकान में “जायसवाल किराना एंड जनरल स्टोर” नाम से थोक व फुटकर की दुकान संचालित है। वर्तमान में उनका परिवार दोस्तपुर थाना क्षेत्र के रोसाईसिंहपुर बाजार स्थित मकान में रहता है। पीड़ित के अनुसार शनिवार रात करीब नौ बजे दुकान बंद कर व



शॉर्ट सर्किट से लगी किराना स्टोर की दुकान में आग।

● अमृत विचार

● शॉर्ट सर्किट बना हादसे की वजह एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू

घर चले गए थे। देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लग गई। रविवार तड़के करीब साढ़े चार बजे तेज धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जागे। दुकान से उठती आग की लपटें और धुआं देख तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि दुकान का लोहे का शटर तक लाल हो गया, छत गिर गई और भवन पूरी तरह नहीं कर सका। सूचना पर पहुंची फायर

ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मौके पर मोतिगरपुर थाना के उपनिरीक्षक श्रीराम मिश्र पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।

35 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान

पीड़ित शरद जायसवाल ने बताया कि सहालग को देखते हुए दुकान में भारी मात्रा में किराने का सामान रखा गया था। एक दिन पहले ही करीब डेढ़ लाख रुपये का नया सामान भी आया था। आग की इस घटना में लगभग 35 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान को कमजोर कर रही है, जिससे गांव के गरीब मजदूरों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। कहा मजदूरी

स्वास्थ्य मेले में जुकाम-बुखार के मरीजों की संख्या अधिक रही

विदेश्वरीगंज, सुलतानपुर, अमृत विचार: बल्दौराय तहसील क्षेत्र के विदेश्वरीगंज, देहली बाजार और हलियापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। देहली बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल 41 मरीजों का उपचार किया गया, जिनमें सर्दी-जुकाम, बुखार एवं त्वचा रोग के मरीजों की संख्या अधिक रही। यहां डॉ. विकास, फार्मासिस्ट मनोज श्रीवास्तव, स्टाफ नर्स राजनंदिनी तथा एएनएम अमिता श्रीवास्तव मौजूद रहीं। वहीं, विदेश्वरीगंज

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 21 मरीजों का परीक्षण किया गया। यहां भी सर्दी-जुकाम व बुखार के मरीज अधिक पाए गए। मेले में डॉ. शशि प्रकाश सिंह, फार्मासिस्ट करुणेश पांडेय, लैब टेक्नीशियन निशा यादव और स्टाफ नर्स सरिता पाल उपस्थित रहीं। मेले का निरीक्षण डिप्टी सीएमओ आर.के. कनौजिया ने किया।

हलियापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित जन आरोग्य मेले में डॉ. मीरा श्रंगार ने मरीजों का उपचार किया। उनके साथ फार्मासिस्ट चक्रपाणि दुबे, स्टाफ नर्स ज्योति गुप्ता, लैब टेक्नीशियन अनिरुद्ध मिश्रा और एएनएम प्रियंका सिंह मौजूद रहीं।

एसएफआई सुलतानपुर का 26वां सम्मेलन संपन्न

सुलतानपुर, अमृत विचार : छत्र संघटन एसएफआई सुलतानपुर का 26वां जिला सम्मेलन शनिवार को कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन हाल में संपन्न हुआ। सम्मेलन से पूर्व बस स्टेशन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। जिला अध्यक्ष अमीर हमजा ने संपन्न का झंडा रोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि बाल मुकुंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक आम प्रकाश वर्मा ने कहा कि शिक्षा इतनी सुलभ होनी चाहिए कि कोई भी छात्र आर्थिक कारणों से वंचित न रहे और शिक्षा सामाजिक मूल्यों का विकास करे। राज्य अध्यक्ष पार्थ सारथी द्विवेदी ने शिक्षा बजट में कटौती, विश्वविद्यालयों को अनुदान के स्थान पर ऋण देने और सरकारी स्कूलों के सम्मेलन को गरीब व पिछड़े छात्रों के लिए घातक बताया। दूसरे सत्र में 21 सदस्यीय जिला समिति का चुनाव हुआ, जिसमें सलिल बुरिया अध्यक्ष और दुर्गा यादव सचिव चुने गए। सम्मेलन में आठ इकाइयों से 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

## ग्रामीण इलाकों में 6-8 घंटे की अघोषित बिजली कटौती

भदैया, सुलतानपुर

अमृत विचार: ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार छह से आठ घंटे की अघोषित बिजली कटौती से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बिजली संकट का सीधा असर खेती-किसानी के साथ-साथ छोटे व्यापारियों पर भी पड़ रहा है। दिनभर विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों को खासा दिक्कत हो रही है।

भदैया विकास खंड क्षेत्र में भदैया, लोलेपुर, दरियापुर और पकड़ी उपकेंद्रों से विद्युत आपूर्ति की कटौती है। भदैया उपकेंद्र से बार-बार फाल्ट होने और दिन में लगभग छह घंटे बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं दरियापुर उपकेंद्र से जुड़ी भगटा-रनुमानगंज लाइन पर भी प्रतिदिन छह से आठ घंटे बिजली आपूर्ति बाधित की जा रही है। पकड़ी उपकेंद्र के अंतर्गत बालमपुर क्षेत्र में सुबह छह से आठ बजे तथा दोपहर दो से शाम छह बजे तक कुल छह घंटे की रोस्टर कटौती की जा रही है।

लगातार हो रही बिजली कटौती के चलते बिजली पर निर्भर दुकानदार सुबह तड़के दुकान खोलकर काम निपटाने को मजबूर हैं। वहीं गेहूं की फसल

● किसान और व्यापारी परेशान खेती और कारोबार पर असर

● अवर अभियंता बोले- फाल्ट होने पर की जाती है अस्थायी कटौती

की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों को रात में नलकूप चलाकर खेतों की सिंचाई करनी पड़ रही है। सदी की शुरुआत में ही दिन के समय बिजली कटौती ने किसानों और व्यापारियों को चिंता बढ़ा दी है।

इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की दुकान चलाने वाले चंद्रभान यादव ने बताया कि वे पिछले तीन दिनों से सुबह छह बजे ही दुकान खोल रहे हैं, क्योंकि सुबह नौ बजे के बाद बिजली कट जाती है। वहीं किसान चंद्र प्रकाश मिश्र, भूपेश और अनुज तिवारी ने कहा कि दिन में बिजली न मिलने के कारण उन्हें रात में सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे परेशानी और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि अनावश्यक कटौती से सबसे अधिक नुकसान खेती को हो रहा है।

अवर अभियंता भदैया आर.पी. गुप्ता ने बताया कि बिजली कटौती शासन के निर्देशानुसार की जा रही है। उन्होंने कहा कि रोस्टर के अनुसार ही विद्युत आपूर्ति दी जा रही है तथा फाल्ट की स्थिति में मरम्मत के लिए अस्थायी कटौती करनी पड़ती है।

## मनरेगा कांग्रेस की देन, भाजपा इसे खत्म करने पर आमादा

मोतिगरपुर, सुलतानपुर

● मनरेगा बचाओ चौपाल का किया गया आयोजन

भुगतान में देरी, कार्य आवंटन में कमी तथा बजट कटौती जैसे मुद्दों को उठाते हुए इसे गरीब-विरोधी मानसिकता का परिचायक बताया। जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस की देन है, लेकिन वर्तमान सरकार इसे समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांव-गांव जाकर मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। ब्लॉक अध्यक्ष राहुल मिश्र ने कहा कि मजदूरों को न तो पर्याप्त काम मिल पा रहा है और न समय पर मजदूरी, जो सरकार की विफलता को दर्शाता है।

चौपाल में जयप्रकाश पाठक, उमेश पांडेय, श्याम नारायण पांडेय, मोती पाल, अंकुर सायण, सतीश सिंह आदि मौजूद रहे।

## अमृत विचार

## क्लासीफाइड

विज्ञापन हेतु अमृत विचार कार्यालय में सम्पर्क करें

सूचना

मेरे पुत्र का स्कूल में नाम AADHYANSH गलत अंकित हो गया है जबकि सही नाम ADYANSH DWIVEDI है।उसे भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। आवर्ष द्विवेदी पुत्र श्री आर एस दुबे निवासी 135, बेट नंज शाना कोतवाली शहर जिला हरदोई।

सूचना

मेरे पुत्र दीपक यादव का चाल चलन समाज विरोधी व संदेहजनक हो गया है। समझाने के बाद भी उसमें सुधार नहीं है। इस कारण से मैंने उससे सम्बंध विच्छेद कर अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेवखल कर दिया। यदि वह किसी से लेनदेन या कोई कृत्य करता है तो वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा। उसका परिवार के लोगों से कोई सरोकार नहीं। सतीश कुमार पुत्र मोहर सिंह निवासी मोहनपुर पोस्ट लखौरी संपर्क इटावा।

सूचना

मैं सत्य नारायण सुत स्व० बाबू राम निवासी ग्राम सोनबरसा पोस्ट रामपुर थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर यह कि मैं आर्मी से सेवानिवृत्त आर्मी नं० 13869536H नायक के पद पर सेवा दे चुका हूँ। मेरी सेवापुस्तिका में मेरे पत्नी चन्द्रवती की अन्वतिथि 01/07/1962 व नाम चन्द्रवती दर्ज हो गया है जबकि मेरे पत्नी की सही जन्मतिथि 01/01/1959 व नाम चन्द्रवती सत्य व सही है।

सूचना

पहले मेरा नाम Vasin Khan था अब मैंने बदलकर अपना नाम Wassem Khan रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व प ह च ा न ा ज ा ए । S / O - Mohammad Shahid Khan R/O- Bhewapar, Isur, Sultanpur, Uttar Pradesh, - 228142

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में मेरा और मेरे पिता का नाम आनंद त्रिपाठी पुत्र रामकृपाल त्रिपाठी दर्ज है जबकि पेन कार्ड में मेरा और मेरे पिता का नाम आनंद त्रिपाठी पुत्र राम कृपाल त्रिपाठी दर्ज है, भविष्य में मेरे और मेरे पिता के नाम को आनंद त्रिपाठी पुत्र राम कृपाल त्रिपाठी समाप्त व पढ़ा जाए। आनंद त्रिपाठी पुत्र रामकृपाल त्रिपाठी ग्राम व पो. हाजीपुर जिला अयोध्या

सूचना

मेरे पिता महादेव पुत्र रामलुनार विगत 25 फरवरी 2016 से अचानक वहीं गांव हो गए हैं। इनकी उम्र लगभग 88 वर्ष है। इनका रंग सांबला लंबाई 5 फीट 8 इंच है। शरीर चौड़ा तथा बाल सफेद हैं। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इनके लापता होने की सूचना थाना तुलसीपुर में 10 अक्टूबर 2017 को दर्ज है। इनकी बहुत तलाश की गई लेकिन इनका कोई पता नहीं चल सका है। संतम पुत्र महादेव निवासी राम संडवा गुलरिहा, परगना, थाना व तहसील तुलसीपुर जनपद-बलरामपुर +919651453805

सूचना

पहले मेरा नाम SANJAY SINGH था अब मैंने बदलकर अपना नाम SANJAY SINGH KASERA रख लिया है भविष्य में मुझे SANJAY SINGH KASERA के नाम से जाना व पहचाना जाए। S/O- RAD

## संप्रभुता पर सख्त

देश के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा यह स्पष्ट कहना कि तथाकथित 'चिकन नेक' भारत की भूमि है और इस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य के एक गंभीर रणनीतिक संकेत है। बयान बताता है कि केंद्र सरकार 22 किलोमीटर चौड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर अत्यंत सतर्क और इसकी रक्षा के लिए आक्रामक रुख रखती है। 'चिकन नेक' पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से जोड़ने वाली एकमात्र स्थलीय कड़ी है। इसके पश्चिम में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश और उत्तर में भूटान तथा चीना का प्रभाव क्षेत्र है। यदि इस संकरी पट्टी की सुरक्षा में कोई व्यवधान आता है, तो आठ पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक और सामरिक निरंतरता पर प्रत्यक्ष असर पड़ सकता है।

इस दृष्टि से इसे रणनीतिक संप्रभुता का मामला माना जाना चाहिए। गृहमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि दिल्ली में कुछ तत्वों ने इस कॉरिडोर को 'काट देने' जैसे नारे लगाए थे। उनके बयान पर केंद्र की कड़ी प्रतिक्रिया यह संदेश देती है कि राष्ट्रीय एकता और भौगोलिक अखंडता पर कोई भी सार्वजनिक उकसावा अब सहन नहीं किया जाएगा और राजनीतिक विमर्श की आड़ में सामरिक संवेदनशीलता को हल्के में लेने वालों के साथ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा भी इसी व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा है। जहां भूमि संबंधी विवाद हैं, वहां केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, हलौकिक कवल भूमि का मुद्दा ही बाधा नहीं है; तकनीकी सर्वेक्षण, सीमा निर्धारण के अंतर्राष्ट्रीय समझौते और स्थानीय विरोध भी प्रक्रिया को धीमा करते हैं।

असल में सीमा प्रबंधन में भूमि अधिग्रहण, स्थानीय प्रशासन का सहयोग, पर्यावरणीय स्वीकृतियां तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रोटोकॉल जैसे जटिल पहलू शामिल होते हैं। कई स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में देरी एक व्यावहारिक बाधा रही है, पर यह पूरी कहानी नहीं है। नदियां, आबादी का घनत्व, तस्करी की चुनौतियां और सीमा पर रहने वाले नागरिकों के आजीविका संबंधी प्रश्न भी बाड़बंदी को जटिल बनाते हैं। इसलिए दूसरी सीमाओं, विशेषकर कुछ हिस्सों में भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमा पर भी पूर्ण बाड़बंदी अभी बाकी है।

भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आती तो भी बाड़ तो लगेगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी एक दल के शासन पर निर्भर नहीं हो सकती। संवैधानिक ढांचे के भीतर केंद्र सरकार के पास सीमा सुरक्षा के पर्याप्त अधिकार हैं। किंतु प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार का सहयोग अनिवार्य होता है। बेहतर समाधान यह होगा कि इसे चुनावी मुद्दा बनाने के बजाय सर्वदलीय सहमति और केंद्र-राज्य समन्वय के जरिए आगे बढ़ाया जाए। गृहमंत्री का बयान केवल चुनावी आरोप-प्रत्यारोप नहीं माना जाना चाहिए। यह उस बदलते सुरक्षा वातावरण की स्वीकृति है, जिसमें हाइब्रिड युद्ध, सूचना युद्ध और आंतरिक अस्थिरता के प्रयास समान रूप से गंभीर खतरे हैं। 'चिकन नेक' केवल एक भूगोल नहीं, भारत की पूर्वोत्तर नीति, 'एक्ट ईस्ट' रणनीति और सामरिक आत्मविश्वास का प्रतीक है, इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक शोर से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के ठोस, संस्थागत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना समय की मांग है।

### प्रसंगवश

## एक संन्यासी ने हजारों आंखों में भर दी रोशनी

पंजाब के एक छोटे से गांव से निकले एक साधारण युवक ने संन्यास का मार्ग चुना और राजस्थान में पहुंच कर भक्ति के साथ जन सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने अपने तप, त्याग व करुणा से हजारों लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया। वह युवक संत स्वामी ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है। गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री प्रदान देने की घोषणा की है। उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि उस विचारधारा पर मुहर है, जिसमें सेवा को साधना और मानवता को धर्म माना जाता है।

पंजाब के मोगा जिले की निहाल सिंह वाला तहसील में एक छोटा सा गांव है- रौता। इस गांव से एक दिन एक युवक निकला, लेकिन उसने दुनिया से कुछ पाने का नहीं बल्कि दुनिया को कुछ लौटाने का रास्ता चुना। यह युवक आगे चलकर स्वामी ब्रह्मदेव के नाम से विख्यात हुए। स्वामी ब्रह्मदेव ने संन्यास लिया, लेकिन समाज से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने पीड़ित मानवता की पीड़ा को देखा। उन्होंने 1963 में जब अमृतसर में श्री दुर्याना मंदिर में अंध विद्यालय को देखा तो ऐसा ही कोई काम करने का संकल्प किया।

अपनी शिक्षा पूर्ण कर वह 1978 में राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक मंदिर में आए। यहीं से शुरू हुई श्री जगदंबा अंध विद्यालय की कहानी। शुरुआत बहुत साधारण थी। कोई बड़ी इमारत नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं। थे तो बस कुछ अच्छे लोह और स्वामी जी का अटूट भरोसा। जन सहयोग से रोपा गया एक छोटा सा पौधा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही पौधा एक दिन वटवृक्ष बन जाएगा।

वर्ष 1980 में उन्होंने जगदंबा अंध विद्यालय की आधारशिला रखी। जगदंबा अंध विद्यालय की शुरुआत केवल एक बच्चे और एक शिक्षक के साथ हुई थी, लेकिन आज वह वटवृक्ष बन चुका है। बीते साढ़े चार दशकों में उन्होंने सात हजार से ज्यादा दुष्टिबाधित बच्चों को शिक्षित किया है। मूक-बधिर बच्चों के लिए चार दशक से स्कूल भी चल रहा है। स्वामी ब्रह्मदेव ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें जीना भी सिखाया। नेत्रहीन और मूक-बधिर बच्चों के हाथ में हुनर दिया, साथ में आत्म विश्वास भी दिया। आज उस विद्यालय से पढ़े अनेक बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं।

स्वामी जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो जन्म से अंधे नहीं हैं, बस आर्थिक संकट के कारण इलाज नहीं करा पाए। यहीं से शुरू हुआ मोतियाबिंद ऑपरेशन का काम। वर्ष 1993 में स्थापित श्री जगदंबा आई हॉस्पिटल में अब तक साढ़े चार लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर उनकी आंखों की रोशनी बचाई जा चुकी है। साढ़े चार लाख का यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं है। यह साढ़े चार लाख घरों में लौटी उम्मीद है। स्वामी ब्रह्मदेव ने समाज को एक और गहरी बात सिखाई है, वह है मरणोपरांत नेत्रदान। उन्होंने लोगों को समझाया कि मौत के बाद भी किसी की जिंदगी रोशन की जा सकती है। धीरे-धीरे यह बात लोगों के दिलों में उतरती गई। सालों से संस्था के जरिए नेत्रदान करा कर जरूरतमंदों को नेत्र प्रत्यारोपित किए जाते हैं।

स्वामी ब्रह्मदेव का जीवन दिखावे से दूर रहा है। वह कथा-कीर्तन करते हैं, चढ़ावे में आया धन सेवा में लाना देते हैं। न कोई शोर, न कोई प्रचार। वही सादा वेरा, वही सरल बोलचाल। वे खुद संस्था में मौजूद रहते हैं, काम देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। उनके लिए सेवा कोई परियोजना नहीं है, जीवन का स्वभाव है। पद्मश्री मिलने के बाद भी उन्होंने श्रेय खुद नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान प्रभु की कृपा और जनता के निःस्वार्थ सहयोग का प्रतिफल है।



सपने को साकार होने से रोकने वाली एकमात्र चीज है- असफलता का भय।  
-पाउलो कोएल्हो, ब्राजीलियन लेखक

# आम बजट 2026 विकास व अनुशासन का संतुलन



राजत मेहरोत्रा  
वित्तीय एवं आर्थिक विशेषज्ञ

केंद्रीय बजट 2026-27 केवल सरकार का हिसाब-किताब नहीं, बल्कि यह बताता है कि आने वाले समय में देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। दुनिया में व्यापार तनाव, तकनीकी बदलाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच सरकार ने इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है। सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाकर लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये किया है और यह लक्ष्य रखा है कि देश का कुल कर्ज (Debt/GDP) अनुपात को बजट अनुमान 2026-27 में GDP के 55.6% के रूप में आंका गया है, जबकि संशोधित अनुमान 2025-26 में यह 56.1% था। Debt-to-GDP अनुपात में गिरावट का अर्थ है कि समय के साथ सरकार को उधार लेना पड़ता है, तो उसे कम उधारा लेना पड़ता है और ब्याज पर होने वाला खर्च भी कम होता है। इसका सीधा फायदा यह होता है कि सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी क्षेत्रों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। घाटा कम होने से महंगाई पर भी दबाव घटता है। इसके अलावा, जब फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में रहता है, तो विदेशी निवेशकों और रेंटिंग एजेंसियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है, जिससे देश में निवेश आता है और रुपया भी मजबूत रहता है। कुल मिलाकर, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट घटाने का उद्देश्य केवल हिसाब संतुलित करना नहीं है, बल्कि भविष्य में विकास के लिए स्थायी और भरोसेमंद आर्थिक आधार तैयार करना है।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट को आय स्थिरता व जोखिम प्रबंधन का बजट कहा जा सकता है। सिंचाई परियोजनाओं, कृषि अवसररचना और वेयर हाउसिंग नेटवर्क के विस्तार से फसल नुकसान कम होगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी। एग्री-लॉजिस्टिक्स और कोल्ड-चेन पर निवेश बढ़ाकर कृषि उत्पादों की बर्बादी घटाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म और फसल बीमा कवरेज के विस्तार से किसानों की आय में स्थिरता आएगी। कृषि-आधारित एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्धन और रोजगार दोनों बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है।

छात्रों और युवा शक्ति के लिए यह बजट 'शिक्षा से रोजगार' की कड़ी को मजबूत करता है। डिजिटल शिक्षा अवसररचना, स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक लैब तथा उद्योग से जुड़े कौशल कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। शिक्षा और मेडिकल शिक्षा से जुड़े टीसीएस प्रवधानों को घटाकर 2% किए जाने से विदेशी मध्यम करने वाले मध्यम वर्गीय छात्रों को सीधी राहत मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल डिग्री उत्पादन नहीं, बल्कि रोजगार योग्य युवा तैयार करना है, ताकि जनसंख्या लाभार्थ वास्तविक आर्थिक शक्ति बन सके। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बजट में केंद्रीय स्थान मिला है। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण, बीमा और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने से महिलाओं की भागीदारी औपचारिक अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2026 संजीवनी जैसा है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का एमएसएमई प्रोथे फंड घोषित किया है, जिससे छोटे उद्योगों को सस्ता ऋण और विस्तार का अवसर भी मजबूत रहता है। कुल मिलाकर, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट घटाने का उद्देश्य केवल हिसाब संतुलित करना नहीं है, बल्कि भविष्य में विकास के लिए स्थायी और भरोसेमंद आर्थिक आधार तैयार करना है।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट को आय स्थिरता व जोखिम प्रबंधन का बजट कहा जा सकता है। सिंचाई परियोजनाओं, कृषि अवसररचना और वेयर हाउसिंग नेटवर्क के विस्तार से फसल नुकसान कम होगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी। एग्री-लॉजिस्टिक्स और कोल्ड-चेन पर निवेश बढ़ाकर कृषि उत्पादों की बर्बादी घटाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म और फसल बीमा कवरेज के विस्तार से किसानों की आय में स्थिरता आएगी। कृषि-आधारित एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्धन और रोजगार दोनों बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है।

छात्रों और युवा शक्ति के लिए यह बजट 'शिक्षा से रोजगार' की कड़ी को मजबूत करता है। डिजिटल शिक्षा अवसररचना, स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक लैब तथा उद्योग से जुड़े कौशल कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। शिक्षा और मेडिकल शिक्षा से जुड़े टीसीएस प्रवधानों को घटाकर 2% किए जाने से विदेशी मध्यम करने वाले मध्यम वर्गीय छात्रों को सीधी राहत मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल डिग्री उत्पादन नहीं, बल्कि रोजगार योग्य युवा तैयार करना है, ताकि जनसंख्या लाभार्थ वास्तविक आर्थिक शक्ति बन सके। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बजट में केंद्रीय स्थान मिला है। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण, बीमा और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने से महिलाओं की भागीदारी औपचारिक अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2026 संजीवनी जैसा है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का एमएसएमई प्रोथे फंड घोषित किया है, जिससे छोटे उद्योगों को सस्ता ऋण और विस्तार का अवसर भी मजबूत रहता है। कुल मिलाकर, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट घटाने का उद्देश्य केवल हिसाब संतुलित करना नहीं है, बल्कि भविष्य में विकास के लिए स्थायी और भरोसेमंद आर्थिक आधार तैयार करना है।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट को आय स्थिरता व जोखिम प्रबंधन का बजट कहा जा सकता है। सिंचाई परियोजनाओं, कृषि अवसररचना और वेयर हाउसिंग नेटवर्क के विस्तार से फसल नुकसान कम होगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी। एग्री-लॉजिस्टिक्स और कोल्ड-चेन पर निवेश बढ़ाकर कृषि उत्पादों की बर्बादी घटाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म और फसल बीमा कवरेज के विस्तार से किसानों की आय में स्थिरता आएगी। कृषि-आधारित एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्धन और रोजगार दोनों बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है।

कृषि-आधारित एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्धन और रोजगार दोनों बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है। छात्रों और युवा शक्ति के लिए यह बजट 'शिक्षा से रोजगार' की कड़ी को मजबूत करता है। डिजिटल शिक्षा अवसररचना, स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक लैब तथा उद्योग से जुड़े कौशल कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। शिक्षा और मेडिकल शिक्षा से जुड़े टीसीएस प्रवधानों को घटाकर 2% किए जाने से विदेशी मध्यम करने वाले मध्यम वर्गीय छात्रों को सीधी राहत मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल डिग्री उत्पादन नहीं, बल्कि रोजगार योग्य युवा तैयार करना है, ताकि जनसंख्या लाभार्थ वास्तविक आर्थिक शक्ति बन सके। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बजट में केंद्रीय स्थान मिला है। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण, बीमा और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने से महिलाओं की भागीदारी औपचारिक अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2026 संजीवनी जैसा है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का एमएसएमई प्रोथे फंड घोषित किया है, जिससे छोटे उद्योगों को सस्ता ऋण और विस्तार का अवसर भी मजबूत रहता है। कुल मिलाकर, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट घटाने का उद्देश्य केवल हिसाब संतुलित करना नहीं है, बल्कि भविष्य में विकास के लिए स्थायी और भरोसेमंद आर्थिक आधार तैयार करना है।

### आमने

खुद के ऊपर 14-14 मुकदमे हैं। उनमें जमानत करा लें। उनको सेंटल करा लें। सरकार से हाथ-जोड़ी करके। पौने तीन साल बाद में कांग्रेस की सरकार आ रही है। मदन दिलावर जी से मिलने जेल में मैं जाऊंगा। गोविंद डोटारसा तो यहीं रहेगा।

### सामने

कांग्रेस सरकार के दौरान मिड-डे मील योजना में करीब दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। जांच की आंच उन 'मगरमच्छों' तक पहुंचेगी, जिन्होंने जनता की कमाई पर डाका डाला। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का जाल बिछ चुका है।

कहीं नहीं जाएंगे।  
-मदन दिलावर  
-गोविंद सिंह डोटारसा : शिक्षा मंत्री  
कांग्रेस नेता, राजस्थान : राजस्थान सरकार

## सुप्रीम फैसले से प्राइवेट स्कूलों में बराबरी की बात

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब हर प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी अगर आपके पास साधन नहीं हैं, फिर भी आपका बच्चा महंगे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त पढ़ाई कर सकता है। हाल ही में शिक्षा के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम और दूरगामी फैसला सामने आया है। अदालत ने साफ कहा है कि सच्चा बंधुत्व तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ें। इसी सोच का मजबूत करते हुए शीप अदालत ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट और गैर-सरकारी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत मुफ्त सीटें सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गरीब बच्चों को प्रवेश देना 'एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए'।

आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून, पहली अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके तहत छह से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत यह हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो इसमें कोई भी स्कूल बच्चे को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता है। हर 60 बच्चों पर कम से कम दो प्रशिक्षित अध्यापकों का होना अनिवार्य है। हर तीन किलोमीटर के अंदर स्कूल होना

जरूरी है। राईट टू एजुकेशन पर होने वाले खर्चों का 55 प्रतिशत केंद्र और 45 प्रतिशत राज्य सरकार उठाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, देश के स्कूल शिक्षा तंत्र में 24.8 करोड़ से अधिक छात्र नामांकित हैं और प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर 96.9 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है।

कोर्ट ने कहा कि कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला केवल कागजी अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को स्पष्ट नियम बनाने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से जुड़े इस मामले में याचिकाकर्ता दिनेश बीवाजी अष्टिकर ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को पढ़ाई के निजी स्कूल में 25 फीसदी कोटे के तहत दाखिला नहीं मिला। आरटीआई से सामने आया कि सीटें खाली थीं, फिर भी स्कूल ने जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए राहत नहीं दी कि ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वर्षों की देरी के कारण बच्चों को समय पर राहत मिलना संभव नहीं रहा। इसके बावजूद अदालत ने इसे 'नजीर तय करने वाला' मामला मानते हुए व्यापक दिशा-निर्देश देने का फैसला किया। कोर्ट ने माना कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, भाषा की बाधा, डिजिटल आिदन प्रक्रिया और जानकारी की कमी के कारण गरीब परिवारों के लिए 25 फीसदी कोटे तक पहुंचना आज भी मुश्किल है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पढ़ाई के स्कूलों में दाखिला केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है। अदालत ने यह याद दिलाया कि निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के लिए 25

प्रतिशत सीटें आरक्षित करना कोई अलग कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) और 39 (एफ) में निहित बाल विकास और बंधुत्व के सिद्धांतों को लागू करने का जरिया है। शीप अदालत का कहना था कि आरटीई कानून सभी बच्चों को जाति, वर्ग, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना एक ही स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा देने की बात करता है। अदालत ने कोठारी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम पर जोर दिया गया था, जहां पर समाज के हर वर्ग के बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा मिल सके। संविधान के भाईचारे का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब एक रिकशा खींचने वाले का बच्चा, एक करोड़पति या सुप्रीम कोर्ट के जज के बच्चे के साथ एक ही स्कूल में पढ़े। शीप अदालत के इस फैसले को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषदों से सलाह लेकर, धारा 12(1)(सी) के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम और कानून तैयार करें और जारी करें। कोर्ट ने आगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियम और कानून जारी करने की जानकारी इकट्ठा करें और 31 मार्च तक कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।

### सोशल फोरम

## जिगर और नातिया मुशायरा

अजमेर में एक नातिया मुशायरा था। आयोजकों के सामने बड़ी मुश्किल थी कि जिगर मुरादाबादी को इस मुशायरे में कैसे बुलाया जाए। वे खुले रिंद (शराब पीने वाले) थे। नातिया मुशायरे में उनकी शिरकत आसान नहीं थी। आयोजकों में कुछ उनके हक में थे, कुछ खिलाफ। आखिर बहुत सोच-विचार के बाद आयोजकों ने फैसला किया कि जिगर को दावत दी जानी चाहिए। जब जिगर को बुलाया गया तो वे सिर से पांव तक कांप उठे।



हिस्ट्री अनफोल्ड  
लॉग

'मैं गुनहागर, रिंद, सियाहकार, बदनसीब और नातिया मुशायरा! नहीं साहब, नहीं।' अब आयोजकों के सामने यह समस्या थी कि जिगर साहब को कैसे तैयार किया जाए। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और होंठों से इनकार। आखिरकार असगर गोंडवी ने हुक्म दिया और जिगर खामोश हो गए। सिरहाने बातल रखी थी, उसे कहीं छिपा दिया। दोस्तों से कह दिया कि कोई उनके सामने शराब का नाम तक न ले। यह मौका मिला है तो मुझे इसे खोना नहीं चाहिए। शायद यह मेरी बख्शीश की शुरुआत हो। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा गए। नात के मजबून सोचते थे और ग़ज़ल कहने लगते थे। सोचते रहे, लिखते रहे, काटते रहे, लिखे हुए को काट-काट कर थकते रहे। आखिर एक दिन नात का मतला हो गया।

फिर एक शेर हुआ, फिर तो जैसे बारिश-ए-अनवार हो गई। नात मुकम्मल हुई तो उन्होंने सज्द-ए-शुक्र अदा किया। मुशायरे के लिए इस तरह रवाना हुए जैसे हज को जा रहे हों। उन्होंने कई दिनों से शराब नहीं पी थी, लेकिन हलक सूखा नहीं था। धरत तो यह हाल था, दूसरी तरफ मुशायरा-गाह के बाहर और शहर के चौराहों पर विरोध में पोस्टर लग गए थे कि एक शराबी से नात क्यों पढ़वाई जा रही है। आखिर मुशायरे की रात आ गई। जिगर को बड़ी सुरक्षा के साथ मुशायरे में पहुंचा दिया गया। मंच से आवाज़ उभरी- 'रईस-उल-मुताज़िज़लीन हज़रत जिगर मुरादाबादी!'

इस एलान के साथ ही एक शोर उठ खड़ा हुआ। जिगर ने बड़े धैर्य के साथ मंच को ओर देखा और प्रेम से भर स्वर में बोले, 'आप लोग मुझे हूट कर रहे हैं, या रासूल पाक की नात को, जिसे पढ़ने की सआदत मुझे मिलने वाली है और जिसे सुनने की सआदत से आप अपने आप को महरूम करना चाहते हैं?'

शोर को जैसे सांप सूंघ गया। बस यही वह विराम था, जब जिगर के टूटे हुए दिल से यह आवाज़ निकली-  
**एक रिंद है और मदावत-ए-सुल्तान-ए-मदीना हां, कोई नज़र-ए-रहमत-ए-सुल्तान-ए-मदीना**  
-फैसलबुक वाल से

### सामयिकी

## बेटियों का कागजी कवच और सामाजिक बेड़ियां

बेटियां घर की रौनक होती हैं। समाज की शक्ति होती हैं और राष्ट्र की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर भी देश की बेटियां समान अवसर, सुरक्षा एवं लैंगिक समानता की उपेक्षा का बोझ ढो रही हैं। सरकार ने बेटियों के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और कानून बनाए हैं, जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला आरक्षण विधेयक, पास्को एक्ट, घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाएं, जिनके माध्यम से बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। इन योजनाओं से कुछ सकारात्मक बदलाव भी दिखे हैं।

फिर भी, जमीनी हकीकत आज भी बहुत नहीं बदली है। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में लड़कियों की उन्नति दिखावा मात्र है। जिस समाज में हर रोज कोई लड़की या महिला बलात्कार का शिकार होती हो, उस समाज को प्रातिशील कहना, दोगलापन है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, देश में प्रतिदिन 81 रप के पुलिस केस दर्ज होते हैं। ये तो बस आंकड़े हैं, अधिकतर घटनाएं तो लोक-लाज के डर से परिवार और समाज द्वारा छिपा लिए जाते हैं।

जहां एक तरफ लड़कियों के लिए समान अवसरों की बातें तो बोली जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ घरेलू जिम्मेदारियां लड़कियों पर ही लाद दी जाती हैं। आज भी लड़कियों को खुद के सपने चुनने का अधिकार नहीं है और न ही स्वतंत्रता से कहीं आने-जाने की छूट ही मिलती है। साथ ही, रसोई और घरेलू कामों का बोझ शुरू से ही उनके कंधों पर डाल दिया जाता है। वास्तविकता में, लड़कियों को स्वतंत्रता और समान अवसर की सुविधाएं केवल मौखिक एवं कागजी स्तर पर ही सीमित रही है। वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कम है। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी है कि शिक्षा में आगे होने के बावजूद कई लड़कियां नौकरी या आगे की पढ़ाई छोड़ देती हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता, लैंगिक भेदभाव, असुरक्षा की भावना और कार्यभार पर भेदभाव जैसी चुनौतियां हर कदम पर उन्हें कमजोर करती हैं। आज भी लाखों लड़कियां शिक्षा और नौकरी के अवसरों से वंचित रह जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, सामाजिक एवं पारिवारिक सहयोग का प्राप्त न होना।

डिजिटल युग में साइबर हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न ने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। खुले आम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके चरित्र पर उदासियां उड़ाई जाती हैं और गालियां दी जा रही हैं। यह हिंसा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुंचाती है, बल्कि उन्हें ऑनलाइन स्पेस से दूर रहने, अपनी राय व्यक्त न करने या डिजिटल दुनिया से कट जाने पर मजबूर करने की साजिश है। यह क्रूर सच्चाई है कि जहां इंटरनेट ने महिलाओं को आवाज दी, शिक्षा दी और अवसर दिए, वहीं इस प्लेटफॉर्म का उनके खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बचपन से ही शिक्षा और घर-समुदाय स्तर पर हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। सही मायने में, देश की बेटियां की वास्तविक प्रगति तब होगी, जब कानून और योजनाएं सिर्फ घोषणाएं न रहें, बल्कि समाज की सोच बदलने, जमीनी सुरक्षा सुनिश्चित करने, घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ बांटने और हर बेटों को बराबरी का हक दिलाने में सक्षम बनें। हमारे देश को 'बेटी बचाव, बेटी पढ़ाओ' नारे की अपेक्षा 'समाज और परिवार में बेटियों के प्रति भेदभाव मिटाओ' नारे की ज्यादा ही जरूरत है।

# नई कार स्टेटस देती पुरानी कार समझदारी

**इसलिए बढ़ रहा है पुरानी कारों का बाजार**

देश में हर साल लाखों लोग पहली बार कार खरीदते हैं और उनमें से बड़ी संख्या सेकेंड हैंड या यूज्ड कार को प्राथमिकता देती है। इसके पीछे कारण हैं-

- नई कारों की बढ़ती कीमतें
- कम डाउन पेमेंट और आसान फाइनेंस
- डेप्रेसिएशन का कम झटका
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बढ़ती विश्वसनीयता
- सर्टिफाइड प्री-ओन्ड कार प्रोग्राम्स

**इन कारों की मांग सबसे अधिक**

बाजार के ट्रेंड पर नजर डालें, तो हैचबैक मारुति स्विफ्ट, वैनानआर, ग्रैंड आई-10 और सेडान में होंडा सिटी, मारुति सियाज, इसी तरह एसयूवी में क्रेटा, ब्रेजा, डस्टर आदि 5 से 7 साल पुरानी, कम चली और अच्छी तरह मेंटेड कारें सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं।



**पुरानी कारों की बिक्री नई कारों से ज्यादा**

भारत में पुरानी कारों की बिक्री नई कारों की तुलना में 8 से 10 फीसदी सालाना वृद्धि दर से बढ़ रही है। वर्तमान में प्रत्येक नई कार की बिक्री पर लगभग 1.4 पुरानी कारें बेची जा रही हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार साल 2026 के अंत तक भारत में इस्तेमाल की गई कारों की बिक्री 75 लाख यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है। यही नहीं इस साल देश में पुरानी कारों का बाजार 3.4 लाख करोड़ से अधिक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि पुरानी कारों के बाजार में हिस्सेदारी की बात करें, तो अभी भी सिक्का स्थानीय डीलरों और ब्रोकर का चलता है, जो बाजार के लगभग 68 फीसदी हिस्से पर काबिज हैं, लेकिन ग्राहकों का भरोसा अब वरंटी और सर्टिफाइड कारों के कारण तेजी से संगठित क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो रहा है। इस बदलाव से डिजिटल माध्यमों से होने वाली पुरानी कारों की बिक्री की हिस्सेदारी इस साल के अंत तक करीब 30 फीसदी पहुंचने की उम्मीद है।

**मारुति, टाटा, महिंद्रा के साथ ऑनलाइन स्टार्टअप्स ने जीता यूज्ड कार का भरोसा**

पुरानी कारों के संगठित कारोबार में मारुति सुजुकी True Value, महिंद्रा First Choice और टाटा मोटर्स Assured जैसे निर्माताओं के साथ Cars24, Spinny, CarDekho और Droom जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ और भी अनेक ऑनलाइन स्टार्टअप्स शामिल हैं। ये सभी सर्टिफाइड गाड़ियां खोजने, टेस्ट ड्राइव बुक करने और पूरी लेनदेन प्रक्रिया में मदद के अलावा अधिकतर कार के मूल्यांकन और कागजी कार्रवाई में भी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे पुरानी कार खरीदना आसान हो जाता है। इनमें Cars24 को पुरानी कारों की खरीद-बिक्री के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आप कार का मूल्यांकन, टेस्ट ड्राइव और पूरी कागजी कार्रवाई जैसे आरसी ट्रॉसफर, लोन आदि में मदद पा सकते हैं। Spinny भी एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, जो सर्टिफाइड और अच्छी क्वालिटी वाली पुरानी कारों को आसान और सुरक्षित तरीके से खरीदने का बेहतर अनुभव प्रदान कर रहा है। CarDekho पुरानी और नई दोनों तरह की कारों की पूरी जानकारी जैसे मॉडल, कीमत और माइलेज जैसी डिटेल्स प्रदान करता है। इसके मुकाबले Droom ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहां आप विभिन्न कारों की तुलना कर सकते हैं और कई विकल्प देख सकते हैं। इसी कड़ी में CarWale भी एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, जहां आपको पुरानी और नई कारों के डेर सारे विकल्प मिलते हैं। इनके अतिरिक्त OLX भी पुरानी कारों खरीदने और बेचने के लिए लोकप्रिय ऐप है, जिसमें आप सीधे विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं।

-मनोज त्रिपाठी, कानपुर



## Hero Vida Dirt .E K3: बच्चों के रोमांच को मिली इलेक्ट्रिक उड़ान

बदलते समय के साथ बच्चों की दुनिया भी स्मार्ट और टेक-फ्रेंडली हो रही है। इसी कड़ी में Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने भारत में बच्चों के लिए एक अनोखी और सुरक्षित इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक Dirt .EK3 पेश की है। यह बाइक न सिर्फ खेल-खेल में राइडिंग का मजा देती है, बल्कि सुरक्षा और सीखने, दोनों का पूरा ध्यान रखती है।



**कीमत और उपलब्धता**  
Vida Dirt .EK3 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 69,990 रखी गई है। पहले 300 यूनिट्स इसी कीमत पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यह बच्चों के लिए एक प्रीमियम, लेकिन समझदारी भरा विकल्प बनती है। इसकी बिक्री 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है।

**दमदार बैटरी**

Dirt .EK3 में 360 Wh की रिमूवेबल बैटरी और 500W मोटर दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा तक सीमित रखी गई है। बैटरी महज 2 घंटे में 20% से 80% तक चार्ज करने पर 2 से 3 घंटे तक राइड का मजा देती है। तीन राइडिंग मोड- Beginner, Amateur और Pro, बच्चों को धीरे-धीरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर देते हैं।

**सुरक्षा और स्मार्ट फीचर्स**

Vida ने सेफ्टी के मामले में कोई समझौता नहीं किया है। बाइक में मैग्नेटिक किल स्विच, चेस्ट पैड, ब्रेक रोटार कवर और रियर ग्रैबरेल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि एक मोबाइल ऐप के जरिए माता-पिता बच्चे की राइडिंग एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं, स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं और अन्य पैरामीटर्स नियंत्रित कर सकते हैं।

**इंटरनेशनल पहचान**

Dirt .E K3 का डिजाइन सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। इसे Red Dot Award 2025 दिया गया है, जो इसकी क्वालिटी और इनोवेशन का प्रमाण है। कुल मिलाकर, Hero Vida Dirt .EK3 बच्चों के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक राइडिंग अनुभव लेकर आई है, जहां रोमांच, सीख और सुरक्षा तीनों का खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है।

**बच्चों के साथ 'बढ़ने' वाली बाइक**

इस बाइक की सबसे खास बात है इसका एडजस्टेबल डिजाइन। व्हीलबेस और सस्पेंशन को तीन लेवल- Small, Medium और High पर सेट किया जा सकता है। यानी जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, बाइक भी उसके कद और उम्र के अनुसार ढलती जाएगी। इससे माता-पिता को हर कुछ साल में नई बाइक खरीदने की चिंता नहीं रहती।



## सर्दियों में क्यों 'नखरे' दिखाती है बाइक ?

**काम की बात**

सर्दियों की सुबह बाइक सवारों के लिए अक्सर एक परीक्षा बन जाती है। तापमान गिरते ही कई बाइक सेल्फ और किक दोनों पर सुस्त प्रतिक्रिया देने लगती हैं। बार-बार कोशिशों के बाद भी इंजन का स्टार्ट न होना न केवल समय की बर्बादी करता है, बल्कि बाइक की मैकेनिकल सेहत पर भी असर डालता है। ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठंड में बाइक स्टार्टिंग की समस्या पूरी तरह तकनीकी है और सही समझ के साथ इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है।

**ठंड का बाइक पर असर**

कम तापमान में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्रैकशाफ्ट और पिस्टन को घूमने में अधिक प्रतिरोध झेलना पड़ता है। दूसरी ओर, लोड-एंसिड बैटरी की केमिकल रिएक्शन क्षमता ठंड में कमजोर हो जाती है, जिससे सेल्फ स्टार्ट का आउटपुट घट जाता है। यही कारण है कि सर्दियों में सुबह के समय बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत करती है, जिससे बाइक सवार को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, खासकर उन वाहनों में जिनका मेटेनैस नियमित नहीं होता।

**स्टार्टिंग समस्या से निपटने के स्मार्ट तरीके**

- **स्पाईक प्लग की भूमिका अहम**- ठंड और नमी के कारण स्पाईक प्लग पर कार्बन डिपॉजिट या नमी जमा हो सकती है, जिससे स्पाईक कमजोर पड़ जाता है। यदि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले स्पाईक प्लग की जांच जरूरी है। प्लग को साफकर दोबारा फिट करने से करंट प्लो बेहतर होता है और इंजन आसानी से घात पकड़ता है।
- **क्लच ट्रिक से घटेगा लोड**- सर्दियों में गियरबॉक्स ऑयल भी गाढ़ा हो जाता है। बाइक को न्यूट्रल में रखकर क्लच पूरी तरह दबाने से गियरबॉक्स इंजन से अलग हो जाता है। इससे किक मारते समय इंजन पर कम लोड पड़ता है और स्टार्टिंग आसान हो जाती है।
- **चोक का सही और सीमित उपयोग**- कार्बोरेटर वाली बाइक में चोक ठंडे इंजन के लिए बेहद उपयोगी है। चोक खींचने से एयर-फ्यूल मिक्सचर रिच हो जाता है, जिससे इंजन जल्दी स्टार्ट होता है। हालांकि इंजन चालू होने के 20-30 सेकेंड बाद चोक बंद कर देना चाहिए, वरना फ्यूल कंजमेशन बढ़ सकता है।
- **इनिशन ऑफ रजक प्री-किक तकनीक**- ऑटो मैकेनिक्स के अनुसार, इनिशन बंद रजक पर 3-4 बार खाली किक मारने से सिलेंडर के भीतर गाढ़ा ऑयल फैल जाता है। इससे इंजन के मूविंग पार्ट्स लुब्रिकेट हो जाते हैं और स्टार्टिंग के समय कम प्रतिरोध पैदा होता है।
- **लगातार फेल स्टार्टिंग का नुकसान**- बार-बार सेल्फ मारने से बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है और स्टार्ट मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वहीं, ठंडे इंजन को जबरदस्ती स्टार्ट करने से पिस्टन और क्रैकशाफ्ट पर अनावश्यक घर्षण बढ़ता है, जिससे लंबे समय में इंजन की परफॉर्मंस प्रभावित हो सकती है।
- **एक्सपर्ट्स की मेटेनैस सलाह**- ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में बाइक को खुले में खड़ा करने से बचना चाहिए। कवर का इस्तेमाल बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नमी से सुरक्षित रखता है। साथ ही मौसम के अनुसार सही ग्रेड का इंजन ऑयल और समय-समय पर बैटरी हेल्थ चेक करना बेहद जरूरी है।
- **आने वाला कल**- ऑटो इंडस्ट्री ठंडे मौसम के लिए बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी और लो-विस्कॉसिटी इंजन ऑयल पर काम कर रही है। जब तक ये तकनीकें आम नहीं होतीं, तब तक सही ड्राइविंग हैबिट्स और बेसिक मेटेनैस से सर्दियों में बाइक स्टार्टिंग की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।



**मॉय फर्स्ट राइड**

## सासू मां के साथ मेरी आगे बढ़ने की यात्रा



जीवन में कुछ यात्राएं सड़कों पर तय होती हैं और कुछ हमारे मन और सोच के भीतर। मेरी कार सीखने की यात्रा भी ऐसी ही एक यात्रा रही, जो केवल ड्राइविंग सीखने तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और बदलाव को अपनाने की कहानी बन गई। 2024 में जब मेरी शादी तय हुई, तब तक मैं कार चलाना नहीं जानती थी। मायके में इसकी कभी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी थी, इसलिए यह कौशल मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन शादी के बाद ससुराल का वातावरण अलग था। यहां मेरी सासू मां और ननद दोनों कार चलाती थीं। घर से जुड़ा अधिकांश काम-चाहे फैक्ट्री जाना हो, कच्चा माल लाना हो या बाजार की खरीदारी-कार से ही पूरा होता था। ऐसे में मुझे यह समझ में आने लगा कि अब मुझे भी इस जिम्मेदारी में हाथ बंटाना होगा। कार सीखने का निर्णय लेना आसान था, लेकिन उसे सीखने की प्रक्रिया उतनी सरल नहीं थी। पहली बार स्ट्रीटिंग पकड़ते समय हाथ कांप रहे थे। सड़क पर निकलते ही मन में डर और असमंजस बना रहता था। ब्रेक, एक्सेलेरेटर और क्लच के बीच तालमेल बैठाने में समय लगा। कई बार छोटी-छोटी गलतियां हुईं, लेकिन हर बार सासू मां ने धैर्य और अपनापन

दिखाया। उनका विश्वास और सहयोग मेरे लिए सबसे बड़ा संबल बना। धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ा और डर कम होने लगा। सुबह की खाली सड़कों से शुरुआत हुई, फिर मोहल्ले की गलियों से होते हुए मैं मुख्य सड़क तक पहुंच पाई। समय के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। आज मैं अपनी सासू मां के साथ फैक्ट्री के कामों के लिए जाती हूँ और बाजार की जिम्मेदारियां भी निभाती हूँ। अब कार मेरे लिए केवल एक साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान बन गई है। इस पूरी यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। परिस्थितियां जब बदलती हैं, तो हमें भी अपने भीतर बदलाव लाना पड़ता है। परिवार का सहयोग और विश्वास किसी भी नई शुरुआत को आसान बना देता है। सासू मां के साथ मेरा रिश्ता इस दौरान और भी गहरा हुआ, क्योंकि हमने साथ-साथ सीखने और आगे बढ़ने का अनुभव साझा किया। आज जब मैं कार चलाती हूँ, तो मुझे सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती, बल्कि उस सफर का आनंद भी मिलता है, जिसने मुझे आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनाया। मेरी कार सीखने की यात्रा वास्तव में मेरे नए जीवन की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा बन चुकी है।

-अपर्णा, कानपुर

# डायरेक्ट बेनिफिट न मिलने से आमजन निराश, भाजपाई मगन

## आम बजट जानने को उत्सुक दिखे लोग, किसान हुए निराश, भाजपा कार्यालय में देखा गया बजट का सजीव प्रसारण

संवाददाता गोंडा

अमृत विचार : वित्तीय वर्ष 2026 का आम बजट रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। बजट को लेकर व्यापारियों, किसानों एवं महिलाओं में उत्साह रहा लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट न मिलने से लोग निराश नजर आए। वहीं भाजपा ने बजट को आमजन के लिए लाभकारी बताया है।

हालांकि एमएसएमई सेक्टर में छोटे व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके लिए बजट में 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को उम्मीद थी कि 6000 किसान निधि से बढ़कर 9000 हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। महिलाओं के किचन के सामान भी सस्ते होने की उम्मीद धूमिल हो गई। युवाओं के रोजगार पर बजट में कुछ खास नहीं दिखा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आम आदमी के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। कैसर से जुड़ी 17 दवाओं



आम बजट का लाइव प्रसारण देखते विद्यार्थ कप्रभात वर्मा व अन्य।

पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे ये दवाएँ सस्ती हो जाएंगी। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है, जिससे बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे और मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 रिजलन हब बनाए जाएंगे। लेदर आइटम, मोबाइल बैटरी, चमड़े के उत्पाद, सिंथेटिक फुटवियर, लिथियम आयन

सेल, सोलर ग्लास, मिक्सड गैस सोलरनजी ईवी, माइक्रोवेव ओवन, विमानों का ईंधन और विदेश यात्रा सस्ती होगी। छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को मजबूती देने के लिए 10,000 करोड़ का विशेष फंड बनाया गया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। टैक्स भरना आसान होगा और बेहतर सड़क, रेल और सुविधाएँ मिलेंगी। विद्यार्थ कप्रभात कुमार वर्मा ने अपने

विधानसभा क्षेत्र गौरा के सैदापुर स्थित आवास पर केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण देखा। विधायक ने कहा कि यह बजट जनकल्याण, आर्थिक सुदृढ़ता एवं समावेशी विकास को समर्पित है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ मिलेगा। भाजपा जिला कार्यालय केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण सुना गया। जिला संयोजक भाजपा अनुपम प्रकाश मिश्र ने बताया कि इस जनहितकारी बजट में भारत

### देशवासियों के लिए लाभकारी है बजट : पंकज



पंकज श्रीवास्तव, वरिष्ठ रेल परामर्शदात्री समिति के सदस्य।

गोंडा, अमृत विचार : पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आम बजट को जनहित में सराहनीय बताया, आम बजट देशवासियों के लिए बहुत ही लाभकारी है और रेल बजट में रेल यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों की सुखा के प्रति धन आवंटित किया गया है। इसी प्रकार रेल बजट में कोरोना काल से बंद वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को बहाल करते हुए कई हाई स्पीड रेल गाड़ियों के संचालन तथा बंदे भारत एवं अमृत भारत जैसी सभी सुविधाओं से परिपूर्ण नए एसी ट्रेनों को कई रूट चलाने पर जोर दिया गया है रेल बजट से सभी को लाभ होगा और सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी होगी।

वर्ष के समस्त पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए तथा शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए तथा छात्र और छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत ही जनहित व्यवस्था किया गया है। कैसर तथा मधुमेह जैसी बीमारियों में काम आने वाली दवाइयों को सस्ता किया गया है। पूर्व जिला अध्यक्ष इकबाल बहादुर तिवारी, निवर्तमान

जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी, केके श्रीवास्तव, राजा बाबू गुप्ता, आशीष त्रिपाठी, राकेश तिवारी, राजेश राय चंदानी, नीरज मौय्य, विवेक श्रीवास्तव, पंडित श्रीकांत पांडे, विद्याभूषण द्विवेदी, नंदकिशोर, नंदू चौरसिया, बीना राय राजभर, बबलू मौय्य, अरविंद पाठक, आशीष मोहनवाल, धर्मवीर शुक्ला, सुषमा श्रीवास्तव, श्याम सुंदर मौय्य, अभिषेक तिवारी, मनीष द्विवेदी आदि मौजूद थे।

### न्यूज झीफ

#### घर में घुसकर हमला चार लोग घायल

नवाबगंज, गोंडा, अमृत विचार : तुलसीपुर माझा में रविवार को जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक घटना में एक ही परिवार के चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विजय कुमार यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका अरविंद से जमीनी विवाद चल रहा है। बीते शुक्रवार को नवाबगंज थाने पर दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। इसके बावजूद रविवार को 11:30 बजे विपक्षीय गैरों की मेड़ काटते हुए टटिया उजाड़कर जबरन उनके घर में घुस आए।

#### गैंगस्टर एक्ट का वांछित गिरफ्तार

गोंडा, अमृत विचार : पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित गिरफ्तार किया है। थाना वजीरगंज में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार को लाल ब्रदर्स पेट्रोल पम्प अकबरपुर के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

#### ट्रेक के किनारे मिला अज्ञात युवक का शव

नवाबगंज, गोंडा, अमृत विचार : मनकापुर-अयोध्या रेलवे ट्रैक पर पर्वती गांव के पास रविवार की शाम एक अज्ञात युवक का शव मिला। उम्र करीब 30 वर्ष है। किसी चलती ट्रेन से गिरने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, रविवार सायं लगभग 4-15 बजे कुछ लोग रेलवे लाइन के किनारे गए थे, तभी उनकी नजर ट्रैक के किनारे पड़े युवक पर पड़ी। पुलिस के अनुसार, युवक की मौत ट्रेन से गिरने के कारण होने की संभावना है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

## टावर पर चोरी का किया खुलासा, तीन गिरफ्तार

गोंडा, अमृत विचार : नगर कोतवाली पुलिस टीम ने टेलीकॉम टावर से हुई चोरी की घटना का अनावरण करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से चोरी किया गया आरआरयू, बीबीयू तथा घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार पंकज कुमार सिंह, सुरक्षा अधिकारी निशा सेवा सुरक्षा कंपनी, इंडस टावर ने तहरीर देकर बताया था कि 28 जनवरी को स्टेशन

रोड स्थित डॉ. एस.एन. ओझा गली, छेदीपुरवा में लगे एयरटेल टावर से अज्ञात चोर आरआरयू व बीबीयू चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने सूचना पर मिश्रलिया ओवरब्रिज के पास डीजल डिपो के पीछे से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में आलोक पाण्डेय, प्रदीप तिवारी व छोटकनू शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटना स्वीकार की। बरामद सामान की शिनाख्त कराई गई।

## प्रांतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मुरादाबाद का दबदबा

गौरा चौकी, गोंडा, अमृत विचार: प्रधान स्पोर्टिंग क्लब परसौना के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय प्रांतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन फाइनल मुकाबले से पहले तक मुरादाबाद की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने तीनों मैच जीतकर प्रतियोगिता में बढ़त बना ली।

बनभोजत के परसौना औराडीह में चल रही इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन शाहपुर नवादा ने अमर डोभा को, एशिया इमरजेंसी ने आजमगढ़ को हराया। मुरादाबाद और मुगलसराय की बीच हुए मुकाबले में मुरादाबाद ने जीत दर्ज की समापन समारोह में



खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर प्रतियोगिता शुरू कराते सपा नेता हाफिज मलिक।

मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हाफिज मलिक ने फाइनल विजेता टीम को 10,000 रुपये तथा उपविजेता टीम को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। वहीं प्रांतीय

वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अध्यक्ष हाजी यूसुफ चौधरी ने विजेता टीम को 30,000 रुपये और उपविजेता टीम को 20,000 रुपये देने की घोषणा की। फाइनल मुकाबला रात्रि में खेला

जाएगा। परवेज अहमद ने इसी वर्ष सादुल्लाह नगर में प्रांतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित कराने की घोषणा की, जबकि समाजवादी नेता अब्दुल हफीज मलिक ने अगले वर्ष प्रांतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराने की घोषणा की। कार्यक्रम में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अध्यक्ष हाजी यूसुफ चौधरी, मुख्य अतिथि हाफिज मलिक, आयोजक प्रधान अब्दुल गफफार चौधरी, लतीफ मलिक, अयूब चौधरी, मनव्वर हुसैन चौधरी, मिनहाज, अब्दुल सलाम, मोहम्मद अफजल सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

### किया याद

### श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ मनायी जयंती, संत की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण

## संत रविदास जयंती पर निकली शोभायात्रा का पुष्पवर्षा से स्वागत



संत रविदास की जयंती पर शोभायात्रा निकालते लोग।

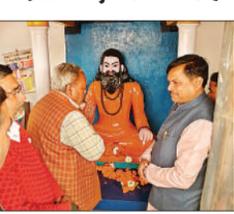
● अमृत विचार

गोंडा, अमृत विचार: संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर गोंडा नगर में शोभायात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभायात्रा इमामबाड़ा छावनी एवं शास्त्री नगर मोहल्ले से निकाली गई। श्रद्धालुओं ने फूलों से सुसज्जित संत रविदास की मूर्ति को सजाया था। महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी आस्था का केंद्र रही। सायं लगभग 4 बजे इमामबाड़ा मोहल्ले से शोभायात्रा प्रारंभ हुई, जो कुछ दूर चलने के बाद शास्त्री नगर मोहल्ले की शोभायात्रा के साथ सम्मिलित हो गई। इसके पश्चात संयुक्त शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पीपल

चौराहे पर पहुंची। पीपल चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक राकेश वर्मा गुड्डू के नेतृत्व में संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। श्रद्धालुओं को मिष्ठान्न वितरित किया गया। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक राकेश वर्मा गुड्डू ने कहा कि संत रविदास जी संत शिरोमणि थे। इस मौके पर अमित गौतम, विनोद गौतम, मुकेश गौतम, भरत गिरि, बबलू वर्मा, कमल बाबा, आशीष मोहनवाल, आनंद वर्मा, विजय वर्मा, राजेंद्र सिंह, अर्जुन बजरंगी, संदीप शास्त्री आदि थे।

### संत रविदास ने समाज को दिखायी एकता की राह

गोंडा, अमृत विचार : संत रविदास जयंती पर रविवार को साहबगंज बड़ागांव स्थित संत रविदास मंदिर परिसर में भाजपा एवं मंदिर व्यवस्थापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता केके श्रीवास्तव ने कहा कि संत रविदास ने समाज को भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता और एकता का मार्ग दिखाया। प्रभाकर त्यागी, नीलम त्यागी, रामकुमार राव, सूज कुमार गौतम की सक्रिय भूमिका रही। इस मौके पर अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष नंदकिशोर 'नंद', भाजपा जिला महामंत्री राकेश तिवारी, बंद प्रकाश बाबु शुक्ला, अभिषेक दत्त त्रिपाठी, अरुण कुमार, सचिन वाल्मीकि, जगुन जायसवाल आदि थे।



संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते लोग।

संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते लोग।

### कलश यात्रा के साथ हुआ महायज्ञ का शुभारंभ



कलश यात्रा में शामिल लोग।

● अमृत विचार

गोंडा, अमृत विचार : विलविला खतीपुर मजरा शुवलनपुरवा में महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। आयोजन याज्ञिक अंजनी शरण शास्त्री महाराज के नेतृत्व में किया जा रहा है। अयोध्या से पहले पंकज शास्त्री, रसिक जी महाराज, मनमोहनचौधरी, अशोकानंद तथा यज्ञाचार्य पंडित हरिओम शरण शास्त्री द्वारा प्रवचन किए जाएंगे। महायज्ञ के शुभारंभ पर रविवार को श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। कार्यक्रम 1 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा, जबकि 9 फरवरी को सामूहिक हवन एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान रघुनाथ शुक्ला, परमानंद शुक्ला, चौधरी शुक्ला, सुशील शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, भूरू शुक्ला, दरोगा शुक्ला, अर्जुन शुक्ला आदि थे।

### पालिका के दो कर्मचारी सेवानिवृत्त, दी विदाई



सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई देते कर्मचारी व सभासद।

● अमृत विचार

गोंडा, अमृत विचार : पालिका में कार्यरत ड्राइवर रामचंद्र तथा कर लिपिक जैनेंद्र तिवारी के सेवानिवृत्त होने विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सभासदों ने दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवकाल की सराहना की। अध्यक्षता ईओ एवं एसडीएम द्वितीय विशाल कुमार ने की। इस मौके पर कर निर्धारण अधिकारी रत्नेश यादव, दिलीप कनौजिया, काजी हाशिम रसूल, फराज अहमद, अनिल सिंह, रामजन्म मिश्रा, नितेश राठौर, राहुल श्रीवास्तव, वेद श्रीवास्तव, सुधीर श्रीवास्तव सहित सभासद फहीम सिद्दीकी, शाहिद अली कुरेशी, ताहिर अहमद, रिजवान खान, रबू खान, मनोज कश्यप, जतिन श्रीवास्तव, संतोष यादव, अभिषेक कनौजिया एवं अशफाक अहमद उपस्थित रहे।

### एंटी रोमियो स्कॉयड ने चलाया जागरूकता अभियान



महिलाओं व बेटियों को जागरूक करती महिला पुलिस।

● अमृत विचार

गोंडा, अमृत विचार : ए एंटी रोमियो स्कॉयड टीमों एवं राजप्रति अधिकारियों ने गांवों, कस्बों तथा सार्वजनिक स्थलों पर चोला लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया। महिलाओं, बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण, आत्मरक्षा के उपाय, साइबर अपराध से बचाव तथा कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की जानकारी दी गई। महिला पुलिसकर्मियों ने उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं की व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके आवागमन के दौरान होने वाली संभावित परिस्थितियों पर चर्चा कर समाधान के प्रति आश्वस्त किया। पुलिस आयातकालीन सेवा 112, दुर्मेन पावर हेल्पलाइन 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, एंबुलेंस सेवा 108, साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं स्वास्थ्य सेवा 102 की जानकारी साझा की गई।

### एबीवीपी ने आयोजित की युवा संवाद संगोष्ठी



स्कूल के बच्चों को संबोधित करते विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी।

● अमृत विचार

करनेलगंज, अमृत विचार : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पीएस इंटर कॉलेज में की युवा संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता प्रभात सह मंत्री मुकेश सोनी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को राष्ट्रनिर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। वहीं संघ के विभागाध्यक्ष प्रमुख रूपानारायण सिंह ने पंच परिवर्तन विषय पर छात्रों से संवाद किया। प्रधानाचार्य डीपी सिंह ने आभार जताया। मंच संवादन संयोजक रामानन्द मिश्रा ने किया। तरबंगाने तहसील संयोजक अन्तरिक्ष त्रिपाठी, करनेलगंज के कार्यकर्ता अशु मिश्रा, गुनगुन, उमेश आदि थे।

### पानी का पैसा मांगने पर दुकानदार को रॉड से पीटा

नवाबगंज, गोंडा, अमृत विचार : बर्दई पुरवा (मिशन स्कूल) निवासी पंकज के साथ दुबंगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार उसकी दुकान कटी तिराहे के पास है। पीड़ित ने शान में दी तहरीर में बताया कि बीती 29 जनवरी की रात लगभग 9 बजे तीन अज्ञात युवक उसकी दुकान पर आए और पानी की बोतल खरीदी। जब पंकज ने बोतल के पैसों मांगे तो दुबंगों ने लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे उसके साले सुमित और भाई राजेश को भी हमलावरों ने पीटा। लोगों के एकत्र होने पर आरोपी फरार हो गए। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि पनसीआर दर्ज कर ली गई है। दौषियों की पहचान कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

### जहां से हटाई गई, फिर वहीं लौटीं स्टाफ नर्स

करनेलगंज, अमृत विचार : सीएससी करनेलगंज से गंभीर आरोपों के चलते हटाई गई स्टाफ नर्स संस्था गुप्ता की उसी केंद्र पर दोबारा तैनाती ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छह माह पहले उन पर प्रस्तुत का बाथरूम में प्रसव कराने, बाहर से दवाइयों मांगने और अभद्र व्यवहार के आरोप लगे थे। जांच में आरोप सही पाए जाने पर उनका तबादला सीएससी काजीदेवर कर दिया गया था। इसकी आख्या जिलाधिकारी ने 19 सितंबर 2025 को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को भेजी थी। अब अचानक करनेलगंज में उनकी वापसी हो गई। सीएमओ संत पटेल ने बताया कि यह स्थानांतरण अनभिज्ञतावश हुआ है। आरोपों की जानकारी अधीक्षक द्वारा नहीं दी गई थी, इसलिए नियमित प्रक्रिया में तैनाती हो गई।

### संदिग्ध दशा में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव

गौरा चौकी, गोंडा, अमृत विचार : खोडोत्रे के लक्ष्मी नगर ग्रांट गांव में रविवार सुबह नदी किनारे एक पेड़ से 24 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता मिला। मुक्त की पहचान लक्ष्मी नगर ग्रांट निवासी दुर्गा कुमार पुत्र रामहित के रूप में हुई है। दुर्गाश राजगौर मिस्त्री था। शनिवार को वह काम करने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। रविवार सुबह ग्रामीणों ने लक्ष्मी नगर ग्रांट के पास नदी किनारे एक पेड़ पर उरका से शव लटकता देखा। थानाध्यक्ष चशवंत सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच की जा रही है।

### प्रसव को आंशिक सहायता को निजी अस्पताल ले गए दलाल

कटरा बाजार, गोंडा, अमृत विचार : गंभवती को बिना अनुमति आशा के सहयोग से निजी अस्पताल ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। अधीक्षक डॉ इंद्र राणा ने इस संबंध में आशा से स्पष्टीकरण मांगते हुए सीएमओ को पत्र भेजा है। अधीक्षक ने बताया कि 30 जनवरी को एक गर्भवती को प्रसव के लिए सीएससी लाया गया था। आशा बीना की मिलीभगत से गोंडा कटरा मार्ग पर स्थित अलशिफा सुपर स्पेशियलिटी सेंटर के स्टाफ ने निजी वाहन से उसे अपने अस्पताल ले जाया गया था।

## न्यूज़ ब्रीफ

## स्वास्थ्य मेलों में 1693 मरीजों को मिला निःशुल्क उपचार

बलरामपुर अमृत विचार : जनपद के सभी 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में कुल 1693 मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया। इनमें 789 पुरुष, 756 महिलाएं एवं 148 बच्चे शामिल रहे। स्वास्थ्य मेलों में सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के साथ बीपी, शुगर, टीबी, कुष्ठ, नेत्र व दंत रोगों की जांच, गर्भवती महिलाओं की एनपी सी जांच, शिशु एवं विधायक केलाश नाथ शुक्ला की निरीक्षण किया गया। साथ ही विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महदेइया पहुंचकर मले का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

## सात गौशालाएं बंद, पशु अन्य केंद्रों में शिफ्ट

बलरामपुर अमृत विचार : जिले में ऐसी सात गौशालाएं विन्धित की गई हैं जहां 30 से कम पशु संरक्षित हैं। पशुओं की समुचित देखभाल और संसाधनों के बेहतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इन गौशालाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन गौशालाओं में संरक्षित पशुओं को नजदीकी अन्य गौशालाओं में स्थानांतरित कराया जाए ताकि उनकी देखभाल सुचारु रूप से हो सके।

## बचपन डे-केयर सेंटर में दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण शुरू

बलरामपुर अमृत विचार : दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में बचपन डे-केयर सेंटर का संचालन शुरू किया गया है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी तनुज त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे दिव्यांग बच्चों जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है, उनके अभिभावक अपने बच्चों का पंजीकरण संबंधित सेंटर पर करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों का प्रवेश प्रथम आवक, प्रथम पाक के आधार पर किया जा रहा है। इस पहल से दिव्यांग बच्चों को अनुकूल वातावरण में शिक्षा और विकास के अवसर मिल सकेंगे।

## चलती ट्रेन में यात्री पर पत्थर लगने से मचा हड़कंप

नवाबगंज, गोंडा, अमृत विचार : चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है, जिसने रेलवे सुरक्षा और लापरवाही दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि पत्थर किसी बच्चे ने खेल-खेल में फेंका होगा, लेकिन चलती ट्रेन की रफ्तार में यह घटना किसी की जान भी ले सकती थी। गोंडा के मुन्नन खां चौराहा निवासी जिया उल हक (43) रविवार को लखनऊ से ट्रेन से लौट रहे थे। अयोध्या से मनकापुर के बीच दोपहर करीब दो बजे वह ट्रेन में खिड़की के पास बैठे थे। इसी दौरान नवाबगंज स्टेशन से लगभग एक किलोमिटर पहले अचानक एक पत्थर उनके सिर में आ लगा।

पत्थर लगते ही उनका सिर फट गया। घायल यात्री को देखकर पास ही बैठी एक महिला यात्री ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उनकी मदद ककी जिससे जिससे खून का बहाव

## प्रतिक्रिया

संवाददाता, बलरामपुर

अमृत विचार : केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट में महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय वृद्धि, युवाओं के रोजगार और देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट को समावेशी विकास की दिशा में एक संतुलित प्रयास माना जा रहा है, जिसमें समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की योजना है। यह कहना है जिले के भाजपा विधायक पल्लूराम, केलाश नाथ शुक्ला व राम प्रताप वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा तथा नगर पालिका बलरामपुर अध्यक्ष



पल्लूराम।



केलाश नाथ शुक्ला।



राम प्रताप वर्मा।



रवि मिश्रा।



डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू।

डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू का। इन लोगों ने बताया कि महिलाओं के लिए बजट में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और कौशल विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में

मदद मिलेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसानों के हित में कृषि अवसंरचना, सिंचाई परियोजनाओं और फसल बीमा योजनाओं को मजबूती देने की घोषणा की गई है। प्राकृतिक खेती, डिजिटल कृषि सेवाओं और किसान क्रेडिट सुविधाओं के विस्तार से किसानों

की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण सड़कों और बंजारण सुविधाओं में निवेश से कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार मिलने की उम्मीद है। युवाओं के लिए बजट में रोजगार सृजन, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के विशेष प्रावधान किए गए हैं। इससे

युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं सीमावर्ती सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बजट में बड़ोतरी की गई है। बजट महिला, किसान, युवा और राष्ट्र सुरक्षा को केंद्र में रखकर देश के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम माना जा रहा है।

## छात्रों का 1500 रुपये लेकर नकल कराने का आरोप

## परीक्षा केंद्र पर किया हंगामा, मौके पर पहुंचे अधिकारी

पचपेड़वा बलरामपुर

अमृत विचार : राजकीय महाविद्यालय पचपेड़वा में उस समय हंगामा मच गया जब सीता शरण महाविद्यालय जैतापुर और फातिमा डिग्री कॉलेज डालपुर बकौली के छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर तैनात कुछ निरीक्षकों/शिक्षकों पर प्रति छात्र 1500 रुपये लेकर नकल कराने का गंभीर आरोप लगाया। उक्त दोनों महाविद्यालयों का परीक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय पचपेड़वा में था, जहां लगभग 450 छात्र-छात्राएं परीक्षा दे रहे थे। इसी केंद्र पर राजकीय महाविद्यालय पचपेड़वा के छात्र भी परीक्षा दे रहे थे।

छात्रों का आरोप है कि उनसे यह कहकर 1500 वसूले गए कि सभी को नकल कराई जाएगी और पास करा दिया जाएगा। जब परीक्षा के दिन नकल नहीं कराई गई तो छात्रों ने अपने पैसे चापस मांगने शुरू किए। आरोप है कि पैसा लौटाने से इनकार किया गया और कुछ



आरोप लगाने वाले छात्रों से पूछताछ करते प्रशासनिक अधिकारी। ● अमृत विचार

शिक्षकों द्वारा डराने-धमकाने के साथ ही एफआईआर कराने की धमकी दी गई। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक और शीशा तोड़ने का आरोप उन पर मढ़ा गया। सीता शरण महाविद्यालय के पीयूष दुबे, सूरज दुबे, सूरज कश्यप, रिजवान, अजीत पाल, सतीश मिश्रा, दीपक यादव, मनोज सहित दर्जनों छात्रों ने उपजिलाधिकारी तुलसीपुर को पत्र देकर शिकायत की। सूचना पर तहसीलदार योगेंद्र शरण शाह व प्रभारी निरीक्षक ओम

प्रकाश चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों व प्राचार्य से पूछताछ की। छात्रों ने अभिषेक कुमार अग्रहरी व सुनील कुमार के खातों में पैसे ट्रान्स्फर करने के साक्ष्य भी दिखाए। प्राचार्य डॉ. शरद चौधरी ने नकल से साफ इनकार करते हुए कहा कि केंद्र पर सीसीटीवी लगे हैं और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। तहसीलदार ने भी जांच के बाद दोषियों पर एफआईआर व सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

## मतदाता पुनरीक्षण शिविर में उमड़ी भीड़

बलरामपुर, अमृत विचार : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा बलरामपुर की मतदाता सूची को अद्यतन करने के उद्देश्य से विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डीएवी इंटर कॉलेज एवं महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे, वहीं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवक-युवतियों को नए मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया।

डीएवी इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम कटने, त्रुटि सुधार एवं निवास परिवर्तन से संबंधित समस्याएं प्रमुख रहीं। मोहल्ला अलीजानपुरवा निवासी रामा, मोती सागर के राजीव

गुलाठी, तुलसीपाक के दीपक उपाध्याय एवं नौशहरा निवासी इकबाल ने नाम से जुड़ी विभिन्न त्रुटियों की शिकायत दर्ज कराई। वहीं महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज में पहुंचे मतदाताओं ने भी फार्म प्राप्त कर सुधार की प्रक्रिया शुरू कराई।

शिविर के दौरान सुपरवाइजर लेखपाल अनिल कुमार, प्रशांत वर्मा एवं राहुल कुमार वर्मा ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया और लोगों को फार्म-6 व फार्म-8 भरने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता अजय सिंह पिंकू, झूमा सिंह, सपा नेता कृष्ण कुमार गिहार सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी बीएलओ मतदाताओं की समस्याओं के निस्तारण में सक्रिय रहे।



मतदाता पुनरीक्षण शिविर में मौजूद मतदाता व अन्य लोग। ● अमृत विचार

## एसटीएफ के हथिये चढ़ा 50 हजार का इनामी

गोंडा, अमृत विचार : लखनऊ एसटीएफ की टीम ने 50 हजार के इनामी शांति गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त थाना धानेपुर में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। लखनऊ एसटीएफ की टीम ने थाना धानेपुर में दर्ज मुकदमा यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त आकाश यादव, निवासी डेबरीकला थाना धानेपुर, गोंडा को कटरा रेलवे स्टेशन के सामने से दबोच लिया। आरोपी की गिरफ्तारी पर देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार आकाश सक्रिय आपराधिक गिरोह का सरगना है, जो अपने साथियों सुमित तिवारी, संदीप मोर्या, आदित्य कश्यप व हरतू कश्यप के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह द्वारा बाइक सवारों को निशाना बनाकर आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की कई घटनाएं की गईं।

## चौक के सौंदर्यीकरण का शुभारंभ



घंटाघर निर्माण के लिए भूमि पूजन करते नगरपालिका अध्यक्ष व अन्य। ● अमृत विचार

संवाददाता, बलरामपुर अमृत विचार : ऐतिहासिक चौक-चौराहे के सौंदर्यीकरण एवं घंटाघर निर्माण कार्य का भूमि पूजन समन्वयन हुआ। पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने मंत्रोच्चार के बीच परीक्षण एक बार फिर शुरू हो गया। यह परियोजना नगर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करते

हुए उसे आधुनिक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। भूमि पूजन कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी लाल चंद्र मोर्या, अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस, सभासदगण, व्यापारी संगठन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा, कृष्णगोपाल गुप्ता, संजय शुक्ला, प्रवीण सिंह,

शिव कुमार द्विवेदी सहित अनेक गगनमान्यजनों ने सहभागिता निभाई। पालिका के तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने कहा कि नगर का यह प्राचीन चौक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसके सौंदर्यीकरण और घंटाघर निर्माण से नगर की सुंदरता बढ़ेगी।

## फैसला

## 210 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगेंगे आरओ कूलर

गोंडा, कार्यालय

अमृत विचार : जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर नौनिहालों को शुद्ध, स्वच्छ और ठंडा पेयजल मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिले के 210 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आरओ वाटर कूलर लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। इस पहल से छोटे बच्चों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को भी स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिलेगी, जिससे जलजनित बीमारियों में कमी आने की उम्मीद है।

जनपद में कुल 3095 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें लगभग 2.58 लाख लाभार्थी पंजीकृत हैं। इन केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण आहार, प्रारंभिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल के लिए केवल इंडिया मार्क हैंडपंप पर निर्भर रहना पड़ता है। कई स्थानों पर जल की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं, जबकि



आंगनबाड़ी केंद्र। ● अमृत विचार

कुछ केंद्रों को पास के विद्यालयों या अन्य संस्थानों के जल संसाधनों का सहारा लेना पड़ता है। विभागीय जानकारी के अनुसार उन केंद्रों को प्राथमिकता दी गई है, जहां बच्चों की संख्या अधिक है और पेयजल की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। आरओ वाटर कूलर की स्थापना के साथ-साथ उनकी नियमित देखरेख और

रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, ताकि उपकरण लंबे समय तक सुचारु रूप से कार्य करते रहें। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आरओ वाटर कूलर लगाने से बच्चों को स्वच्छ और ठंडा पानी मिलेगा, जिससे गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। चिकित्सकों के अनुसार शुद्ध पेयजल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अधिकारियों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की यह पहल सरकार की सकारात्मक सोच को दर्शाती है। भविष्य में शेष आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिले के सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरओ वाटर कूलर लगाए जाएंगे। प्रथम चरण में 210 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए शासन द्वारा कार्यवाही संस्था नामित कर दी गई है।

## सवा शेर की नहीं बुझ रही प्यास, शेर की हो रही तलाश

राकेश सिंह, बलरामपुर

अमृत विचार : चंपक वन की रानी शेरनी के चाचा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। वह अपनी बीट में रहकर वन्य जीवों की सेवा में जुट गया। अधिकतर समय वन्य जीवों के साथ गुजारने लगा। अंधे वन्यजीवों का नेत्र परीक्षण एक बार फिर शुरू हो गया। वन्य जीवों के आंखों की रोशनी वापस आने लगी। चुनाव लड़ने के इच्छुक वन्य जीव अपनी गाड़ियों पर चंपक वन पर पड़ना तय था। लेकिन तेंदुए की कंगाली की वजह व जेल जाने की डर से वह जाती तो लोग हाल-चाल पूछने पहुंच जाते। जिनके दर्शन पांच साल तक नहीं हुए थे वह वन्य जीवों के सामने दांत चियारने लगे। वन्य जीवों के पूछने पर कहते कि व्यस्तता होने के कारण वह पांच साल तक इलाके में नहीं हो सके। विकास की बात पूछने



को जंगल की बड़ी कुर्सी दिखाई पड़ रही थी। उधर तेंदुए की रिहाई का असर भी चुनाव पर पड़ना तय था। लेकिन तेंदुए की कंगाली की वजह व जेल जाने की डर से वह जाती तो लोग हाल-चाल पूछने पहुंच जाते। जिनके दर्शन पांच साल तक नहीं हुए थे वह वन्य जीवों के सामने दांत चियारने लगे। वन्य जीवों के पूछने पर कहते कि व्यस्तता होने के कारण वह पांच साल तक इलाके में नहीं हो सके। विकास की बात पूछने

पर चेहरे से हसी गायब हो जाती। वन्य जीवों के नेता कहते कि क्या करें पांच साल तक कमीशन इतना भारी भरकम रहा की उसे निपटारे निपटारे ही समय समाप्त हो गया। सारा माल बबर शेर के खाते में चला गया। चंपक वन की रानी के चाचा के खाते में जो भी घन आया वह दान पुण्य में चला गया। घर की पूंजी भी गवानी पड़ी। बड़े-बड़े दिग्गजों को जंगल की बड़ी कुर्सी दिखाई पड़ रही थी। उधर तेंदुए की रिहाई का असर भी चुनाव पर पड़ना तय था। लेकिन तेंदुए की कंगाली की वजह व जेल जाने की डर से वह जाती तो लोग हाल-चाल पूछने पहुंच जाते। जिनके दर्शन पांच साल तक नहीं हुए थे वह वन्य जीवों के सामने दांत चियारने लगे। वन्य जीवों के पूछने पर कहते कि व्यस्तता होने के कारण वह पांच साल तक इलाके में नहीं हो सके। विकास की बात पूछने

## वार्षिकोत्सव में बच्चों की प्रस्तुतियों ने मोहा मन



उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्रा को पुरस्कृत करते अतिथि। ● अमृत विचार

बलरामपुर अमृत विचार : पायनियर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, कालीथान में पुरस्कार वितरण समारोह एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। शुभारंभ विद्यालय प्रबंधन एवं मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन व पुष्प अर्पण से हुआ। विद्यालय परिवार द्वारा मुख्य अतिथि विधायक पल्लूराम, पूर्व सांसद दहने मिश्रा एवं विधायक केलाश नाथ शुक्ला व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्याम मनोहर तिवारी सहित सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया गया। नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दर्शकों का मन मोह लिया। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नर्सरी से कक्षा 12 तक के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। शिक्षकों, कर्मचारियों को भी लिए पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉ. एमपी तिवारी ने अतिथियों का आभार जताया।

## शिक्षा ही आत्मनिर्भरता की कुंजी है



वार्षिकोत्सव के दौरान मौजूद कॉलेज की छात्राएं व शिक्षिकाएं। ● अमृत विचार

उत्तरीला, बलरामपुर, अमृत विचार : राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव सम्पन्न हुआ। शुभारंभ मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार प्रतिमा मोर्या ने किया। विद्यालय परिवार ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। शैक्षणिक सत्र के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रतिमा मोर्या ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही आत्मनिर्भरता की कुंजी है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली छात्राओं को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

## बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया का जन्मदिन 13 मार्च को पर्व के रूप में मनाने का लिया गया निर्णय



तेयारी बैठक में मौजूद चौरसिया समाज के लोग। ● अमृत विचार

उत्तरीला, बलरामपुर अमृत विचार : फक्कड़दास मंदिर के पास आयोजित चौरसिया समाज की जागरूकता गोष्ठी में बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया का जन्मदिन 13 मार्च को पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. बी. आर. चौरसिया ने कहा कि बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया का जन्म 13 मार्च 1903 को हुआ था तथा 18 सितंबर 1995 को उनका स्वर्गवास हुआ। वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और सामाजिक न्याय के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। लोक अदालत की स्थापना में अहम भूमिका निभाने के कारण उन्हें लोक अदालत का जनक माना जाता है। गोष्ठी में धर्मवीर चौरसिया ने समाज के उत्थान के लिए उच्च शिक्षा को आवश्यक बताया। अशोक चौरसिया ने बाबू जी के सम्मान में स्मृति द्वार निर्माण की लंबित मांग उठाई। डॉ. विकास चौरसिया व दीपक चौरसिया ने कहा कि बाबूजी के नाम का स्मृति द्वार गौरव का विषय होगा और इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे।

## सपा नेता अर्जुन गोस्वामी के पिता का निधन

कटरा बाजार, गोंडा, अमृत विचार : सपा नेता व पूर्व प्रधान अर्जुन प्रसाद गोस्वामी के पिता दुखी गोस्वामी को 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताते चलें कि अभी कुछ माह पहले अर्जुन प्रसाद गोस्वामी पर जिला बंदर की कार्यवाही की गई थी। शनिवार को पिता के स्वास्थ्य खराब होने की सूचना पर जिला प्रशासन ने उनको 15 दिन का समय दिया है। शनिवार की देर रात उनके पिता ने अपने वीरपुर आवास पर अंतिम सांस ली। अर्जुन गोस्वामी ने बताया कि वह अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं। कुछ लोगों ने सत्ता का दुरूपयोग कर जिलाबंदर की कार्यवाही कराई। तभी से वे सदमे में थे। उसी के विरोध से उनके पिता की मौत हुई है। उनका अंतिम संस्कार दोपहर में गांव के पास खेत में कर दिया गया। सपा से कैसरगंज लोकसभा प्रत्याशी भगत राम मिश्र, पूर्व विधायक बेजनाथ दुबे, अवस राम गोस्वामी, सांसद प्रतिनिधि सुनील सिंह, विश्राम बाबा, हरिशंकर पांडेय सहित हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

## ढाबली में की चोरी, झोपड़ी में लगा दी आग

इटियाथोक, गोंडा, अमृत विचार : ज्ञानपुर के खरिहा चौराहे पर शनिवार की रात अज्ञात लोगों ने फूस से बनी झोपड़ी में आग लगा दी और साथ में पान की ढाबली का ताला तोड़कर उसमें सारा सामान व नगदी कर उठा ले गए। अजीब व अमजद अली ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने बताया कि खरिहा चौराहे पर पान की ढाबली करते हैं। उसी के सामने झोपड़ी भी है। रात करीब 12:00 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोगों ने ढाबली का ताला तोड़कर उसमें सारा सामान व नगदी उठा ले गए और झोपड़ी में आग लगा दी। पीड़ित ने बताया कि रात को डायल 112 को फोन किया गया था डायल 112 मौके पर पहुंची और जानकारी लेकर वापस चली गई। सुबह कोतवाली में शिकायत की पर पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की।

## विद्युत पोल से टकराकर पलटा ट्रक

मनकापुर, गोंडा, अमृत विचार :

शनिवार रात करीब तीन बजे मनकापुर-रेहरा मार्ग पर तहसील मोड़ के पास बालू लादकर इट्टीहाह पुल के करीब गिराने जा रहा एक ट्रक ओवरलॉड होने के कारण अनियंत्रित हो गया और 11 हजार वॉल्ट की विद्युत लाइन के पोल से टकराकर पलट गया। हादसे में विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। घटना के बाद इलाके में अंधेरा छा गया। मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के अवर अभिभावक शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि क्षतिग्रस्त पोल व लाइन को मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है और विद्युत व्यवस्था जल्द बहाल कर दी जाएगी। एहतियात के तौर पर आपूर्ति बंद करी गई है।



पलटा ट्रक व टूटा पोल। ● अमृत विचार

## छूटे लाभार्थियों के बनाए जा रहे होल्डन कार्ड

बलरामपुर, अमृत विचार : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के होल्डन कार्ड बनाए जाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च वहा किया जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने जनपद के सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि होल्डन कार्ड आयुष्मान होल्डन कार्ड अभी तक नहीं बना है, वे शीघ्र कार्ड बनाकर योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि होल्डन कार्ड के जरिए लाभार्थी सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। सीएमओ ने बताया कि होल्डन कार्ड बनाने के लिए पात्र लाभार्थी आशा कर्माकर्ता, एनएम, सीएएओ, पंचायत सहायक अथवा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे।

## न्यूज़ ब्रीफ

## कुत्ते ने बुजुर्ग पर किया हमला, भर्ती

बहराइच। जिले के रानीपुर इलाके में मंदिर से पूजा कर वापस लौट रहे एक वृद्ध पर अचानक आकारा कुत्ते ने हमला कर दिया। जब तक लोग उन्हें बचाते कुत्ते ने उनके हाथ की एक उंगली चबा डाली, लोगों में डंडा मारकर कुत्ते को भागाया। रानीपुर थाना क्षेत्र में स्थित भानपुर ग्राम के रहने वाले वृद्ध छोटन उम्र 76 वर्ष रविवार को घर से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे, जब वो वापस लौट रहे थे। तभी अचानक एक कुत्ते ने उनपर हमला कर दिया। चौख सुकर ग्रामीण डंडे लेकर दौड़े लेकिन तब तक उसने बुजुर्ग को एक उंगली बुरी तरह चबा डाली। घायल बुजुर्ग को परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पर चिकित्सकों की ओर से उनका इलाज किया जा रहा है।

## संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत

श्रावस्ती: भिन्गा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम आगापुर के मजरा भागसिंह पुरवा में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव उसी के कमरे में फांसी के फंदे से लटक मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच करना की जागी है। भांगा सिंह पुरवा निवासी अनीता देवी पुत्री तिलकराम दोपहर में परिवार के साथ भोजन करने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। काफी देर बाद भी जब वह बाहर नहीं आई तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनो ने कमरे में जाकर देखा तो अनीता का शव फंदे से लटक रहा था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची भिन्गा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिन्गा भेज दिया है।

## झोपड़ी में लगाई आग गृहस्थी जलकर राख

कैसरगंज (बहराइच): कैसरगंज थानान्तर्गत ग्राम पंचायत गोडहिया न.एक के सेंटर चौराहा पर बीती रात अज्ञात शरारती तत्वों ने एक निर्धन व्यक्ति रामखन की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। आग से झोपड़ी में रखी सामान जलकर राख हो गया। गोडहिया पुलिस चौकी प्रभारी संजीत कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना की जांच का रचा रही है। अभी तहरीर नहीं मिली है।

## युवती के अपहरण का आरोप, मुकदमा दर्ज

जरवलरोड (बहराइच): थाना जरवल रोड क्षेत्र से एक 18 वर्षीय युवती के अपहरण का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित पिता निवासी तर्पेसिंह, थाना जरवल रोड ने थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री को शादी के बहाने बहला-फुसलाकर घर से बाहर बुलाया गया, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। पीड़ित के अनुसार, 24 जनवरी की रात करीब 9 बजे ग्राम निवासी रामचंद्र की पुत्री ने उनकी बेटी को घर के बाहर बुलाया था। इसके बाद से युवती लापता है। खोजबीन के दौरान परिजनो को जानकारी मिली कि युवती को प्रमोद पुत्र रामसुधन, निवासी ग्राम सुरतांज, थाना मोहम्मदपुर खाला, जनपद बाराबंकी के पास पहुंचा दिया गया है, जो उससे शादी करना चाहता है। आरोप है कि जब परिजनो ने इसका विरोध किया तो दयाशंकर और रामकेवल सहित अन्य लोगों ने युवती व उसके परिवार को बंदनाम करने की धमकी दी। साथ ही गांव के प्रधान के माध्यम से परिवार पर पुलिस में शिकायत न करने का दबाव भी बनाया गया। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को शादी कराने के उद्देश्य से किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया है। जरवल रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

## आयोजन

## सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से छात्राओं की होगी मानसिक व शारीरिक तैयारी

संवाददाता, जमुनहा/कानीबोडी (श्रावस्ती)

**अमृत विचार।** बाल रक्षा भारत संस्था की ओर से संचालित सखी इनिशिएटिव टू सिक्योर हर फ्यूचर कार्यक्रम के तहत छात्राओं को किया जा रहा है। इसके तहत विद्यालयों में छात्राओं को जागरूक करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के तहत राजकीय हाईस्कूल खुरहरी, राजकीय हाईस्कूल दिकौली, राजकीय हाईस्कूल ददौरी, राजकीय हाईस्कूल इमलिया करनपुर में

## धर्म केवल सनातन, बाकी सब पंथ: विष्णुदेवाचार्य

## रुपईडीहा में आयोजित हिंदू सम्मेलन में बोले मुख्य वक्ता-संगठित होने से भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र

संवाददाता, रुपईडीहा (बहराइच)

**अमृत विचार।** भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र आदर्श नगर पंचायत रुपईडीहा के दशहरा बाग में विशाल हिन्दू सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रमुख वक्ता स्वामी विष्णुदेवाचार्य ने कहा कि बहराइच महाराजा सुहेलदेव की धरती है। आक्रांता की मजार पर हिन्दू भी माथा टेकने जाता है। उन्होंने कहा कि सनातन ही केवल धर्म है। बाकी सब पंथ व मजहब हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जीवन पद्धति है। भारत में हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। कार्यक्रम को जमुनहा गुरुद्वारे के पंथी गुरुमीत सिंह ने भी अपने संबोधन में कहा कि हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए ही सिख धर्म की स्थापना हुई थी। औरंगजेब ने हमारे बच्चों को धर्म परिवर्तन न करने पर जिंदा दीवाल में चुनवा दिया। धर्म न बदलने पर हमारे गुरु ने शीश कटा दिया। आज भी दिल्ली में



रुपईडीहा में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मौजूद लोग।

अमृत विचार

शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है।

नेपाल विश्व हिन्दू की कृष्णा पांडेय ने कहा कि नेपाल भी पहले हिन्दू राष्ट्र ही था। इसे सत्तालोलुपों ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया। अब सड़क पर निकल कर नेपाल के लोग हिन्दू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का संचालन किया गया। सम्मेलन को आचार्य दयाशंकर शुक्ल व आरएसएस के सर्वेश ने भी लोगों को एक होने का संदेश

दिया। मुख्य वक्ता वरिष्ठ प्रचारक अमर नाथ ने भी हिन्दू एकता पर बल दिया। समारोह का संचालन प्रधानाचार्य अनुज सिंह ने किया। सम्मेलन हेतु वक्ताओं ने सीमा जागरण मंच के संयोजक राजेश सिंह धर्म जागरण मंच के संघ प्रचारक सर्वेश व चेरमैन डॉ उमाशंकर वैश्य की भूरि भूरि प्रशंसा की।

उन्होंने यह भी कहा कि इस सम्मेलन की रुपईडीहा में आवश्यकता महसूस की जा रही

## सर्व स्पर्शी और सर्व समावेशी है बजट: मिश्रीलाल

संवाददाता, श्रावस्ती

**अमृत विचार।** मोदी सरकार की ओर से रविवार को संसद में आम बजट प्रस्तुत किया गया। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत बजट का भाजपाइयों ने जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी मंडलों में जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ता सहित आमजन के साथ लाइव प्रसारण सुना।

संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026-27 का आम बजट प्रस्तुत किया। इसका लाइव प्रसारण जिला सहित सभी मंडलों में सुना गया। भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष मिश्रीलाल वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पुनः देश को एक सर्व स्पर्शी और समावेशी बजट दिया है। युवाओं, छात्रों, किसानों, महिलाओं, छोटे बड़े व्यापारियों सहित स्वास्थ्य, कृषि, टैक्स आदि के लिए एक संपूर्ण समर्पित बजट है। यह बजट विकसित भारत 2047 एवं जन कल्याण की मजबूत आधारशिला साबित होगा। पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर दयाल पांडेय ने कहा कि बजट में आयुष सेक्टर को मजबूती देते हुए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित

## ● बजट का भाजपाइयों ने जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी मंडलों में देखा प्रसारण

किए जाएंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष संजय कैराली पटेल ने कहा कि कोविड के बाद आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता और पहचान मिली है और आयुर्वेद उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बजट 2026-27 में कई कदम उठाए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष व पूर्व सांसद दहन मिश्रा ने कहा कि यह विकासोन्मुखी बजट किसान, युवा, महिला, श्रमिक, मध्यम वर्ग सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण उत्थान को सुनिश्चित करता है। साथ ही यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, आधुनिकीकरण को गति देते, आधारभूत संरचना के विस्तार तथा सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करता है। श्रावस्ती विधायक राम फेरन पांडेय ने कहा कि बजट खेल क्षेत्र, रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अनेक अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से शुरू की गई खेल प्रतिभाओं के व्यवस्थित पोषण को आगे बढ़ाते हुए, खेल क्षेत्र को रूपांतरित करने के लिए एक खेलो

## जिलाधिकारी ने ग्राम सेमरहना में विस्थापन का लिया जायजा

बहराइच

**अमृत विचार।** तहसील मिर्हीपुरवा (मोतीपुर) अन्तर्गत राजस्व ग्राम भरथापुर के हितग्राहियों को ग्राम सभा सेमरहना में विस्थापित किये जाने की कार्यवाही का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद, उप जिलाधिकारी मोतीपुर मिर्हीपुरवा (मोतीपुर) राम दयाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रद्युम्न सिंह, अधि.अभि. लो.नि.वि. निर्माण खाउड-1 अमर सिंह, तहसीलदार धर्मेन्द्र कुमार, अधि. अधि. नगर पंचायत जंग बहादुर, खाउड



अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी।

विकास अधिकारी मिर्हीपुरवा व अन्य अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी राम दयाल से भूमि पैमाइश के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। डीएम ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए कृषि आवंटन हेतु भी भूमि का चिह्नकन कर लिया जाए।



भिन्गा में कार्यकर्ताओं के साथ बजट का लाइव प्रसारण देखते जिला पंचायत अध्यक्ष।

## विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा यह सर्वसमावेशी बजट: समय प्रसाद

पयागपुर (बहराइच)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 'केंद्रीय बजट 2026' को लेकर पयागपुर विकास खंड मुख्यालय के सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रमुख प्रतिनिधि समय प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बजट भाषण को लाइव सुना और इसे देश के सर्वांगीण विकास का रोडमैप बताया बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रमुख प्रतिनिधि समय प्रसाद मिश्र ने कहा कि यह बजट मात्र एक वित्तीय विवरण नहीं, बल्कि 'विकसित भारत' के संकल्प को सिद्ध करने वाला दस्तावेज है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बजट में किसान, युवा, महिला, श्रमिक और मध्यम वर्ग सहित समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान को सुनिश्चित किया गया है। विधायक सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि इस बजट में हर तबके का ध्यान रखा गया है इस बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने का प्रावधान होगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष भाजपा उमाशंकर तिवारी, मंडल अध्यक्ष प्रमोद पांडेय, वरिष्ठ कार्यकर्ता हरिओम रस्तोगी, आनन्द बिहारी (गुरु जी) और मुकेश शर्मा सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों, स्वास्थ्य संबंधी

समस्या से जूझ रहे देशवासियों, अप्रवासी भारतीयों के निवेश के नए रास्ते खोले जा रहे हैं।

## पत्रकार संघ ने 5 रनों से जीता मुकाबला

रुपईडीहा (बहराइच)

**अमृत विचार।** सीमावर्ती आदर्श नगर पंचायत रुपईडीहा कस्बा रुपईडीहा स्थित श्री रामजानकी इंटर कॉलेज के खेल मैदान में सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों (एसएसबी, पुलिस एवं वन विभाग) की संयुक्त टीम और रुपईडीहा पत्रकार संघ के बीच एक मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस रोमांचक प्रतियोगिता का आयोजन नगर पंचायत रुपईडीहा द्वारा किया गया, जिसमें 12-12 ओवरों का मैच खेला गया। मैच से पूर्व नगर पंचायत चेरमैन प्रतिनिधि डॉ. अश्विनी वैश्य द्वारा रुपईडीहा पत्रकार संघ के कप्तान एम. अरशद और सुरक्षा एजेंसियों की टीम के कप्तान वन क्षेत्राधिकारी रूपईडीहा



मैच के बाद सुरक्षा एजेंसियों के जवान व पत्रकारों के लोग। अमृत विचार

अतुल श्रीवास्त्व के बीच टॉस कराया गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रुपईडीहा पत्रकार संघ की टीम सिद्धनाथ गुप्ता, के सुपुत्र शुभम गुप्ता के शानदार 40 रन और संजय वर्मा, के सुपुत्र सूर्यशं के 24 रनों की मदद से निर्धारित 12 ओवरों में 98 रन बनाए और विपक्षी टीम को 99 रनों का लक्ष्य दिया

## चार नेपाली किशोरियां मुक्त, दो तस्कर गिरफ्तार

सिरसिया (श्रावस्ती)। मानव तस्करों के विरुद्ध 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की ओर से शनिवार रात बड़ी कार्रवाई की गई इस दौरान जवानों ने चार नाबालिग नेपाली लड़कियां मुक्त कराने के साथ दो मानव तस्कर गिरफ्तार किया।

एसएसबी के कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण के दिशा-निर्देशन में शनिवार को एसएसबी 62वीं वाहिनी सीमा चौकी गुज्जरगौरी की ओर से मानव तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसमें आसूचना शाखा से मिली सूचना के आधार टीम ने दो भारतीय को भचकाही गांव के पास बाइक सहित गिरफ्तार किया। उनके पास से टीम ने चार नाबालिग लड़कियों को बरामद किया। दोनों युवक नेपाली किशोरियों को नेपाल से भारत की ओर मानव तस्करों/देह व्यापार के उद्देश्य से ले जा रहे हैं। मुक्त कराई गई सभी नेपाली लड़कियों एवं पकड़े गए व्यक्तियों सिरसिया पुलिस के सुपुर्द कर दिया है।

## बस व बाइक की आमने-सामने टक्कर से पिता-पुत्र गंभीर, रेफर

जरवल रोड (बहराइच)

**अमृत विचार।** लखनऊ बहराइच मार्ग पर बसहिया पाते मोड़ के सामने रोडवेज बस के टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए सूचना पर जरवल पुलिस घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्तफाबाद पहुंचाया गया जब चालक छोड़कर फरार हो गया। दोनों घायलों को डॉम्रा सेंटर बहराइच रेफर किया गया है।

जरवल रोड थाना अंतर्गत लखनऊ-बहराइच मार्ग बसहिया पाते मोड़ पर रोडवेज बस जो सवारी करकर लखनऊ से बहराइच की तरफ जा रही थी और मोटरसाइकिल बुलेट सवार अपने घर से सी एससी मुस्तफाबाद इलाज के लिए जा रहे थे। तभी ग्राम बसैया पाते मोड़ के पास आमने-सामने टक्कर हो गई मोटरसाइकिल चालक पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए।

वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उसैद अहमद पुत्र जामिन अली उम्र करीब 25 वर्ष तथा जामिन अली पुत्र हिदायत अली उम्र करीब 55 वर्ष निवासी बसहिया जगत थाना जरवल

हादसा

● लखनऊ-बहराइच मार्ग पर हुआ हादसा, चालक फरार



हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस व बाइक।

रोड जनपद बहराइच गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनको प्राथमिक उपचार लिए जरिए एम्बुलेंस सीएससी मुस्तफाबाद भेजा गया तथा रोडवेज बस का चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं रोडवेज बस व मोटर साइकिल को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। घायलों को डॉम्रा सेंटर बहराइच रेफर किया गया है।

## स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 6 से

संवाददाता, बहराइच, अमृत विचार। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 6.0 का शुभारंभ बहराइच जनपद में 6 फरवरी से होगा। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से जनपद के 38 सीमावर्ती गांव में 6 एवं 7 फरवरी को चिकित्सा शिविर लगाकर



प्रेसवार्ता के दौरान मौजूद डॉ. सारिका व अन्य।

मरीज का परीक्षण किया जाएगा तथा 8 फरवरी को किसान डिग्री कॉलेज परिसर में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की जिला अध्यक्ष डॉ. सारिका साहू ने दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के फ्रेण्डलीप्यु आरएमएल एसजीपीजीआई महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले प्रहरी हो या वहां निवास करने वाले वनवासी बंधु उनका स्वास्थ्य ही राष्ट्र की शक्ति है। इसी संकल्प के साथ नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन और श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास विगत 5 वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा की अलख जगह रहे हैं। प्रेस वार्ता में गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के मेजर डॉ एसपी सिंह, डॉ विकास मिश्रा, डॉ बृजेश शुक्ला, डॉ दिव्येश बरनवाल, डॉ मनीष शुक्ला, डॉ रामेंद्र त्रिपाठी, डॉ अमिताभ मिश्रा डॉ दिवाकर दत्त त्रिपाठी, डॉ उपेंद्र वर्मा, डॉ रामकुमार विभागा प्रचार प्रमुख अतुल गौड़, जिला प्रचार प्रमुख विपिन आदि उपस्थित रहे।

**पयागपुर की बेटी दीपिका गुप्ता ने रचा इतिहास** पयागपुर बहराइच। कहते हैं कि अगर इरादे बुलंद हों और मेहनत में ईमानदारी हो, तो सफलता कदम चूमती है। इसे सच कर दिखाया है पयागपुर के भूमणज बाजार की निवासी दीपिका गुप्ता ने। दीपिका ने भारतीय जीवन बीमा निगम के फैजाबाद मंडल में इस वित्तीय वर्ष का प्रथम दोहरा शतक (200 पॉलिसी) लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दीपिका गुप्ता, जो श्याम सुंदर गुप्ता की सुपुत्री हैं, ने यह उपलब्धि फैजाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोंडा, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, रायबरेली, अमेठी, अकबरपुर और रुदौली जैसे जनपदों के लगभग 30,000 अभिकर्ताओं के बीच प्राप्त की है। इस वित्तीय वर्ष में 200 पॉलिसी पूर्ण करने वाली वह मंडल की पहली अभिकर्ता बनी हैं। उनकी इस ऐतिहासिक सफलता के लिए क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या में उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। दीपिका की इस उपलब्धि से पूरे पयागपुर क्षेत्र में खुशी की लहर है और लोग उन्हें 'नारी शक्ति' की जीती-जागती मिसाल मान रहे हैं। दीपिका के मार्गदर्शक और सीएलआईए राजेश मिश्रा ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि दीपिका शुरू से ही एक अत्यंत मेहनती और समर्पित अभिकर्ता रही हैं। 11 पॉलिसी से शुरू होकर 200 पॉलिसी तक का यह सफर उनकी दिन-रात की मेहनत और लगन का परिणाम है। वह अन्य युवाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

**लापता युवक का फंदे से लटका मिला शव** इकौना (श्रावस्ती), अमृत विचार। सीताद्वार गांव से 18 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवती का शव शनिवार देर शाम जामुन के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची इकौना पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिन्गा भेज दिया है। इकौना थाना क्षेत्र प्रमोद टंडवा महंत के माजरा सीताद्वार निवासी सांवली प्रसाद उर्फ ननकऊ (11) पुत्र रतीराम 13 जनवरी से लापता था। शनिवार देर शाम गांव से करीब दो किलोमीटर दूर एक जामुन के पेड़ में उसका शव रस्सी के फंदे से लटका मिला। सूचना पर सीओ इकौना भ्रम परासवान के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष परमानंद तिवारी व फॉरेंसिक टीम ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया। बाद में पुलिस ने शव का पंचनामा भराकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिन्गा भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थानाध्यक्ष का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं युवक की मौत के बाद परिजनो में कोहराम मच गया है।

**वैकल्पिक व्यवस्था के बिना नहीं बंद होगा संजय सेतु** संवाददाता, जरवलरोड (बहराइच) **अमृत विचार।** घाघरा नदी पर बने संजय सेतु को लेकर चल रही बंदी के अटकलों के बीच प्रशासनिक सूत्रों ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। नाम न छपने की शर्त पर प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि जब तक वैकल्पिक मार्ग, ट्रैफिक डायवर्जन और आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी तरह लागू नहीं हो जातीं, तब तक संजय सेतु पर आवागमन बंद नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पुल की जरूरत नहीं हो जाती, तब तक संजय सेतु पर आवागमन पूर्ववत् जारी रहेगा और वैकल्पिक व्यवस्था के चयन के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। जिससे कि लोगों को दिक्कत न हो।

## विद्यालयों में छात्राओं को जागरूक करते हुए दिया गया प्रशिक्षण



आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेतीं राजकीय हाईस्कूल की छात्राएं।

अमृत विचार

छात्राओं को प्रशिक्षण दिलाया गया। इस दौरान छात्राओं को बताया गया कि अगर उनको कोई समस्या हो तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बचाव के लिए कौन सी तकनीक अपनाए। ट्रेनर ने बताया कि आत्मरक्षा की ट्रेनिंग के जरिये छात्राएं मानसिक रूप से भी सशक्त होती हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई तकनीक जैसे कोई गर्दन पर वार करे तो कैसे हथ स्वयं को बचाएं, यदि सामने से वार आए तो कैसे अपने चेहरा का रविवार को समापन हुआ। इस दौरान आयोजित समारोह में कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण ने उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया।



एसएसबी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी व प्रशिक्षणार्थी।

सशस्त्र सीमा बल 62वीं वाहिनी भिन्गा में कस्टम विभाग के हवलदारों के लिए आयोजित एक सप्ताह के बाह्य/शारीरिक एवं शस्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का रविवार को समापन हुआ। इस दौरान आयोजित समारोह में कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण ने उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया।

संचालन एवं उपयोग, शस्त्र अभ्यास, सुरक्षा, सतर्कता एवं अनुशासन से संबंधित विषयों पर सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। समापन पर कमांडेंट ने कहा कि इस प्रकार के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों से विभिन्न विभागों के कार्मिकों की कार्यकुशलता, समन्वय एवं पेशेवर दक्षता में वृद्धि होती है। उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण को अपने कार्य व्यवहार में अपनाने एवं कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी, सतर्कता एवं आत्मविश्वास के साथ करने हेतु प्रेरित किया। इस मौके पर एसएसबी के अधिकारी, प्रशिक्षक व अन्य मौजूद रहे।



